कामयाबी के साथ संपन्न पार्टी की 9वीं कांग्रेस जिन्दाबाद!

प्रभात

"पीजीए को मजबूत करो ! सरकारी दमन को परास्त करो !!"

9वीं कांग्रेस का नारा

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष-14 : अंक-3 ☆ **पार्टी की 9वीं कांग्रेस का विशेषांक** ☆ फरवरी - जून 2001 मूल्य-10 रुपए

जनसेना को मजबूत करो!

देश भर में जनयुद्ध को फैला दो!! सामरिक इलाकों में आधार क्षेत्र कायम करो!!!

- देशवासियों से भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] की 9वीं कांग्रेस का आह्वान

4 मार्च 2001 का दिन भारतीय जनता के लिए ऐतिहासिक दिन था। इस दिन भाकपा (मा-ले) (पीपुल्स वार) पार्टी की 9वीं कांग्रेस (महाधिवेशन) शुरू हुई थी। यह कांग्रेस 8वीं कांग्रेस के 31 वर्ष बाद होने जा रही थी। इस दौरान पार्टी कई उतार-चढ़ावों से गुजरती हुई तथा ज्यादा शक्तिशाली बनती हुई आगे बढ़ी है और 10 राज्यों में विस्तार कर चुकी है। विशेष तौर पर भाकपा (मा-ले) (पीपुल्स वार) और भाकपा (मा-ले) (पार्टी यूनिटी) के विलय के बाद इस कांग्रेस का महत्व और भी बढ़ गया।

इसमें कोई शक नहीं है कि `नक्सलबाड़ी' के वज्रनाद ने भारत में हथियारबंद संघर्ष को एजेन्डे पर लाया था। और उत्पीड़ित जनता को क्रांतिकारी आन्दोलन में गोलबंद करते हुए उस कार्यदिशा को चारों तरफ फैलाने वाली हमारी पार्टी, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने मई 1970 में अपनी 8वीं कांग्रेस को सफलतापूर्वक आयोजित कर कई ऐतिहासिक फैसले किए थे। भाकपा और माकपा के संशोधनवाद से नाता तोड़कर क्रांतिकारी विरासत को जारी रखते हुए क्रांति का संचालन कर चुके हमारे तमाम प्यारे नेताओं ने उस कांग्रेस में भाग लेकर पार्टी के कार्यक्रम, संविधान और क्रांति का मार्ग पेश किया था जिनका कांग्रेस ने बहसों के बाद अनुमोदन किया। तबसे इतिहास 30 साल से ज्यादा आगे बढ़ा। कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजरा। कई अनमोल अनुभव पीछे छोड़ता गया। तमाम रुकावटों को पार करता ही बढ़ा। हमारी पार्टी ऐसे कई नेताओं का पिंड छुड़ाकर, जिन्होंने खुद को क्रांति के रास्ते से अलग किया, गैर-सर्वहारा भटकावों का मुकाबला कर शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाते हुए सर्वहारा की अग्रणी पार्टी के तौर पर उभरी। क्रांतिकारी प्रेरणा से, संघर्ष के दृढ़ संकल्प के साथ, जनदिशा पर चलते हुए हमने हमारी पार्टी, भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] को असली सर्वहारा पार्टी के रूप में उभारा। इस सिलसिले में हमने 1998 से 9वीं कांग्रेस की तैयारियां शुरू करके मार्च 2001 में उसका सफल आयोजन किया।

देश भर में हजारों पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 प्रतिनिधि और साथ ही, तुर्की और नेपाल की क्रांतिकारी पार्टियों से 2 भाईचारा प्रतिनिधि **कॉ.श्याम-कॉ.महेश-कॉ.मुरली कॅम्यून** में इकट्ठा हुए जो किसी स्थान पर गहरे जंगल में स्थित था। भयंकर राजकीय हिंसा और दमन के बीच से गुजरते हुए शत्रु के सघन कोम्बिंग (खोजबीन) अभियानों के बीच कांग्रेस 18 दिन तक चली और 22 मार्च को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

दण्डकारण्य स्पेशल जोन का तीसरा पार्टी अधिवेशन कामयाबी के साथ संपन्न !

➤ *देखिए पृष्ठ 11...*

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले की सात कांग्रेसें तभी हुई थीं जब भाकपा और माकपा मिलकर थीं। चूंकि इतिहास ने यह स्पष्ट किया था कि जन आन्दोलनों की उभार के 3-4 मौकों को छोड़कर, राजसत्ता छीन लेने के लिए पार्टी को और जनता को तैयार करने का इरादा कभी नहीं रखने वाले नेतृत्व के तहत असली कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कभी नहीं हो सकता, इसलिए 22 अप्रैल 1969 को हमारी पार्टी का पुनर्निर्माण किया गया। तबसे लेकर इतिहास का सफर पूरा दीर्घकालिक जनयुद्ध को ही केन्द्र में रखकर जारी था और हमने क्रांतिकारी पार्टी का विकास किया।

संशोधनवाद के खिलाफ गुस्से से क्रांति की पटरियों पर आ चुकी हमारी पार्टी की कार्यनीति में 1970 के दशक तक ही पनप चुके वामपंथी दुस्साहसिकवाद के चलते हमें अस्थायी पराजय झेलनी पड़ी थी। फिर से 1974 तक अतीत की समीक्षा कर पार्टी को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली जनाधार का निर्माण करते हुए हथियारबंद संघर्ष को जारी रखने के प्रयास तेज किए गए। लेकिन देश भर में पार्टी में फूट पड़कर किसी भी एक केन्द्र की गैर-मौजूदगी की स्थिति में हमने जहां का वहीं पार्टी-केन्द्र कायम करने तथा आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास तेज किए। हमारे इन प्रयासों के केन्द्र आन्ध्रप्रदेश और बंगाल थे। इसके तहत 1980 के दशक तक आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को मिलाकर एक केन्द्र का निर्माण किया गया। इसके नेतृत्व में कर्नाटक में नए सिरे से पार्टी इकाई कायम की गई और तेलंगाना व धर्मपुरी (तमिलनाडु) में सामंतवाद विरोधी संघर्ष तेज किया गया।

तेलंगाना आन्दोलन न सिर्फ अपने बल बूते पर खड़ा हुआ, उसका विस्तार दण्डकारण्य में भी हुआ। मुक्त इलाका कायम करने के लक्ष्य से दण्डकारण्य आन्दोलन मजबूती से उभरा। तेलंगाना के उत्तरी भाग में तेज हुए छापामार युद्ध ने न सिर्फ दक्षिणी तेलंगाना तक विस्तार किया, बल्कि प्रदेश के बाकी सभी इलाकों को प्रभावित किया जिससे जनता का आन्दोलन में गोलबंद होना संभव हो सका। पिछले 26 सालों से तेज होते और ठोस केन्द्रीकरण से बढ़ रहे शत्रु-दमन का मुकाबला करके खड़े होने वाली पार्टी ने लगातार उन्नत कार्यभारों की पूर्ति के लिए खुद को तैयार करते हुए जनता को तैयार किया।

उधर, बंगाल में नुकसान होने के बावजूद पड़ोस के बिहार में सामंतवाद विरोधी संघर्ष को तेज करते हुए छापामार युद्ध को जारी रखा गया। और `90 के दशक के आखिर से छापामार इलाकों के निर्माण के प्रयास सक्रिय रूप से जारी हैं। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में देहाती इलाकों में आन्दोलन के निर्माण के प्रयास जारी हैं, फिर भी आन्दोलन को मजबूत करने में हम अभी भी पीछे ही हैं।

9वीं कांग्रेस की तैयारियां

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, क्रांतिकारियों की एकता इस पूरे काल में एक मुख्य समस्या बनकर ही हमारे सामने रही है। आन्दोलन का एक ठोस इलाके में निर्माण करने के बाद ही उसका दूसरे इलाकों को प्रभावित करना शुरू हुआ। इस सिलसिले में आन्दोलन के चोट खाने के बाद देश भर में फूट पड़ने से बनी पार्टियों और ग्रुपों से नई ताकतें उभरकर आईं। इन्हीं ताकतों ने अपनी-अपनी पार्टियों और ग्रुपों के अवसरवादी और दक्षिणपंथी नेताओं का तथा पार्टियों का गलत राजनीति का मुकाबला करना शुरू किया। इस दौरान आन्ध्र को केन्द्र बनाकर खड़े होकर उभरी पुरानी भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] ने एक क्रांतिकारी राजनीतिक शक्ति के रूप में देश को प्रभावित किया। दूसरी ओर पुरानी भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। इस काल में एमसीसी भी एक ताकत बनकर उभरी है। ये तीनों पार्टियां भारत के क्रांति के मानचित्र पर पिछले ढाई दशकों से ज्यादा समय से हथियारबंद संघर्ष जारी रखने वाली पार्टियों के रूप में अंकित हुई हैं। इन तीनों के बीच अलग-अलग एकता वार्ताएं चली हैं। 1998 में पुरानी पीपुल्स वार और पार्टी यूनिटी का विलय नई पीपुल्स वार में हुआ और अस्थाई केन्द्रीय कमेटी की स्थापना कर 9वीं कांग्रेस की तैयारियां शुरू कर दी गईं। इन दोनों पार्टियों में मौजूद ताकतें 8वीं कांग्रेस के समय तक तत्कालीन भाकपा (मा-ले) में रही थीं जो क्रांतिकारी आन्दोलन को दोबारा खड़ा करने के सिलसिले में अस्तित्व में आने वाली दो अलग-अलग पार्टियों में शामिल हुई थीं। आज उन्हीं ताकतों ने एक ही कार्यदिशा, समान व्यवहार और अपेक्षाकृत मजबूत व देशव्यापी एकीकृत पार्टी के रूप में जनता के सामने खड़े होकर 1998 के आखिर से 9वीं कांग्रेस की सक्रिय तैयारियां शुरू कीं।

8वीं कांग्रेस से 9वीं कांग्रेस के बीच हमारी पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में कई बार राज्य अधिवेशन आयोजित किए। उससे निचले स्तर के अधिवेशन भी अनेक हुए हैं। अखिल भारतीय अधिवेशन भी आयोजित किए गए। इस दौर का इतिहास पूरा 8वीं कांग्रेस की विरासत को जारी रखते हुए आन्दोलन को बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश में भारत में पिछले दो दशकों से लगातार शत्रु-दमन का सामना करते हुए छापामार दस्तों के जन छापामार सेना में तब्दील हो जाने का इतिहास ही है। इन सामंतवाद विरोधी संघर्षों को आगे ले जाकर, छापामार इलाकों में जनता की राजसत्ता के अंगों का गठन करके राजसत्ता छीन लेने के लक्ष्य के साथ बाकी तमाम कार्यभारों का तालमेल बिठाया गया। सामरिक महत्व वाले इलाकों में मुक्त इलाकों की स्थापना को फौरी कार्यभार बनाकर इसके लिए हमारे प्रयास तेज करते हुए, देश भर में जनयुद्ध फैलाने और जनसेना के निर्माण को साधारण लक्ष्य बनाकर कदम-दर-कदम बढ़ाया गया। आइए, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संपन्न हमारी 9वीं कांग्रेस की कामयाब दास्तान पर नजर डालें, जिसने कई नए कार्यभार और समृद्ध भावनाएं हमारे सामने पेश कीं।

कांग्रेस के प्रतिनिधि जो जिला और राज्य अधिवेशनों को सफलतापूर्वक संपन्न कर चले आए

अगस्त 1998 में दोनों पार्टियों का विलय हुआ। बुनियादी दस्तावेजों पर एकमत हासिल किया गया। एक अस्थायी केन्द्रीय कमेटी गठित की गई ताकि पार्टी में समान कार्याचरण स्थापित किया जा सके। 1999 के बीच तक कार्यक्रम-संविधान, रणनीति और कार्यनीति, राजनीतिक प्रस्ताव, वित्तीय नीति दस्तावेजों के मसौदे तैयार किए गए। इन्हें 8 भाषाओं में प्रकाशित करवा कर प्रत्येक पार्टी सदस्य तक पहुंचाया गया। प्राथमिक इकाई सैल से लेकर उच्चतर स्तर तक इन मसौदा दस्तावेजों पर विचार-विमर्श किया गया और विभिन्न राजनीतिक कक्षाएं लेकर पार्टी सदस्यों की समझ को इन दस्तावेजों के विषय में समृद्ध बनाया गया ताकि वे इन दस्तावेजों को और भी समीक्षात्मक ढंग से देख सकें। पार्टी की राजनीतिक - सांगठनिक समीक्षा अगस्त 2000 तक तैयार हुई और इसे राज्य अधिवेशनों को भेज दिया गया।

इसके बाद देश भर में निचले स्तरों में अधिवेशनों का सिलसिला शुरू हुआ। विभिन्न जगहों पर कई एरिया अधिवेशन, इसके बाद 24 जिला/डिवीजनल अधिवेशन, 3 रीजनल अधिवेशन, 10 राज्य स्तर के अधिवेशन किए गए। इन अधिवेशनों में दस्तावेजों पर विस्तृत चर्चाएं की गईं और सैकड़ों की संख्या में संशोधन व सुझाव केन्द्रीय कमेटी को भेजे गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य व स्पेशल जोनल कमेटी ने अपनी-अपनी राजनीतिक - सांगठनिक समीक्षा भी तैयार की।

अधिकांश अधिवेशन दुश्मन के दमन अभियानों के बीच ही, हमलों का मुकाबला करते हुए ही संपन्न हुए। पश्चिम करीमनगर में दुश्मन ने अधिवेशन हाल पर ही धावा बोलकर जबर्दस्त गोलीबारी की जिसमें हमारे 5 कॉमरेड शहीद हो गए। तेलंगाना के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में, दण्डकारण्य, बिहार, एओबी - हर तरफ दुश्मन के खोजबीन अभियानों के बीच ही, जनता की सतर्क निगरानी में, पीजीए बलों द्वारा दी गई सुरक्षा में एक-एक अधिवेशन संपन्न हुआ। अतीत का जायजा लेते हुए नए कार्यभार तय किए गए।

कॅम्यून

कांग्रेस की विधिवत शुरूआत से दो महीना पहले से ही कॅम्यून स्थल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई थीं। जनता के सहयोग से पीजीए कॉमरेडों ने लगभग 10 टन सामान कॅम्यून स्थल तक लाने का आसंभव नजर आने वाला काम सम्भव कर दिखाया। अन्तिम 10 दिनों में कॅम्यून स्थल का रूप ही बदल गया। बीहड़ जंगल को आधुनिक सुविधा सम्पन्न टाउनशिप में बदल दिया गया। कॉ. जौहर लाइब्रेरी, 1910 भुमकाल विद्रोह प्रैस, कॉ. भास्कर राव - कॉ. मल्लिकार्जुन - कॉ. निर्मल - कॉ. प्रसाद अस्पताल, कम्युनिटी किचेन, तारलागूडेम परेड ग्राउण्ड, खुला वीडियो थियेटर हाल, सब कुछ वहां था। एक ओर पीजीए कॉमरेड्स इन सब का निर्माण कर रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रतिनिधि राजनीतिक - सांगठनिक चर्चाओं में व्यस्त थे। नीचे से प्राप्त किए संशोधनों व सुझावों व चर्चा के मुद्दों के आधार पर केन्द्रीय कमेटी ने प्रतिनिधियों के अध्ययन के लिए दस्तावेजों पर कई संशोधन वितरित किए। प्रतिनिधियों ने इन संशोधनों पर विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्टों पर गहरा विचार-विमर्श किया।

पूरी कांग्रेस की प्रक्रिया के दौरान दीवारी पत्रिका `गुरिल्ला वाणि' के कई अंक निकाले गए जिसमें कई रिपोर्ट, व्यंग्य, कार्टून, लेख, कविताएं होती थीं। सायंकाल में विभिन्न राज्यों व जन नाट्य मंडली के सांस्कृतिक कर्मियों द्वारा गीत, नाटक व एकांकी अभिनय प्रस्तुत किए जाते थे। इसके अलावा पीजीए कॉमरेडों के लिए राजनीतिक स्कूल भी चल रहा था। रात को चार्ली चैप्लिन, विभिन्न देशों के आन्दोलनों, पार्टी डोक्युमेन्टरी व युद्ध पर फिल्में दिखाई जाती थीं। वॉलीबाल, बैडमिन्टन, शतरंज भी मनोरंजन की गतिविधियों के रूप में मौजूद थे।

कांग्रेस का उद्घाटन

4 मार्च 2001 को तारलागूडेम परेड ग्राउण्ड में कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। प्लटून कमाण्डर रविराज ने पार्टी सचिव कॉ. गणपति को पार्टी झण्डा फहराने के लिए आमंत्रित किया तब तमाम उपस्थित लोगों ने झण्डे को क्रांतिकारी अभिवादन किया। 3 फायर करके झण्डे को सलामी दी गई। और लाल झण्डे पर एक गीत गाया गया। इसके बाद कॉ. गणपति ने कांग्रेस के ऐतिहासिक महत्व पर भाषण दिया। इसके बाद केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. बस्वराज ने पीजीए का झण्डा फहराया और पीजीए की प्राथमिक, गौण व बुनियादी शक्तियों के बारे में बात रखी। इसके बाद केन्द्रीय कमेटी सचिवमण्डल सदस्य कॉ. एन.प्रसाद ने शहीद स्मारक का अनावरण किया और शहीदों की याद में सिर एवं बन्दूकें झुकाकर दो मिनट की खामोशी मनाई गई। 8वीं कांग्रेस से अब तक शत्रु की दमनकारी मशीनरी से लड़ते हुए शहादत देने वाले हजारों कॉमरेडों की याद में बनाए गए शहीदी स्मारक पर अंकित शब्द **'लोक नायक अमर होते हैं'** सबके दिलों में नया जज़्बा पैदा कर रहे थे। कॉ. एन.प्रसाद ने शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता पर बात रखी।

इसके बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. गौरव और तुर्की कम्युनिस्ट पार्टी/एम-एल के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. ओकान ने अपना भाईचारा भाषण दिया। फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी से हालांकि कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने अपना भाईचारा सन्देश कांग्रेस को भेजा। अन्त में मीटिंग एक रैली के रूप में कॉ. चारु मजुमदार हाल की तरफ चल पड़ी। पूरा क्षेत्र गगनभेदी नारों से गूंज उठा - **मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिन्दाबाद !, आधार इलाकों का निर्माण करो !, विश्व सर्वहारा क्रांति जिन्दाबाद !** क्रांतिकारी गीतों ने माहौल में क्रांतिकारी उत्साह भर दिया।

उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त होने पर पीजीए योद्धाओं द्वारा तैयार

"आज दक्षिण एशिया एक ज्वालामुखी की तरह है !"

- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

[भाकपा (मा-ले) (पीपुल्स वार) की 9वीं कांग्रेस के लिए भाईचारा संदेश के कुछ अंश]

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की ओर से मैं आपको क्रांतिकारी अभिनन्दन करता हूं। हमारी पार्टियां पड़ोसी देशों की मित्र पार्टियां हैं। दोनों देशों की जनता के गहरे सम्बन्ध रहे हैं। भारत में घटने वाली प्रत्येक घटना का नेपाल पर प्रभाव पड़ता है। चारु मजुमदार के नेतृत्व में शुरू हुए नक्सलबाड़ी संघर्ष का प्रभाव भी नेपाल में झापा संघर्ष के रूप में पड़ा था।

..... आपकी पार्टी नक्सलबाड़ी विद्रोह की सच्ची वारिस है। 1980 के दशक से पी.डब्ल्यू. व एम.सी.सी. द्वारा शुरू किए गए सशस्त्र संघर्ष का पार्टी व आन्दोलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने और आपने अपने शहीदों का रक्त बहाकर जो अनुभव हासिल किए हैं, हम उनके आदान-प्रदान के इच्छुक हैं।

..... दोनों पार्टियों के सम्बन्ध बहुत पुराने हैं ..... 1993 से हम आपके लम्बे सशस्त्र संघर्षों के अनुभवों से सीखते आ रहे हैं। हमारा सम्बन्ध केवल वैचारिक व राजनीतिक अनुभवों के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे भी व्यापक हैं।

..... भारतीय क्रांति व विश्व क्रांति का अटूट सम्बन्ध है। भारत में क्रांति हुए बिना हम विश्व क्रांति के बारे में सोच भी नहीं सकते।

..... भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम पी.डब्ल्यू. से आशा करते हैं कि वे तमाम माओवादियों को एक केन्द्र के नीचे लाने का प्रयास करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इन प्रयासों में हमारी पार्टी हर सहयोग करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोचेगी।

..... आज विश्व भर में आंदोलन तीव्र हो रहे हैं। दक्षिण एशिया एक ज्वालामुखी की तरह है। भारत और नेपाल में माओवादियों के नेतृत्व में शक्तिशाली जनयुद्ध लड़े जा रहे हैं। राष्ट्र मुक्ति संघर्ष तेज हो रहे हैं। भारतीय विस्तारवाद के रूप में हमारे सामने एक साझा दुश्मन मौजूद है।

..... हम आशा करते हैं कि भारत में नव जनवादी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए, तमाम माओवादियों के एक केन्द्र में एकताबद्ध करने के लिए, विश्व सर्वहारा क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए विश्व सर्वहारा का एक शक्तिशाली अंग बनने के लिए, यह कांग्रेस सही वैचारिक - राजनीतिक दिशा को सूत्रबद्ध करने में सफल होगी।

पुनः हम आशा करते हैं कि यह कांग्रेस पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। ❖

की गई मिठाई *'7 कप्स'* सभी में बांटी गई।

कांग्रेस का प्रतिनिधि-सत्र

कांग्रेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पांच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल का चयन किया गया। चर्चा को मार्गदर्शन देने के लिए पुरानी केन्द्रीय कमेटी स्टीयरिंग कमेटी के रूप में काम करने लगी। इसके बाद भाईचारा पार्टियों से आए प्रतिनिधियों ने भाषण दिया।

18 दिनों की गहन चर्चा के बाद कांग्रेस ने निम्नलिखित दस्तावेज पारित किए। 1) कार्यक्रम, 2) संविधान, 3) रणनीति और कार्यनीति, 4) राजनीतिक प्रस्ताव, 5) राजनीतिक - सांगठनिक समीक्षा और 6) वित्तीय नीति। एक अन्य दस्तावेज गुरिल्ला जोन - हमारा परिप्रेक्ष्य को वापिस ले लिया गया क्योंकि उसके दो अध्याय रणनीति-कार्यनीति में शामिल कर लिए गए थे और बाकी कुछ उसमें दोहराया गया था।

कांग्रेस ने 1970 के कार्यक्रम की क्रांतिकारी दिशा का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और पिछले 30 वर्षों के बदलावों के अनुसार उसे और समृद्ध किया।

भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन की आम दिशा 1967 से लेकर आज तक एक ही तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन मुक्त इलाकों का गठन, जनसेना का निर्माण आदि मामलों में क्या-क्या करने होंगे, इस पर कुछ हद तक अस्पष्टता ही रही है। हमारी पार्टी ने 1980 के दशक से ही गुरिल्ला जोनों के निर्माण को

महत्व दिया और 1995 से ठोस रूप से "गुरिल्ला जोन - हमारा परिप्रेक्ष्य" के नाम से एक विशेष दस्तावेज तैयार करके हमारी पार्टी में इस विषय पर एक आम समझ कायम की गई। 1995 में संपन्न पुरानी पीपुल्सवार के अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन ने माना कि दण्डकारण्य और उत्तरी तेलंगाना गुरिल्ला जोन के प्राथमिक चरण में हैं। अब उन्हें उच्च अवस्था के गुरिल्ला जोनों में विकसित करना चाहिए, यह भी तय किया गया था। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जरूरी सांगठनिक और फौजी निर्माणों और कार्यनीति को भी मोटे तौर पर तय करके यह भी तय किया गया कि किस चरण में किन-किन शर्तों को पूरा करना है।

बीते पांच वर्षों के दौरान प्राप्त कुछ नए अनुभवों की रोशनी में इस कांग्रेस ने और भी स्पष्टता के साथ फौरी कार्यभार और लक्ष्य निर्धारित किए। कांग्रेस ने फौरी लक्ष्य के तहत दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदलने का आह्वान किया जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका है और जहां पर्याप्त जनाधार है और पीजीए के बल मौजूद हैं। साथ ही, कांग्रेस की राजनीतिक - सांगठनिक समीक्षा में प्रमुख कर्तव्य के तहत यह भी स्वीकार किया गया है कि आन्ध्र-उड़ीसा सीमा इलाके में मुक्त अंचल बनाने के मकसद से काम किया जाए और उत्तरी तेलंगाना के सामरिक दृष्टि से अनुकूल इलाकों में छापामार युद्ध तेज करते हुए ही मुक्त इलाके के लक्ष्य से योजनाएं बनाई जाएं।

कांग्रेस ने तय किया कि बिहार के कोयल-कैमूर इलाके के अलावा, देश भर में हम जिन सामरिक महत्व के इलाकों में काम कर रहे हैं, उन सभी इलाकों में हमारा आम लक्ष्य छापामार जोनों

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की विचारधारात्मक एकता को मजबूत करो!

- टीकेपी/एमएल

[भाकपा (मा-ले) (पीपुल्स वार) की 9वीं कांग्रेस के लिए भाईचारा संदेश के कुछ अंश]

टीकेपी/एमएल की केन्द्रीय कमेटी की ओर से मैं आपकी पार्टी की 9वीं कांग्रेस का क्रांतिकारी अभिनन्दन करता हूं। इस कांग्रेस का महान ऐतिहासिक महत्व है।

आपकी कांग्रेस मई 1967 के नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह की सच्ची वारिस है जो संसदीय सुधारवाद व प्रतिक्रियावादी फासीवादी शासकों व स्थानीय शोषकों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। आपकी यह कांग्रेस पुरानी पी.डब्ल्यू. व पुरानी पी.यू. की संयुक्त कांग्रेस है। आपकी कांग्रेस दो माओवादी पार्टियों के विलय को और भी मजबूत करेगी जिसका भारतीय क्रांति के भविष्य के लिए अथाह महत्व है।

आपकी कांग्रेस एक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर के साम्राज्यवादी, पूंजीपति, संशोधनवादी चिल्ला रहे हैं कि समाजवाद मर गया है। हमें यकीन है कि फासीवादी प्रतिक्रियावादी भारतीय शासकों के भयंकर दमन व चौतरफा हमलों के बावजूद यह कांग्रेस सफल होगी जो भारतीय शासकों व साम्राज्यवादियों के विरुद्ध एक सफलता कहलाएगी।

एक के बाद एक समाजवादी देशों का पतन और विश्व सर्वहारा की हार अस्थाई हार ही हैं। जो साम्राज्यवादी और इसकी सड़ी-गली व्यवस्था में कुछ प्रगतिशीलता देख रहे हैं, वे गलती पर हैं। करोड़ों-करोड़ उत्पीड़ित व शोषित जनता आज नहीं तो कल दासता के बंधनों को तोड़कर शोषक वर्गों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी।

आज अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के आगे वैचारिक व सांगठनिक एकता को मजबूत करना और मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए जन संघर्षों में इन्हें एक भौतिक ताकत के रूप में बदलना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी विज्ञान पर जोर देते हुए और भारी कीमत अदा करके ही इस महान व ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि विश्व की माओवादी शक्तियां इस महान, किन्तु मुश्किल कार्यभार को अपने भाईचारा संगठनों के साथ लेते हुए पूरा कर पाने में सफल होंगी।

टीकेपी/एमएल और तुर्की व तुर्क-कुर्दिस्तान की जनता आपकी पार्टी व भारत की जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेगी। हम पुनः कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, लाल योद्धाओं को व इस कांग्रेस को सफल बनाने के लिए प्रयत्नरत तमाम कॉमरेडों को क्रांतिकारी अभिनन्दन करते हैं। ✪

पार्टी सचिव कॉ. गणपति के उद्घाटन भाषण का सारांश

कॉ. चारु मजुमदार की शहादत के बाद पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई। 70 के दशक में दक्षिणपंथी व वामपंथी भटकावों से संघर्ष करते हुए पार्टी की आन्ध्रप्रदेश इकाई ने स्वयं को मजबूत किया। सही राजनीतिक व सांगठनिक समीक्षा के चलते हम न केवल आन्दोलन का विकास कर पाए, बल्कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता में भी कामयाब हुए।

अन्य मा-ले पार्टियों की तरह हम केवल वैचारिक बहसों में ही उलझकर नहीं रहे, बल्कि हमने वर्ग संघर्ष को भी तेज किया था। परिणामतः हम शत्रु से भी दमन मुहिम का सामना कर पाए और पार्टी के आन्तरिक संकट से भी निकल पाए। 1970 कांग्रेस द्वारा तय की गई कार्यक्रम की बुनियादी दिशा पर हम अड़िग रहे।

इसके बावजूद बदलती परिस्थितियों में हम अपनी कार्यनीति को बदलने में सफल रहे, अन्यता आगे बढ़ना असम्भव था और सही राजनीतिक दिशा अपनाकर ही हम आन्ध्रप्रदेश के छोटे इलाके से पार्टी को देशव्यापी बना पाए हैं। इसी प्रकार पुरानी पी.यू. पार्टी बिहार, बंगाल, पंजाब व दिल्ली में आन्दोलन का विकास कर पाई।

कृषि क्रांति को पूरा करने के लिए व गुरिल्ला जोनों की स्थापना के लिए हमें जनता का विश्वास जीतना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के मार्गदर्शन में जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है और हम भी उसमें थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। हमारी क्रांति विश्व सर्वहारा क्रांति का एक हिस्सा है।

पार्टी, जनता की सशस्त्र शक्तियां व संयुक्त मोर्चा को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें पार्टी का सैद्धांतिक - वैचारिक स्तर उन्नत करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें उचित प्रशिक्षण देना होगा।

देश के विस्तार व विभिन्नताओं को देखते हुए विभिन्न राज्य व रीजनल कमेटियों को चाहिए कि वे पार्टी लाइन को सृजनात्मक ढंग से लागू करें।

पार्टी का मुख्य कार्यभार है - पीजीए को मजबूत करते हुए जनयुद्ध के लिए जनता को लामबंद करना। और पार्टी व आन्दोलन का सुदृढ़ीकरण इस पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जनसत्ता स्थापित हो चुकी है वहां सहकारिता के आधार पर नए उत्पादन के सम्बन्ध स्थापित करने होंगे, एक क्रांतिकारी ढंग से जनता के विचारों व जीवन में बदलाव लाना होगा। हमें ऊपरी ढांचे का क्रांतिकरण करने की आवश्यकता है। जनसत्ता के संस्थानों की रक्षा जनसेना करेगी।

अलग-अलग इलाकों में अपना आन्दोलन भिन्न-भिन्न स्तरों तक विकसित हुआ है, लेकिन हमें रणनीतिक क्षेत्रों पर केन्द्रित करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी व श्रम के बीच अन्तरविरोध बढ़ रहे हैं और साम्राज्यवाद को अपने ही लोगों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज चाहे जनयुद्ध पांच देशों में ही चल रहा है और इन्हें कुछ लोग महत्वहीन बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि यही आन्दोलन अग्रगामी दस्ते का काम करते हुए बाकियों के लिए प्रकाश स्तम्भ बनेंगे।

चीन के संशोधनवादी देश में बदलने के बाद विश्व क्रांति के लिए भारत की क्रांति की सफलता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और हमें साहसपूर्वक इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार रहना होगा। साम्राज्यवाद विभिन्न तरीकों से आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करेगा। अतः हमें न केवल अपने शासक वर्गों की, बल्कि साम्राज्यवादियों की प्रति क्रांतिकारी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा।

अतः इन ऐतिहासिक कार्यभारों को ध्यान में रखते हुए 9वीं कांग्रेस को निर्णय लेने की आवश्यकता है। भारत की जनता को आशा है कि वे इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। ✪

का निर्माण रहना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि जनयुद्ध को तेज करते हुए मुक्त इलाकों का गठन करना और जनसेना को मजबूत बनाना हमारा आम कार्यभार होना चाहिए और सभी कार्यक्रमों को इस लक्ष्य के मातहत ही रखना चाहिए।

कांग्रेस ने समीक्षा की कि कुछ फैसले करने में संबंधित कमेटियां और केन्द्रीय कमेटी देर से प्रतिक्रिया की या अनुभव के अभाव से स्पष्टता नहीं हासिल कर सकीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि 1995 तक ही जन छापामार सेना के निर्माण के मुद्दे पर स्पष्टता हासिल करनी चाहिए थी और ऊपर से नीचे तक सैन्य कमानों का गठन करना चाहिए था। यह भी माना गया कि सैनिक दृष्टि से प्लाटून को संगठन का आम स्वरूप बनाने का लक्ष्य तय करने के बावजूद इसके लिए अपनाया गया तरीका गलत था जिसमें सांगठनिक और मिलिटरी कर्तव्यों को अलग नहीं किया गया। कांग्रेस ने यह

कॅम्यून में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

पार्टी की 9वीं कांग्रेस के ऐतिहासिक अवसर पर कॅम्यून में 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का भी अवसर मिला। यद्यपि समय कम था, लेकिन शीघ्रता से कार्यक्रम बनाया गया और न केवल कॅम्यून सदस्य, बल्कि पास के गांवों की महिलाएं भी इस यादगार अवसर पर उपस्थित थीं। पूरे कॅम्यून में महिला मुद्दों से सम्बन्धित पोस्टर लगाए गए। `गुरिल्ला वाणि' का एक विशेष अंक इस अवसर पर निकाला गया।

कॉ. राधा, महिला दस्ते की कमाण्डर ने कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का झण्डा फहराया। अपने भाषण में कॉ. राधा ने भारत में 8 मार्च के इतिहास पर प्रकाश डाला और उत्पीड़ित वर्ग की महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे शोषण का आधार इस अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था में देखने का आह्वान किया। डिवीजन कमेटी सदस्य कॉ. मैना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्लाटून सेक्शन कमाण्डर कॉ. रीता ने आदिवासी महिलाओं पर पितृसत्तात्मक समाज के चलते हो रहे उत्पीड़न पर बात रखी। उसने कॉ. निर्मला, कॉ. कमला आदि महिला शहीदों के विषय में बताया जो अपना घर व नौकरी छोड़कर आदिवासी महिलाओं के बीच काम करने के लिए जंगल में चली आईं।

*जिला कमेटी सदस्या कॉ. विजया ने दण्डकारण्य की महिला शहीदों के बारे में एक पुस्तक **'आधे आसमान के चमकते सितारे'** का विमोचन किया।*

कॉ. गौरव ने नेपाल में चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष से महिला की स्थिति पर पड़ रहे सकारात्मक प्रभावों का वर्णन किया। कॉ. ओकान ने अपनी पार्टी टीकेपी/एमएल की ओर से सभी महिला कॉमरेडों का क्रांतिकारी अभिनन्दन करते हुए कहा कि हमारे पास केवल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन और माओ ही नहीं हैं, बल्कि हमारे पास क्लारा जेटकिन, रोज़ा लक्ज़ेम्बर्ग, एलेक्सैंड्रा कोलान्ताय और चियांग चिङ भी हैं। कॉ. ओकान ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्वकारी स्थानों पर आने के लिए आह्वान किया।

केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सुमित ने बताया कि कैसे क्रांतिकारियों और संशोधनवादी व बुर्जुआ पार्टियों द्वारा इस दिन को मनाने में अन्तर है।

*कॉ.मैना ने 8 मार्च का केन्द्रीय आह्वान देते हुए **पीजीए में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने** पर केन्द्रित किया।*

भाषणों के बीच में गोण्डी, हिन्दी व तेलुगु में महिला उत्पीड़न व उसके विरुद्ध महिलाओं के संघर्ष से जुड़े अनेक गीत गाए गए और कुछ नाटक प्रस्तुत किए गए। ✪

विश्लेषण भी किया कि हालांकि दक्षिणी तेलंगाना 1995 तक ही गुरिल्ला जोन के प्राथमिक चरण में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद उन्नत कार्यभार तय करने में हम पिछड़ गए थे।

समीक्षा में मजदूर मोर्चा व महिला मोर्चा पर किए जा रहे काम में मौजूद कमजोरियों पर बात रखी गई और इन क्षेत्रों के विकास के लिए उप-कमेटियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया।

कांग्रेस द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय व देशीय स्तर पर होने वाले राजनीतिक बदलावों का सार प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का मानना है कि यद्यपि अमरीकी महाशक्ति पहले से कमजोर हुई है लेकिन अभी भी विश्व की जनता की न० 1 दुश्मन है। साम्राज्यवादी शक्तियों के बढ़ते आपसी अंतरविरोध व उनके विरुद्ध विश्व की जनता के बढ़ते संघर्षों का विश्लेषण किया गया। भारत पर कसते साम्राज्यवादी शिकंजे और नई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों का विश्लेषण हुआ। हिन्दू फासीवादी खतरे के प्रति भी कांग्रेस ने जनता को आगाह किया है। कांग्रेस ने तय किया कि विश्व स्तर पर प्रधान अन्तरविरोध साम्राज्यवाद व उत्पीड़ित जनता व राष्ट्रों के बीच का अन्तरविरोध है।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति व तथाकथित `4 लोगों का गैंग' के समर्थन में एक प्रस्ताव किया गया। इसमें लिन पियाओ व उसकी अतिवाम लाइन की भर्त्सना की गई।

1974 की आत्मालोचनात्मक समीक्षा को ऐतिहासिक दस्तावेज मानने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दस्तावेज ने 1970 के शुरू में पार्टी को हुए नुकसानों की समीक्षा करते हुए पार्टी को आगे का मार्ग प्रशस्त किया था।

कई सैद्धांतिक मुद्दों पर कांग्रेस ने पार्टी को स्पष्टता दिलाई

माओवाद :

कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि अब तक जिसे हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा कहते आ रहे थे अबसे उसे मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद कहना चाहिए। माओवाद का यह कहकर विश्लेषण किया गया कि वह लेनिनवाद को और भी समृद्ध बनाने वाला उन्नत चरण था। कांग्रेस ने यह भी माना कि माओ विचारधारा के बजाए माओवाद कहने में कोई गुणात्मक फर्क नहीं है, जैसा कि

पीजीए ने पहलकदमी छीनी !

कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली की शहादत के एक वर्ष पूरे होने के दिन 2 दिसम्बर 2000 को पीजीए का गठन किया गया। उसके बाद से ही इसने दुश्मन के भाड़े की सेना से सैनिक पहलकदमी छीननी शुरू कर दी। एक तरफ कांग्रेस की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही थी, तो दूसरी तरफ पीजीए ने भी कार्यनीतिक जवाबी हमला शुरू कर दिया। जिन दिनों कांग्रेस चल रही थी, ये हमले और भी तेज हो गए। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पीजीए द्वारा रेड, एम्बुश और अन्य कई कार्रवाइयां की गई हैं।

रेड

एक ओर जब कांग्रेस प्रतिनिधि राजनीतिक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श में डूबे हुए थे तो दूसरी ओर पीजीए कॉमरेड्स दुश्मन की नींद उड़ा रहे थे। मार्च महीने में की गई रेड इस प्रकार हैं।

- आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के मार्गदर्शन में पीजीए ने पीलेरु मण्डल, चित्तूर जिले में पुलिस कैम्प पर रेड व एम्बुश किया। पीजीए के एक हिस्से ने कैम्प पर रेड किया और दूसरा रास्ते पर एम्बुश के लिए बैठा जहां से और पुलिस के आने की संभावना थी।
- 6 मार्च को कैम्प पर हमला किया गया। सभी पुलिस वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया वहां से कई एस.एल.आर. प्राप्त हुईं। जमींदार के जिस घर में कैम्प था उस घर को भी उड़ा दिया गया। एक घण्टे बाद जब उस कैंप की ओर नई फोर्स जा रही थी तो बारूदी सुरंग से एम्बुश किया गया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए।
- 12 मार्च को उड़ीसा में गजपति जिला में हम्पादोरा पुलिस कैम्प पर आन्ध्र-उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के फैसले पर पीजीए ने रेड किया। 2 पुलिस वाले मारे गए और बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कार्रवाई में 8 रायफलें, 1 सब मशीन गन, 1 रिवॉल्वर और 900 गोलियां बरामद हुईं।
- आन्ध्रप्रदेश राज्य कमेटी के अन्तर्गत 20 मार्च की रात को पीजीए की एक ही टीम ने दो रेड की। पहली सुन्निपेन्टा, जिला कर्नूल के पुलिस थाने पर और दूसरा वहां से 6 किलोमीटर दूर श्रीशैलम पुलिस आउट पोस्ट पर। पुलिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। रायफलें जब्त कर ली गई और पुलिस जीप को उड़ा दिया गया। श्रीशैलम रेड में एक पुलिस घायल हुआ और बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 रायफलें, कई .410 मस्कट और 2 उच्च शक्ति के कम्युनिकेशन सेट जब्त किए गए।

एम्बुश

- ए.ओ.बी. में विजयनगरम जिला में गुम्मालक्ष्मीपुरम में 27 जनवरी को पुलिस पार्टी को एम्बुश किया गया जिसमें 1 हवलदार व एक पुलिस का व्यक्ति मारा गया और 4 अन्य घायल हो गए।
- जनवरी के अन्त में दण्डकारण्य में माड़ डिवीजन में एक पुलिस गश्त दल पर मौकाई एम्बुश करके एक पुलिस वाले को मार दिया गया।
- विशाखापट्टणम में चिन्तापल्ली के नजदीक फरवरी में एक पुलिस गाड़ी पर बारूदी सुरंग से एम्बुश किया गया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए।

एकल कार्रवाइयां

- दण्डकारण्य में बस्तर डिवीजन में पहले 3 महीनों में 9 पुलिस मुखबिरों का सफाया कर दिया गया।
- महबूबनगर जिला में जनवरी में एक कुख्यात होमगार्ड का सफाया किया गया जो पूर्णकालिक पुलिस मुखबिर था।
- महबूबनगर जिला में कल्वाकुर्थी क्षेत्र में हनुमन्ता रेड्डी नाम के एक सब-इन्सपैक्टर को मार दिया गया।
- नलगोण्डा जिला में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का सफाया किया गया।
- नलगोण्डा जिला में नारायणपुरम मण्डल केन्द्र में एक कांस्टेबल को मार्च के अन्त में मार दिया गया।
- करीमनगर जिला में कमलापुर में एक कांस्टेबल का सफाया किया गया। क्षेत्र का मुख्य पुलिस मुख्यालय होने के बावजूद जन मिलिशिया की मदद से पीजीए ने यह कार्रवाई की।
- निजामाबाद जिला में गंगारम में एक तेलुगुदेशम पार्टी नेता का सफाया किया गया।

अन्य कार्रवाइयां

फरवरी में संचार व्यवस्था के उपकरणों को जब्त करने की मुहिम ली गई।

- नलगोण्डा जिला में नागार्जुनसागर के नजदीक एक निर्माण कैम्प से 4 वाकी-टाकी, 2 वायरलेस सेट, 1 बेस सेट जब्त किए गए।
- नलगोण्डा जिला में दो रेलवे स्टेशनों पर कार्रवाई करते हुए वाकी-टाकी सेट जब्त किए गए।
- नंद्याला-गुन्टूर लाइन पर एक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से एक वाकी-टाकी जब्त किया गया।
- विजयनगरम के नजदीक एक गाड़ी से पीजीए ने 1 वाकी-टाकी जब्त किया। ❖

कुछ पार्टियां मान रही हैं।

प्रधान अंतरविरोध :

विश्व में मौजूद अंतरविरोधों का विश्लेषण कर हमने तीन प्रमुख अंतरविरोधों को पहचान लिया है। वे हैं -

1) साम्राज्यवाद X उत्पीड़ित जनता और राष्ट्र

2) पूंजी X श्रम

3) साम्राज्यवादियों के बीच अंदरूनी अंतरविरोध

लेकिन हमने यह स्पष्ट नहीं किया था कि उनमें प्रधान अंतरविरोध क्या है। साथ ही, पूर्व में हमारी पार्टी ने माना था कि फिलहाल इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9वीं कांग्रेस ने इस विषय पर चर्चा करके निर्धारित किया कि प्रधान अंतरविरोध को जरूर पहचाना जाना चाहिए और साम्राज्यवाद और विश्व की उत्पीड़ित जनता व राष्ट्रों के बीच का अंतरविरोध ही प्रधान अंतरविरोध है।

तीसरा बुनियादी अंतरविरोध :

अब तक हमारा विश्लेषण यह रहा कि हमारे देश में दो बुनियादी अंतरविरोध मौजूद हैं, और उनका हल करने से ही बाकी अंतरविरोध प्रभावित होकर, उनका हल होगा। वे हैं - सामंतवाद X भारत की जनता और साम्राज्यवाद X भारत की जनता। इन दोनों में सामंतवाद और भारत की जनता के बीच के अंतरविरोध को प्रधान अंतरविरोध बताया जा चुका है। लेकिन हमने सामंतवाद, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद - इन तीनों को हमारे दुश्मन के रूप में चिन्हित किया है। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया कि दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और भारत की जनता के बीच का अंतरविरोध भी एक बुनियादी अंतरविरोध है जिसे हमें हल करना होगा।

दो कार्यदिशाओं के बीच संघर्ष :

हमारी पार्टी के इतिहास में हम कई बार दो कार्यदिशाओं के बीच संघर्ष चलाते हुए, हमेशा वामपंथ और दक्षिणपंथ का मुकाबला करते हुए, अपनी गलतियों को सुधारते चले आ रहे हैं। 1974 में पार्टी में मौजूद वाम एकांगीढंग को सुधारने के साथ शुरू करके, पार्टी की कार्यदिशा पर कई बार हुए हमले को पराजित करते हुए, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर प्रकट हुए वामपंथी और दक्षिणपंथी अवसरवाद का पर्दाफाश करते हुए सही कार्यदिशा के लिए दृढ़तापूर्वक खड़े होते रहे हैं। इस संघर्ष में हमें प्राप्त अनुभवों और हमारे क्रांति के कार्याचरण के बदौलत हमारी समझ को और हमारी कार्यदिशा को और बेहतर बनाते आ रहे हैं। इस बार चंद प्रतिनिधियों ने आत्मालोचना रिपोर्ट के समय से ही पार्टी की कार्यदिशा में दक्षिणपंथी भटकाव मौजूद है कहकर कुछ वामपंथी सूत्रीकरणों को सामने लाया। इस पर गहरी चर्चा के बाद कांग्रेस ने उनके तर्कों को नकार दिया तथा पार्टी की कार्यदिशा का बचाव करते हुए उसे और भी समृद्ध बनाया।

गैर-सर्वहारा भटकावों के खिलाफ संघर्ष :

पिछले 2,3 सालों से कई राज्यों में आन्दोलन के दौरान पनपे गैर-सर्वहारा भटकावों के खिलाफ पार्टी को, जन छापामार सेना को, जन संगठनों को और जनता को जागृत करके सही सर्वहारा पार्टी के रूप में पार्टी को उभारने का सिलसिला जारी है। इस बात पर स्पष्टता भी बढ़ रही है कि राजसत्ता छीन लेने के लक्ष्य के साथ ही संघर्ष और संगठन के सभी स्वारूपों का तालमेल करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस ने आह्वान किया कि समूची पार्टी में अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग स्तरों पर उत्पन्न हुए गैर-सर्वहारा भटकावों के खिलाफ संघर्ष जरूरी है। मनोगतवाद, स्वतःस्फूर्तता और इन दोनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न अर्थवाद - इन तीनों को कांग्रेस ने मुख्य भटकावों के रूप में पहचाना। इनके अलावा एकांगीढंग, उदारतावाद, नौकरशाही और पितृसत्ता भी पार्टी में विभिन्न मात्रा में पनपे हैं। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि इन भटकावों के खिलाफ सैद्धांतिक तौर पर लड़ना चाहिए और सभी स्तरों पर पार्टी में शिक्षा देना जरूरी है और उसकी तैयारियां शीघ्रता से की जाएं। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि गैर-सर्वहारा भटकावों और कमजोरियों को दूर करके पार्टी का शुद्धिकरण करने से ही अब तय किए प्रमुख कर्तव्य पर अमल करने के लिए समूची पार्टी को दिशा दी जा सकती है।

> **"सामरिक इलाकों में मुक्त इलाकों का गठन हमारा प्रमुख कार्यभार हो!"**
>
> **- कांग्रेस का आह्वान**

पहलकदमी न गंवाने और दुश्मन के हमले को हराने के बारे में : हमारी पार्टी का अब तक का इतिहास पूरा यही बताता है कि आन्दोलन के विकासक्रम में एक बार दुश्मन का पलड़ा भारी रहा है तो एक बार हमारा पलड़ा भारी रहा है। कई मोड़ों से गुजरता और कई छलांगें लगाता हुआ यह विकासक्रम लगातार जारी है। अब देश भर में कुछ इलाकों में हम हावी में हैं तो कुछ और इलाकों में दुश्मन ने पिछले 2-3 सालों से धीरे-धीरे पहलकदमी

छीन ली है। मुख्य रूप से केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार के बनने के बाद केन्द्र-राज्य सरकारों ने संयुक्त कमान (जेओसी) की अगुवाई में आन्दोलन के खिलाफ चौतरफा हमला छेड़ दिया गया है जो कि पहला देशव्यापी आक्रमण अभियान है। इस योजना के पीछे विश्व बैंक और साम्राज्यवाद का सहयोग है।

इस हमले का मुकाबला करने में हमने जो कार्यनीति अपनाई और जो प्रतिरोध किया उनमें कई खामियां रही हैं। इसलिए, कांग्रेस ने आह्वान किया कि इनमें से उबरते हुए हमारे कार्यनीतिक जवाबी आक्रमण में पार्टी, जन छापामार सेना और जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करके दुश्मन की पहलकदमी को तोड़कर पहलकदमी को अपने हाथों में लेना चाहिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि अब तक जिन इलाकों में पहलकदमी हमारे पास है उसे बनाए रखते हुए कई और कार्यनीतिक हमलों का अभियान चलाकर दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया जाए और पीजीए को मजबूत बनाते हुए उसे जन मुक्ति सेना में बदल दिया जाए।

इसके लिए देशव्यापी मजबूत व गुप्त पार्टी का निर्माण कर, उसके नेतृत्व में जनता को हथियारबंद करना, जन मिलिशिया का निर्माण करना, सटे हुए इलाकों में जनता की राजसत्ता के अंगों को मजबूत बनाना, प्लाटूनों को आम स्वरूप में बदलते हुए कम्पनियों का निर्माण करना और इसके लिए बड़े पैमाने पर भर्तियों को बढ़ाना आदि सांगठनिक कार्यभार कांग्रेस ने तय किए।

इनके साथ ही, कई सैद्धांतिक और राजनीतिक कार्यभार भी निर्धारित किए गए। मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर 19 दिनों तक बहस की गई, जब हाल किसी मुद्दे पर एकमत पर नहीं पहुंच सका तब मत-विभाजन करके कांग्रेस ने पहलकदमी के साथ उचित फैसले किए।

अन्त में कांग्रेस ने कई प्रस्ताव पारित किए जैसे क्रांतिकारी शहीदों संबंधित, दुश्मन की जेलों में बन्द हजारों क्रांतिकारियों के अभिनन्दन में, राष्ट्रीयता के संघर्षों के समर्थन में, साम्राज्यवाद के विरुद्ध उत्पीड़ित राष्ट्रों के संघर्षों के बारे में, विश्व भर के सर्वहारा वर्ग के संघर्षों के समर्थन में, पेरु, फिलिप्पीन्स, तुर्की और नेपाल में माओवादियों के नेतृत्व में चल रहे क्रांतिकारी संघर्षों के समर्थन में, भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ आदि-आदि।

कांग्रेस का अन्तिम सत्र केन्द्रीय कमेटी द्वारा आत्मालोचना-आलोचना का सत्र था। इसके बाद नई केन्द्रीय कमेटी का चयन किया गया और कॉ. गणपति को पुनः सचिव के रूप में चुना गया। केन्द्रीय कमेटी ने पोलित ब्यूरो और केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का चुनाव भी किया ताकि पार्टी को राजनीतिक, सैद्धांतिक व सैन्य मामलों में कुशल नेतृत्व मुहैया कराया जा सके। इसके बाद दोनों भाईचारा प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कांग्रेस में लिए प्रमुख फैसलों पर खुशी व्यक्त की।

सभा के परिसर हर दिन क्रांतिकारी गीतों से गूंज उठता थे। हर तरफ बेहिचक और सटीक विचारों का आदान-प्रदान बोल्शेविक माहौल में किया जाता रहा। कॉमरेड्स श्याम, महेश, मुरली कॅम्यून में यह विश्वास कायम हो गया कि भारत की क्रांति पिछले 25 सालों के संघर्ष में तपकर उभरे परिणीत नेतृत्व के मार्गदर्शन में सही दिशा तय करके आगे बढ़ेगी।

समापन समारोह

अन्ततः 21 मार्च को कांग्रेस का प्रतिनिधि-सत्र समाप्त हुआ। 22 मार्च को सुबह पूरा कैम्प शहीद स्मारक के सामने उपस्थित हुआ। पूरी कांग्रेस के समय पार्टी झण्डा फहराता रहा था, अब उसे गर्वपूर्वक उतारने का वक्त आ गया था।

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा कॅम्यून की संचालन कमेटी की ओर से सभी प्रतिनिधियों का पार्टी की 9वीं कांग्रेस सफलतापूर्वक समाप्त होने पर क्रांतिकारी अभिनन्दन किया गया। इसके पश्चात उन सभी कॉमरेडों का धन्यवाद किया गया जिनकी दिन-रात की मेहनत व पूरी चौकसी के चलते कांग्रेस बिना किसी रुकावट के समाप्त हुई।

इसके बाद उपस्थित समूह को सचिव कॉ. गणपति ने सम्बोधित किया। अपने भाषण में कॉ. गणपति ने कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन किया।

कांग्रेस द्वारा लिए गए मुख्य राजनीतिक कार्यभार इस प्रकार हैं :

1. पीजीए को मजबूत करो और गुरिल्ला जोनों को आधार इलाकों मे विकसित करने के लिए काम करो।
2. सशस्त्र प्रतिरोध व तमाम जनवादी शक्तियों को एकजुट करते हुए राजकीय दमन को परास्त करो।
3. देश में साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध व भूमण्डलीकरण के नाम पर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध तमाम शक्तियों को एकजुट करो।
4. साम्राज्यवाद व विशेष तौर पर विश्व की जनता के न० 1 दुश्मन अमरीकी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए विश्व की तमाम उत्पीड़ित जनता के साथ एकजुट हो।
5. हिन्दू फासीवाद के विरुद्ध तमाम शक्तियों को एकजुट करो।
6. भारतीय विस्तारवाद के विरुद्ध दक्षिण एशिया की उत्पीड़ित जनता के साथ एकजुट हो।

अन्त में कांग्रेस विभिन्न भाषाओं में अन्तर्राष्ट्रीय गीत गाए जाने के साथ समाप्त हो गई। कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों व कार्यभारों को पूरा करने के दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास के साथ प्रतिनिधि लौट गए। ❖

दण्डकारण्य को आधार इलाके में बदल डालो !
छापामार आधारों का निर्माण करो !

जन छापामार सेना, जनता और जन संगठनों को
दण्डकारण्य स्पेशल जोन के तीसरे पार्टी अधिवेशन का आह्वान

दण्डकारण्य का वह एक दस्ता इलाका था। उस पूरे स्थल को दण्डकारण्य स्पेशल जोन के तीसरे अधिवेशन के आयोजन के लिए सजाया गया था। 13 दिनों तक उस स्थल में हर तरफ क्रांतिकारी जोश व स्फूर्ति बिखरती रहीं। वहां एक नया लाल गांव बसाया गया था ताकि वहां अपने-अपने डिवीजन अधिवेशनों को सफलतापूर्वक आयोजन कर पांचों डिवीजनों से आए प्रतिनिधि तथा पीजीए के छापामार रह सकें। शत्रु-दमन को भेदते हुए वहां पहुंचे प्रतिनिधियों, अधिवेशन के सूचारू एवं सुरक्षित संचालन के लिए चारों तरफ तैनात किए गए पीजीए बलों तथा अधिवेशन स्थल के इर्द-गिर्द मौजूद कई गांवों की जनता के दुश्मन की हर हलचल पर लगातार नजर रखते हुए चौकसी बरतने से ही यह पूरा कार्यक्रम कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। अधिवेशन निर्बाध चला।

दण्डकारण्य अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों की

वर्गीय पृष्ठभूमि		कुल - 39	शैक्षणिक पृष्ठभूमि	
खेतिहर मजदूर	1		पार्टी पढ़ाई	5
गरीब किसान	9		प्राथमिक शिक्षा	1
मध्यम वर्ग/उच्च मध्यम वर्ग	23		माध्यमिक	3
धनी किसान	5		हाइ स्कूल	6
जमींदार वर्ग	1		इंटर	9
			स्नातक/स्नातकोत्तर	13
			व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा	2

फरवरी 1995 में दण्डकारण्य पार्टी का दूसरा अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था जिसमें दण्डकारण्य आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए फौरी कार्यभार और नारे निर्देशित किए गए थे। दूसरे अधिवेशन द्वारा निर्देशित कर्तव्यों पर अमल करते हुए पार्टी नेतृत्व और काडरों द्वारा की गई दृढ़तापूर्वक व साहस भरी मेहनत के बदौलत इन पांच सालों में दण्डकारण्य आन्दोलन गुण में भी और तादाद में भी मजबूत हुआ। गुरिल्ला जोन को मजबूत करने के कार्यभार पर अमल में वह आगे बढ़ा। दूसरे अधिवेशन द्वारा निर्देशित कार्यभारों के अमल का मूल्यांकन करके आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के तहत नए कार्यभार निर्धारित करते हुए आयोजित दण्डकारण्य स्पेशल जोन का तीसरा अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

11 से 23 दिसंबर 2000 तक `कोय्यूर शहीद कॅम्यून' में कॉ. दीपक अधिवेशन हाल में आयोजित इस अधिवेशन में 37 प्रतिनिधियों, 2 गैर-मताधिकार वाले प्रतिनिधियों, एक प्रेक्षक (कुल 40 प्रतिनिधियों) और केन्द्रीय कमेटी के तीन सदस्यों ने भाग लिया।

11 दिसंबर की सुबह सभी प्रतिनिधि **'कोय्यूर शहीद कॅम्यून'** के मुख्य-द्वार से जुलूस की शक्ल में कॉ. विक्रम मैदान पहुंचे। बैनरों और इश्तहारों, जिन पर क्रांतिकारी नारे लिखे गए थे, को हाथों में लेकर, तमाम शहीदों को, खास तौर पर कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली को याद करते हुए गगनभेदी नारे लगाते हुए प्रतिनिधि जुलूस में चलते रहे। **"पीजीए को मजबूत बनाओ !", "छापामार आधार-क्षेत्रों का निर्माण करो !", "देश्व्यापी सरकारी हमले को मात दो !"** आदि नारे गोंडी, तेलुगु, हिन्दी भाषाओं में गूंज उठे।

बीच-बीच में पीजीए का गीत (गोंडी में) "पीपुल्सवार ता लाल फौज ....." गाया गया और शहीदों की शहादत का गुणगान करते हुए तेलुगु और गोंडी में कई गीत पेश किए गए और इस तरह यह जुलूस उत्साह भरे माहौल में कॉ. विक्रम मैदान पहुंचा।

जुलूस के मैदान पहुंचने के बाद, एसजेडसी और केन्द्रीय कमेटी के सदस्य झण्डे की ओर खड़े हो गए और अधिवेशन के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आए हुए पीजीए के मुख्य और गौण बलों के करीब 100 योद्धा और अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए प्रतिनिधि कतारबद्ध होकर झण्डे के सामने खड़े हो गए। पूरे मैदान में फैले लाल बंदनवारों और क्रांति के संदेश फैलाते पोस्टरों और बैनरों से निर्मित जोशीले माहौल में एसजेडसी सचिव कॉ. भूपति ने अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए पार्टी का झण्डा फहराया। बाद में सभी ने "मुट्टी हेट्टेड संगेने मंदाना ..... " झण्डा गीत गाया।

झण्डा फहराने के बाद अधिवेशन के प्रतिनिधि और पीजीए के योद्धा मैदान से उस स्थान की ओर चल पड़े जहां शहीदों की स्मृति में स्मारक खड़ा किया गया। स्मारक का अनावरण कॉ. नरेन्दर ने किया और अपने स्मारक भाषण में उन्होंने सभी शहीदों

का नाम लिया जिन्होंने 1995 से दिसंबर 2000 के बीच दण्डकारण्य आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए अपनी जान कुरबान कर दी। उन्होंने विशेष रूप से कोय्यूर शहीदों का नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजली पेश की। बाद में सभी प्रतिनिधियों और पीजीए के योद्धाओं ने अपने शस्त्रों को झुकाकर और टोपियां उतारकर शहीदों के सम्मान में दो मिनट की खामोशी मनाई।

स्मारक के अनावरण के बाद कॉ. रमणा ने दण्डकारण्य के शहीदों की जीवनियों की पुस्तक **'कुरबानियों की राह में संघर्ष के वारिस'** का विमोचन किया, जिसे दण्डकारण्य एसजेडसी ने हिन्दी में प्रकाशित किया। सभी प्रतिनिधियों और केन्द्रीय कमेटी सदस्यों ने कॉ. दीपक अधिवेशन हाल में प्रवेश किया।

हाल में प्रवेश करने वाले प्रतिनिधियों और सीसी कॉमरेडों का स्वागत करते हुए कॉ. लच्छन्ना ने अधिवेशन को सफल बनाने का आग्रह किया।

अधिवेशन के सुचारू संचालन के लिए एसजेडसी सचिव ने अध्यक्षमण्डल के तौर पर कॉ. गणेश, कॉ. नर्मदा और कॉ. राजेश के नाम घोषित किए तो हाल ने उसका अनुमोदन किया। बाद में संचालन कमेटी के तौर पर पूरी एसजेडसी को रहने का प्रस्ताव का हाल ने अनुमोदन किया, और अध्यक्षमण्डल एवं संचालन कमेटी को मंच पर आमंत्रित किया। बाद में उन्होंने सीसी कॉमरेडों को भी मंच पर आमंत्रित किया जो यह मार्गदर्शन देने के लिए आए थे कि यह अधिवेशन सही कार्यभार तय कर ले।

केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. रामजी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज की देशीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्रांति के लिए बेहद अनुकूल हैं। और फिलहाल क्रांति की बढ़िया हालत मौजूद है। उन्होंने साम्राज्यवादी संकट का ब्यौरा दिया। पेरू, फिलिप्पीन्स, नेपाल, तुर्की आदि देशों में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी किस तरह क्रांतिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉ. रामजी ने विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने यह आशा करते हुए कि यह अधिवेशन दण्डकारण्य को मुक्त इलाका बनाने के लक्ष्य से सही कार्यभार तय कर ले, अपना भाषण समाप्त किया।

अधिवेशन में एजेन्डे के पहले अंश के तौर पर शहीदों को लाल सलाम पेश करते हुए प्रस्ताव रखा गया। दूसरे अधिवेशन से तीसरे अधिवेशन के दरमियान दण्डकारण्य आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 30 कॉमरेडों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। साथ ही साथ, भारत की नव जनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र, बिहार आदि राज्यों में शहीद हुए सभी कॉमरेडों को लाल सलाम करते हुए अधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया।

11 से 23 दिसंबर तक कार्यक्रम, संविधान, रणनीति-कार्यनीति, गुरिल्ला जोन - हमारा परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक प्रस्ताव, केन्द्रीय राजनीतिक और सांगठनिक समीक्षा, वित्तीय नीति और दण्डकारण्य स्पेशल जोन की राजनीतिक और सांगठनिक समीक्षा दस्तावेजों को सीसी और एसजेडसी कॉमरेडों ने परिचय करवाते हुए पेश किया, तो प्रतिनिधियों ने उनमें कुछ संशोधन पेश करके कांग्रेस में भेजने का प्रस्ताव करते हुए सभी दस्तावेजों को पारित किया।

इन दस्तावेजों पर हुई बहसों में सभी प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर हमारी पार्टी की राजनीतिक, सांगठनिक व फौजी लाइन को समृद्ध बनाने में योगदान किया। कुछ राजनीतिक, सांगठनिक व फौजी मसलों पर मत-विभाजन हुआ और बहुमत के आधार पर उन्हें पारित या नकार दिया गया।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की पांच सालों की समीक्षा पर गहन चर्चा के बाद एसजेडसी द्वारा निर्देशित फौरी कार्यभारों का अनुमोदन करते हुए अधिवेशन ने 5 मुख्य नारे तय किए। अधिवेशन ने फैसला किया कि पार्टी की समूची शक्तियों, पीजीए और जनता को इन कार्यभारों की रोशनी में चलना होगा। अधिवेशन में तय किए गए पांच नारे :

1) छापामार युद्ध को तेज करते हुए मुक्त इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे !

2) समूचे दण्डकारण्य में मजबूत पार्टी का निर्माण करेंगे ! ग्राम पार्टी कमेटियों का निर्माण कर पार्टी को निचले स्तर से मजबूत बनाएंगे !

3) अ) समूचे दण्डकारण्य में प्लटूनों की संख्या बढ़ाएंगे ! पीजीए को मजबूत बनाएंगे ! बड़ी संख्या में भर्ती-कार्य चलाएंगे !

आ) दुश्मन से लड़कर हथियार हासिल करेंगे ! जन मिलिशिया और पीजीए को हथियारबंद करेंगे !

इ) सैद्धांतिक व राजनीतिक समझ बढ़ाकर सांगठनिक व फौजी कुशलता को बढ़ा लेंगे ! दुश्मन के हमले को हराएंगे !

4) सटे हुए इलाको में जनता की राजसत्ता के अंगों को मजबूत करेंगे !

5) राजनीतिक संघर्षों को महत्व देंगे। जनयुद्ध के संचालन के लिए जनता को राजनीतिक, सांगठनिक और फौजी तौर पर तैयार करेंगे !

आखिर में, अधिवेशन में उठाए गए कार्यभारों को पूरा करने के लिए दण्डकारण्य में समूची पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए 8 सदस्यों और एक वैकल्पिक सस्य वाली एसजेडसी पैनल को कॉ. भूपति ने पेश किया। सभी प्रतिनिधियों ने एकमत से कमेटी का चुनाव किया। उसके तुरन्त बाद नव निर्वाचित कमेटी ने कॉ. लच्छन्ना को सचिव के रूप में चुनकर हाल में उसकी घोषणा की।

सभी नव निर्वाचित कमेटी सदस्यों ने अधिवेशन में तय किए गए कार्यभारों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करने, दुश्मन के हमले को हराने के लिए कुरबानियों से न डरते हुए बहादुरी से लड़ने, पार्टी में उत्पन्न गैर-सर्वहारा रुझनों के खिलाफ लड़ने तथा शहीदों के उद्देश्यों को पूरा करने के *(शेष पृष्ठ 16 पर....)*

दक्षिण बस्तर डिवीजन का तीसरा अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न !

15 सितंबर 2000 से 22 सितंबर तक पार्टी का दक्षिण बस्तर डिवीजन अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न हुआ। हरे-भरे पेड़ों के घेरे में पहाड़ों के बीच, सुन्दर झीलों व झरनों के किनारे, प्रकृति की गोद में **'कोय्यूर शहीद कॅम्यून'** का निर्माण किया गया। डिवीजन के अलग-अलग इलाकों से प्रतिनिधि **'कोय्यूर शहीद कॅम्यून'** पहुंच गए।

कॅम्यून को लाल बन्दनवारों से सजाया गया। चारों तरफ मार्क्सवाद के महान शिक्षकों के उद्धरणों के पोस्टर और बैनर लगाए जाने से माहौल बड़ा आकर्षक दिखने लगा था। मुख्य-द्वार पर कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली के नाम लिखा एक बड़ा बैनर टांग दिया गया था जहां से **'कोय्यूर शहीद कॅम्यून'** में प्रवेश किया जा सकता था। कुछ आगे जाने पर `कॉ. विक्रम पहला डिफेन्स टेन्ट' था। उसे पार करने पर `धारकोण्डा शहीद टेन्ट' था जहां पर पहली प्लटून ने मुकाम किया। उससे लगकर ही शुरू होता था `कॉ. निर्मला मैदान'। मैदान से गुजरकर दूसरे सिरे पर जाने से वहां `कोटेनार शहीद दूसरा डिफेन्स टेन्ट' था। उसके नजदीक ही 'चन्द्रगिरी शहीद मेडिकल हॉल', `कॉ. प्रभाकर ग्रन्थालय', कॉ. सुब्बू किचेन हॉल' और उसके बगल में ही `कॉ. विश्वनाथ गोदाम' था। दाहिनी तरफ `तारलागूडेम शहीद अधिवेशन हॉल' था। कॅम्यून के सामने `कॉ. अनिल ए-संतरी पोस्ट' और पीछे की ओर `कॉ. रमेश बी-संतरी पोस्ट' में तैनात छापामारों ने दिन-रात पूरी सतर्कता बरतते हुए प्रतिनिधियों सहित कॅम्यून में मौजूद कुल 78 छापामारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी की।

फौजी वर्दियों और टोपियों से और कंधों पर बंदूकों से सजे हुए छापमार हाथों में प्लाकार्डों और बैनरों को, जिनमें नारे लिखे गए थे, लेकर 15 सितंबर की सुबह के 8-30 बजे कॉ. अनिल ए-संतरी पोस्ट के पास इकट्ठे हुए थे। वहां से गगनभेदी नारों से, क्रांतिकारी जोश से भरे माहौल में लाइनों में खड़े स्त्री-पुरुष छापामारों का जुलूस निकल पड़ा। जुलूस के सामने लाल झण्डा और उसके बाद एक बड़ा बैनर था जिस पर पार्टी के तीसरे अधिवेशन के बारे में लिखा गया। जुलूस के दौरान **"दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाएंगे !", "जनता की राजसत्ता कायम करेंगे!", "विश्व समाजवादी क्रांति जिन्दाबाद!", "सरकार के साझे हमले को हराएंगे!", "सभी किस्म का संशोधनवाद मुर्दाबाद!", "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!", "नव जनवादी क्रांति जिन्दाबाद!"** आदि नारे गोण्डी, हिन्दी और तेलुगु भाषाओं में जोर शोर से लगाए गए। जुलूस वहां से `कॉ. निर्मला ग्राउण्ड' पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगा।

`कॉ. निर्मला मैदान' में दक्षिण बस्तर डिवीजन सचिव कॉ. गोपन्ना ने लाल झण्डा फहराकर अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। तीन कतारों में खड़े प्रतिनिधियों और सुरक्षा-कॉमरेडों ने झण्डे को सलामी दी जबकि कॉ. सुब्बू ने गोण्डी में झण्डा गीत गाया। झण्डा फहराए जाने के बाद कॉ. गोपन्ना ने भाषण में दिया जिसमें उन्होंने लुटेरी सरकारों द्वारा अपनाई जा रही साम्राज्यवाद अनुकूल नीतियों के चलते देश में आर्थिक संकट किस तरह बढ़ रहा है, इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक अस्थिरता, जनता के सामने संघर्ष की अनिवार्य स्थिति, सरकारों द्वारा अमल पाशविक दमन आदि अनेक विषयों पर रोशनी डाली। अंत में उन्होंने हमारे व्यवहार में हुई खामियों और खूबियों की समीक्षा करना इस अधिवेशन का लक्ष्य बताकर सभी से सहयोग का आग्रह किया।

बाद में शहीदों की यादगार में निर्मित स्मारक का अनावरण कॉ. जमुना ने किया जो प्रतिनिधि के रूप में आई हुई थीं। कॉ. जमुना ने अपने भाषण में बताया कि 1995 से अब तक दक्षिण बस्तर में छह कॉमरेड और आन्ध्र, उत्तर तेलंगाना व बिहार में अनेक कॉमरेड शहीद हो गए। इनके अलावा हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता कॉ. श्याम, कॉ.महेश और कॉ. मुरली ने आखरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करते हुए अमरता को प्राप्त किया। उन्होंने सभी को चाहे कितनी ही मुश्किलें सामने आएं, शहीदों का मकसद पूरा करने के लिए दृढ़ता से लड़ने को कहा और नव जनवादी क्रांति को सफल बनाने को कहा।

कॉ.जमुना का भाषण समाप्त होते ही फिर एक बार शहीदों की याद में गगनभेदी नारे लगाए गए। शहीदों को श्रद्धांजली देने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद तमाम प्रतिनिधि **'तारलागूडेम शहीद अधिवेशन हाल'** की ओर चल पड़े। अधिवेशन हाल में एक ओर मार्क्सवाद के महान शिक्षकों की तसवीरें और एक तरफ हमारी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड चारु मजुमदार का चित्र और साथ ही, चारों तरफ बैनरों और पोस्टरों, जिन पर कई क्रांतिकारी नारे और उद्धरण लिखे गए थे, को लगाया गया। इस तरह **'तारलागूडेम शहीद अधिवेशन हाल'** बेहद आकर्षक और चारों तरफ क्रांतिकारी स्फूर्ति बिखेर रहा था।

अधिवेशन में 34 प्रतिनिधियों, दो प्रेक्षकों, एसजेडसी से एक कॉमरेड और केन्द्रीय कमेटी के दो कॉमरेडों ने भाग लिया। एक प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हो सके। डिवीजन सचिव ने सभी प्रतिनिधियों का परिचय करवाया और तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल और डीवीजनल कमेटी के सदस्यों को स्टीयरिंग कमेटी के रूप में प्रस्ताव रखा। प्रतिनिधियों ने तालियां बजाकर इसका अनुमोदन किया। और सभा-सत्र केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सायन्ना के उद्घाटन भाषण के साथ ही शुरू हो गया।

उन्होंने अपने भाषण में वर्तमान दीशीय और अन्तर्राष्ट्रीय हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदलने के फैसले पर अमल करने के लिए इस अधिवेशन पर

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अधिवेशन के सही फैसले करने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

अधिवेशन ने सबसे पहले शहीदों को लाल सलाम पेश करते हुए तथा जेलों में रहकर भी संघर्ष का परचम ऊंचा उठाए रखे हुए कॉमरेडों और नित्य दमन के बावजूद पार्टी का आंख की पुतली के समान बचाव कर रही जनता को क्रांतिकारी बधाई देते हुए प्रस्ताव किए। और उसके बाद, 4 दिनों तक चली चर्चाओं के बाद पार्टी दस्तावेजों को अधिवेशन ने कुछ संशोधनों के साथ पारित किया।

20 तारीख को आत्मालोचना-आलोचना को दौर चला। पुरानी डिवीजनल कमेटी ने समीक्षा के अन्दर ही अपनी आत्मालोचना पेश की, यह बात प्रतिनिधियों को याद दिलाई गई। डिवीजनल कमेटी सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर आत्मालोचना पेश की। प्रतिनिधियों ने उनकी आलोचना की और सम्बन्धित कॉमरेडों ने उसका उत्तर दिया। नेतृत्व की आत्मालोचना और जवाबों से अधिवेशन संतुष्ट हो गया दस्तावेजों पर चर्चाओं और आत्मालोचना-आलोचना के दौरान हाल में शुरू से लेकर आखिरी तक कॉमरेडाना सम्बन्ध और भी मजबूत हो गए।

21 तारीख की सुबह के सत्र में केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सायन्ना ने नई कमेटी के चयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय कमेटी की समझ पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने मौजूद कार्यभारों को देखते हुए दक्षिण बस्तर डिवीजन को दो भागों - दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर डिवीजनों - में बांटने की जरूरत है और दोनों डिवीजनों का नेतृत्व करने के लिए अधिवेशन को दो सक्षम कमेटियों का चुनाव करना चाहिए।

बाद में पुरानी डिवीजनल कमेटी के सचिव ने इस सम्बन्ध में डिवीजनल कमेटी द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में बताया। और दक्षिण बस्तर के लिए चार सदस्यों और पश्चिम बस्तर के लिए तीन सदस्यों और एक वैकल्पिक सदस्य का प्रस्ताव रखा। सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का एकमत से अनुमोदन किया। और नव निर्वाचित कमेटियों ने अलग-अलग बैठकें करके अपने सचिवों का चुनाव किया और अधिवेशन को बताया। दण्डकारण्य अधिवेशन में भाग लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी ने 7 सदस्यों वाले प्रतिनिधिण्डल का प्रस्ताव रखा जिसका अधिवेशन ने अनुमोदन किया।

उसके बाद के सत्र में अधिवेशन ने डिवीजन, राज्य और देश के हालात का जायजा लेते हुए निम्नलिखित पांच प्रस्ताव किए।

1) 1 नवंबर को गठित होने जा रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर के विलय के खिलाफ 25 अक्टूबर को डिवीजन भर में जनता को बड़े पैमाने पर लामबंद करके रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाए। "अलग जनवादी बस्तर" राज्य की मांग पर जनता को और दूसरी दोस्ताना ताकतों को गोलबंद करके संघर्ष किया जाए।

2) `साझा समन्वय केन्द्र' की अगुवाई में केन्द्र - राज्य सरकारों द्वारा आन्दोलन के खिलाफ छेड़े गए साझे हमले को हरा दिया जाए। जनता, जन संगठन, जन मिलिशिया और ग्राम राज्य कमेटियां दुश्मन का मुकाबला कर सके, इसके लिए पार्टी को उन्हें पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए।

3) बैलाडीला की 11वीं खदान का निजीकरण करते हुए सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर विरोधी नीतियों का जनता में पर्दाफाश करना चाहिए।

4) देश में बढ़ रहे जन संघर्षों पर लुटेरे शसक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे पाशविक दमनचक्र की निंदा करके, जनता में उनके वर्गीय चरित्र को नंगा कर देना चाहिए।

5) राष्ट्रीयताओं के बहादुराना संघर्षों पर सैन्य और पुलिस बलों द्वारा किए जा रहे कत्लेआमों की अधिवेशन ने भर्त्सना की।

आखिरी सत्र में, पार्टी सचिव कॉ. गणपति ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुक्त इलाके के तहत आगे बढ़ रहे इस डिवीजन में हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जन संघर्ष, हजारों की संख्या में जनता का गोलबंद होना, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी, मजबूत हो रहे जनता की राजसत्ता के अंग, बढ़ रही भर्तियां आदि समूची पार्टी को उत्साहित कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने डिवीजन आन्दोलन की कमजोरियों पर रोशनी डालते हुए उन्हें दूर करने पर बात रखी। उन्होंने आगे कहा कि जब हालात हमारे लिए अनुकूल होंगे तभी आत्मगत ताकतों को बढ़ा लेना चाहिए। आने वाले साझे हमले का कम से कम नुकसानों और कम से कम गलतियों से सामना करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर असामान्य कुरबानियां देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।

अगले दिन, 22 सितंबर को केन्द्रीय कमेटी द्वारा भेजे गए सरकुलर पर अधिवेशन में विस्तृत चर्चा की गई जिसमें `संयुक्त हमले को हराने' का आह्वान किया गया। बाद में एसजेडसी सचिवमण्डल सदस्य कॉ. लच्छन्ना ने उस सरकुलर की रोशनी में अपनाए जाने वाले कार्यभारों के बारे में सभी प्रतिनिधियों को अवगत कराया।

इस तरह, अधिवेशन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जैसे ही सभा-सत्र पूरा हुआ, सभी प्रतिनिधियों ने बाकी छापामारों के साथ मिलकर `तारलागूडेम शहीद अधिवेशन हाल' से `कॉ. निर्मला पेरेड ग्राउण्ड' तक जुलूस निकाला। जुलूस में गगनभेदी नारे लगाए गए जिनमें अधिवेशन में तय किए गए नारे प्रमुख थे। झण्डे के सामने कॅम्यून के सभी लोग तीन कतारों में खड़े हो गए। डिवीजनल कमेटी सचिव ने नव निर्वाचित कमेटियों का परिचय करवाया और उन्हें शपथ दिलवाई। उसके बाद दोनों कमेटियों के सचिवों ने अपने भाषणों में अधिवेशन द्वारा तय किए फैसलों और नारों पर अमल करने में अपनी दृढ़ निश्चयता दोहराई। अन्तर्राष्ट्रीय गीत गाकर झण्डा उतारा गया और सभी प्रतिनिधि नए कार्यभारों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अपने-अपने इलाकों की ओर चल पड़े। ✪

माड़ डिवीजन का पहला अधिवेशन कामयाबी के साथ संपन्न!

माड़ डिवीजन घने जंगलों और पहाड़ियों से भरा इलाका है जहां की जनता को परालकोट विद्रोह (1825), महान भुमकाल (1910) जैसी शानदार बगावतों का बहादुराना इतिहास है। पिछले 13 सालों से इस इलाके में क्रांतिकारी आन्दोलन की गतिविधियां जारी हैं। 1999 तक यह इलाका बस्तर और गड़चिरोली डिवीजनों में शामिल था। 1999 के जुलाई माह में पार्टी ने इस इलाके के आन्दोलन को एक नए डिवीजन का रूप दिया। 1999 में आयोजित पार्टी की एक विशेष प्लीनम ने डीवीजनल कमेटी को चुन लिया और वही तब से आन्दोलन का नेतृत्व करती आ रही थी। 22 अक्टूबर 2000 से माड़ डिवीजन के किसी स्थान पर बने **'कोय्यूर शहीद कॅम्यून'** में नव गठित माड़ डिवीजन का सर्वप्रथम अधिवेशन क्रांतिकारी उत्साह के साथ शुरू हुआ।

अधिवेशन में भाग लेने के लिए सभी प्रतिनिधि पहले से तय स्थान पर इकट्ठे हो गए। डिवीजन के सभी छापामार दस्ते इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित थे और दुश्मन के संभावित हमले का मुकाबला करने के लिए सभी फौजी तैयारियां पहले ही की गईं थीं। अधिवेशन के पूरे स्थल को `कोय्यूर शहीद कॅम्यून' का नाम रखा गया और वहां दो प्लाटूनों में विभाजित छापामारों के ठहरने के अलग-अलग स्थानों तथा अन्य स्थानों को अलग-अलग शहीदों के नाम रखे गए। कॉ. अखिला - कॉ. लक्ष्मी टेन्ट, कॉ. राजे मेडिकल टेन्ट, जारावाडा शहीद किचेन, कॉ. विक्रम पेरेड ग्राउण्ड, कोटेनार शहीद अधिवेशन हाल, ताल्लागूडेम शहीद द्वार, धीरी-मुरुम शहीद सांस्कृतिक मंच, कॉ. निर्मला ए-संतरी पोस्ट, कॉ. राकेश बी-संतरी पोस्ट आदि नाम रखकर शहीदों को याद किया गया।

22 तारीख की सुबह के 10-30 बजे डिवीजनल कमेटी सचिव कॉ. कोसा ने झण्डात्तोलन किया और इसके साथ ही अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन हो गया। झण्डा गीत के बाद वहां कतारबद्ध होकर खड़े हुए प्रतिनिधियों और छापामारों को संबोधित करते हुए कॉ. कोसा ने भाषण दिया। उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से माड़ डिवीजन के सामरिक महत्व के बारे में बात रखी और यहां के आन्दोलन के विकास के बारे में विस्तारपर्वक बताया। डिवीजन आन्दोलन को आगे बढ़ाने में बाधा बनी हुई कमजोरियों को दूर करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। और आत्मगत ताकतों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए यह अधिवेशन सही फैसले लेगा, यह आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

बाद में शहीदों की याद में निर्मित स्मारक का अनावरण कॉ. भीमन्ना ने किया। सभी उपस्थित साथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजली दी। बाद में उन्होंने अपने भाषण में माड़ डिवीजन आन्दोलन को आगे बढ़ाने में शहीद साथियों के योगदान के बारे में बताया। साथ ही, उन्होंने आन्ध्र, उत्तर तेलंगाना, बिहार और दण्डकारण्य के तमाम शहीदों, विशेष रूप से केन्द्रीय कमेटी नेता कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुरबानियों से ही आन्दोलन कई उपलब्धियां हासिल कर सका है। उन्होंने शहीद साथियों के अधूरे मकसद को पूरा करने का संकल्प लेने पर जोर दिया।

उनका भाषण समाप्त होते ही लगाए नारों से सारा जंगल गूंज उठा। और कॉ. विक्रम मैदान में उद्घाटन समारोह ने एक जुलूस का रूप लिया। डिवीजनल कमेटी सदस्यों ने सबके आगे रहकर जुलूस की अगुवाई की। और डिवीजन सचिव कॉ. कोसा हाथ में पार्टी का झण्डा लेकर आगे चलने लगे थे।

गगनभेदी नारों और क्रांति के गीतों से चल पड़ा यह जुलूस `कोटेनार शहीद अधिवेशन हाल' पहुंचा। `ताल्लागूडेम शहीद द्वार' के पास अधिवेशन के प्रतिनिधि खड़े हो गए और सुरक्षा कॉमरेड अपने-अपने कामों पर चल पड़े। डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉ. पाण्डू ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। प्रतिनिधि-सत्र की शुरूआत अध्यक्षमण्डल और स्टीयरिंग कमेटी के चुनाव के साथ हुई। डिवीजन सचिव कॉ. कोसा ने कॉ. जूरी, कॉ. राधा और कॉ. राजमन को अध्यक्षमण्डल के तौर पर, और कॉ. कोसा, कॉ. किरण, कॉ. पाण्डू और कॉ. सैनू को स्टीयरिंग कमेटी के तौर पर प्रस्तावित किया तो सभी प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ इसका अनुमोदन किया।

अध्यक्ष के आग्रह पर एसजेडसी सचिव कॉ. भूपति ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने नव गठित माड़ डिवीजन के सर्वप्रथम अधिवेशन में भाग लेने आए प्रतिनिधियों को क्रांतिकारी बधाई दी। उन्होंने केन्द्रीय कमेटी द्वारा लिए गए पीजीए की स्थापना और दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में विकसित करने के लक्ष्य से काम करने के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि दण्डकारण्य में मौजूद सामरिक महत्व के इलाकों में माड़ डिवीजन एक है। उन्होंने कहा कि इस डिवीजन के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहां के पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। उहोंने यह आशा जताते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि पार्टी के केन्द्रीय नारे के तहत ही यह अधिवेशन सही फैसले करेगा।

बाद के सत्र में, स्टीयरिंग कमेटी की ओर से कॉ. किरण ने शहीदों को श्रद्धांजली का प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन में शहीद हुए सभी साथियों, विशेषकर माड़ डिवीजन के आन्दोलन में काम करके शहीद हुए कॉमरेडों - कॉ. प्रभाकर (जांबरी), कॉ. श्रीकान्त, कॉ.राकेश, कॉ. सोमन्ना, कॉ. सबिता, कॉ. कविता, कॉ. गुड्सा, कॉ. राजे, कॉ. लिंगा

(समर्थक) और कॉ. धनीराम कौडो (जन संगठन सदस्य) - को तथा भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देने वाले कॉमरेडों - श्याम, महेश और मुरली - को श्रद्धांजली दी गई। `शहीदों को लाल सलाम', `शहीदों का मकसद पूरा करेंगे' आदि नारे लगाकर सभी प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को पारित किया।

बाद में पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों, क्रमशः कार्यक्रम, संविधान, रणनीति-कार्यनीति, गुरिल्ला जोन - हमारा परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक प्रस्ताव और वित्तीय नीति को एक के बाद एक पेश किया गया। स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों ने इन दस्तावेजों को परिचयपूर्वक पेश किया। दण्डकारण्य की राजनीतिक - सांगठनिक समीक्षा और माड़ डिवीजन की सांगठनिक समीक्षा पेश की गईं। प्रतिनिधियों ने एक-एक दस्तावेज पर संशोधन सुझाए थे जिनमें से कुछ को अगले उच्च अधिवेशन में ले जाने का प्रस्ताव किया गया और कुछ के बारे में स्टीयरिंग कमेटी के दिए विवरण से प्रतिनिधि संतुष्ट हो गए। सभी दस्तावेजों को संशोधनों के साथ पारित किया गया। इन बहसों और विवरणों को देने के दौरान अधिवेशन हाल में जनवादी केन्द्रीयता पर संपूर्ण अमल किया गया। कॉमरेडों के बीच कॉमरेडाना संबंध और भी सुदृढ़ हो गए।

आखिर में पुरानी डिवीजनल कमेटी ने कमेटी के तौर पर और सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर आत्मालोचना पेश की। प्रतिनिधियों ने नेतृत्व की आत्मालोचना का स्वागत किया। डिवीजन के आन्दोलन को आगे बढ़ाने और अधिवेशन के फैसलों व कार्यभारों को पूरा करने के लिए डिवीजनल कमेटी को चुनने के लिए एसजेडसी सचिव कॉ. भूपति ने चार सदस्यों का पैनल पेश किया। प्रतिनिधियों ने एक मत से उस पैनल का चुनाव किया जिसमें तीन पुराने सदस्य थे। नव निर्वाचित डिवीजनल कमेटी ने तुरंत ही बैठक करके कॉ. कोसा को दोबारा सचिव चुन लिया।

इसके साथ ही अधिवेशन का सभा-सत्र समाप्त हो गया। अगले दिन 26 तारीख की सुबह कॉ. विक्रम मैदान में अधिवेशन का विधिवत समापन हुआ। कॅम्यून में मौजूद सभी कामरेडों ने नारे लगाते हुए कोटेनार शहीद अधिवेशन हाल से कॉ. विक्रम ग्राउण्ड तक जुलूस निकाला। फौजी वर्दियों में सज-धजकर सभी प्रतिनिधि और सुरक्षा-छापामार झण्डे के सामने कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। सबसे पहले एसजेडसी सचिव कॉ. भूपति ने नव निर्वाचित डिवीजनल कमेटी से शपथ-ग्रहण करवाई। और डिवीजन सचिव ने वहां उपस्थित सभी पार्टा सदस्यों को शपथ दिलवाई। सभी पार्टी सदस्यों ने अधिवेशन के फैसलों पर दृढ़ता से अमल करने की शपथ ली। बाद में कॉ. कोसा ने अपने भाषण में अधिवेशन के फैसलों और नारों के बारे में बताया।

उनमें से प्रमुख है :

1) आत्मगत ताकतों को बढ़ाएंगे। स्थानीय नेतृत्व को विकसित करेंगे।
2) जनता की राजसत्ता के अंगों का निर्माण करेंगे। पार्टी निर्माण को मजबूत करेंगे।
3) गांव-गांव में मिलिशिया का निर्माण करेंगे और पीजीए को मजबूत करेंगे।
4) गैर-सर्वहारा रुझानों के खिलाफ लड़ेंगे।

और कॉ. कोसा ने देश की और विश्व की वर्तामान परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि चारों तरफ क्रांति के लिए अनुकूल माहौल है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करना जरूरी बताया। अंत में अंतर्राष्ट्रीय गीत गाया गया और झण्डा उतारा गया। ✪

(.... पृष्ठ 12 का शेष)

लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की शपथ ली।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम एसजेडसी सचिव कॉ. लच्छन्ना ने प्रस्तावित किया, तो हाल ने उसका अनुमोदन किया।

समय का पालन करते हुए एजेन्डे के अंशों पर गहराई से विश्लेषण कर दस्तावेजों को चर्चा के जरिए समृद्ध बनाने और अधिवेशन के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान करने वाले सभी प्रतिनिधियों को अध्यक्षमण्डल ने धन्यवाद दिया। आखिर में, सभी प्रतिनिधियों ने शपथ-ग्रहण की।

पृथक जनवादी बस्तर और पृथक विदर्भ राज्यों के गठन की मांग करते हुए; देश भर में जारी विभिन्न तबकों की हड़तालों का समर्थन करते हुए; उन हड़तालों का सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष से तालमेल करने का आह्वान करते हुए; अल्पसंख्यकों पर संघ परिवार और राजग सरकार के हमलों की भर्त्सना करते हुए; पूर्वोत्तर के राज्यों और कश्मीर में बहादुरी से लड़ रही राष्ट्रीयताओं को बधाई देते हुए; क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ भारत के शासक वर्गों द्वारा छेड़े गए तीसरे दमन अभियान का मुकाबला रते हुए उसे हराने का जनता से आह्वान करते हुए अधिवेशन ने अनेक प्रस्ताव किए।

23 दिसंबर की शाम को तीसरे अधिवेशन का औपचारिक समापन कॉ. विक्रम मैदान में हुआ जहां क्रांतिकारी उत्साह के साथ प्रतिनिधि और पीजीए के छापामार दोबारा इकट्ठा हो गए। नए सचिव कॉ. लच्छन्ना ने नव निर्वाचित कमेटी का परिचय करते हुए अधिवेशन में तय मुख्य कार्यभार पर अमल करते हुए साहस के साथ लड़ने, दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदलने के लक्ष्य से पार्टी के नेतृत्व में पीजीए, जन संगठनों और जनता को एकजुट होकर लड़ने का आह्वान के साथ अपना भाषण समाप्त किया। उनके भाषण समाप्त होते ही "दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदल दो" का नारा गूंज उठा। "इंटरनेशनल" के सामूहिक गायन के साथ ही अधिवेशन का समापन समारोह पूरा हो गया। ✪

उत्तर बस्तर डिवीजन का तीसरा अधिवेशन क्रांतिकारी जोशोखरोश के साथ संपन्न !

उत्तर बस्तर डिवीजन का तीसरा अधिवेशन 3 नवंबर 2000 से 7 नवंबर तक संपन्न हुआ। इसमें कुल 21 प्रतिनिधियों और डिवीजनल कमेटी के दो सदस्यों और एसजेडसी से दो कॉमरेडों ने भाग लिया। इनके अलावा अधिवेशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अलग-अलग दस्तों से कई छापामार भी वहां आए थे।

3 तारीख की सुबह सभी प्रतिनिधियों और सुरक्षा ग्रुप के छापामारों ने हाथों में बैनर और प्लैकार्ड लेकर `ताल्लागूडेम शहीद मुख्य-द्वार' से जुलूस निकाला। डिवीजन के सचिव कॉ. सुखदेव ने हाथों में पार्टी का झण्डा लेकर जुलूस का नेतृत्व किया। यह जुलूस `कोय्यूर शहीद नगर' के मुख्य स्थानों से होता हुआ `कॉ. फुलवती पेरेड ग्राउण्ड' पहुंच गया। जुलूस के दौरान **"जन छापामार सेना जिन्दाबाद!", "दण्डकारण्य आधार इलाका बनाएंगे!", "भाकपा (माले) (पीपुल्स वार) जिन्दाबाद!", "मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा जिन्दाबाद!", "सभी किस्म का संशोधनवाद मुर्दाबाद!", "शहीदों के सपनों को साकार बनाएंगे!"** आदि गगनभेदी नारे लगाए गए। विशेष तौर पर कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली को तथा ताल्लगूडेम शहीदों को, दण्डकारण्य और उत्तर बस्तर के शहीदों को लाल सलाम करते हुए नारे लगाए गए। बीच-बीच में रुककर पीजीए का गीत - ***"पीपुल्स वार ता लाल फौज....."*** गाया गया।

बाद में सभी लोग कतारबद्ध होकर खड़े हो गए, तो कॉ. सुखदेव ने पार्टी का झण्डा फहराया। उसके बाद सभी ने झण्डे का अभिवादन किया और कॉ. रामदेर ने झण्डा गीत पेश किया। उसके बाद कॉ. सुखदेव ने अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन करते हुए भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में पिछले 5 सालों के दौरान आन्दोलन में आए उतार-चढ़ावों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 1995 के अधिवेशन के समय डिवीजन में कुल तीन दस्ते थे और कुल सदस्यों की संख्या 26 थी, लेकिन अब चार दस्ते और एक स्पेशल छापामार दस्ता और कुल संख्या 55 तक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि हमारे शहीदों की कुरबानी के बदौलत ही तथा डिवीजन की पार्टी-श्रेणियों, जन संगठनों और जनता की मेहनत के बदौलत ही हासिल की गई। उन्होंने डिवीजन में डीएकेएमएस, केएएमएस, बाल संगठन, सहकारी संगठन आदि के विकासक्रम के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि एसजेडसी के मार्गदर्शन में कुछ गांवों में ग्राम राज्य कमेटियों का निर्माण किया गया और ग्राम रक्षा दस्तों और पार्टी सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है।

आगे उन्होंने डिवीजन भर में चलाए गए जन संघर्षों का ब्यौरा देते हुए उनमें जनता द्वारा हासिल प्रमुख उपलब्धियों और उनमें हुई मुख्य गलतियों के बारे में बताया। नेतृत्व प्रदान करने में डिवीजनल कमेटी की ओर से हुई गलतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कमेटी के अंदर मौजूद उदारतावाद, व्यक्तिगत काम का तरीका, स्वतःस्फूर्तता आदि गैर-सर्वहारा रुझानों के चलते काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि कमेटी इन कमजोरियों से उबरने की कोशिश करेगी।

बाद में कॅम्यून के सारे लोगों ने शहीदों की याद में निर्मित स्मारक के सामने कतारों में खड़े हो गए। शहीदों के नाम पर लगाए जाने वाले गगनभेदी नारों के बीच कॉ. पद्मा ने स्मारक का अनावरण किया। उन्होंने एक-एक शहीद का नाम लेते हुए उनके इतिहास पर रोशनी डालते हुए उनके मकसद पूरे करने के लिए प्रण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिवीजन में हुए आन्दोलन के विकास में शहीदों की कुरबानियों का बहुत बड़ा स्थान है। कॉ. पद्मा के भाषण के बाद शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट की खामोशी पेश की गई। उसके बाद कॉ. मंगडू ने शहीद गीत प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभा दोबारा जुलूस में परिवर्तित हुई और अधिवेशन हाल तक यह जुलूस नारों और गीतों के साथ बढ़ा। अधिवेशन हाल के द्वार से सुरक्षा जिम्मेदारी पर आए हुए छापामार अपने-अपने काम पर चल पड़े, जबकि प्रतिनिधिगण हाल में दाखिल हुए।

डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉ. दसरू ने प्रतिनिधियों और उच्च कमेटी के सदस्यों का स्वागत किया। बाद में सभा-सत्र नाश्ता के लिए स्थगित किया गया। फिर 9-30 बजे से शुरू होने वाले सत्र में पहले डिवीजन सचिव ने एजेन्डा पेश किया और अधिवेशन के सुचारू संचालन के लिए एक तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल तथा डिवीजनल कमेटी के दो कॉमरेडों को बतौर स्टीयरिंग कमेटी का प्रस्ताव रखा, तो अधिवेशन ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

अध्यक्ष के आमंत्रण पर एसजेडसी सचिव कॉ. भूपति ने अधिवेशन में उद्घाटन भाषण दिया। कॉ. भूपति ने अपने भाषण में पार्टी द्वारा हाल ही में लिए गए पीजीए की स्थापना और दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाने के लक्ष्य से काम करने के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिवेशन को इस केन्द्रीय कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए समुचित कार्यभारों को तय करना होगा। उन्होने पिछले 5 सालों में दण्डकारण्य आन्दोलन द्वारा हासिल उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारी कमजोरियों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करते हुए दण्डकारण्य को मुक्त अंचल में बदलने के लिए सभी पार्टी कतारों को कोशिश करनी चाहिए।

अगले सत्र में कॉ. दसरू ने शहीदों को लाल सलाम पेश करते हुए अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा। भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन में विभिन्न राज्यों में शहीद हो चुके कॉमरेडों, विशेष रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन के शहीदों को याद करते हुए प्रस्ताव में श्रद्धांजली पेश की गई। सभी प्रतिनिधियों ने `शहीदों को जोहार' कहते हुए नारे लगाकर प्रस्ताव को पारित *(शेष पृष्ठ 19 पर....)*

भीषण शत्रु-दमन के बीच गड़चिरोली डिवीजन का तीसरा पार्टी अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न!

दुश्मन के खोजबीन अभियानों के बीच, कमाण्डो बलों की छापेमारियों के बीच ही गड़चिरोली डिवीजन का तीसरा पार्टी अधिवेशन 9 से 12 नवंबर 2000 के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जनता के सक्रिय सहयोग से और छापामारों की कड़ी चौकसी से ही यह संभव हो सका। इस अधिवेशन में दस्ता एरिया कमेटी सचिवों, सदस्यों और तकनीकी विभाग के पांच सदस्यों ने प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया, जबकि एसजेडसी के दो सदस्यों, एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य और प्रेक्षक के रूप में बालाघाट से एक डिवीजनल कमेटी सदस्य ने भी भाग लिया।

'शहीद विक्रम ग्राउण्ड' में 9 नवंबर की सुबह के 9 बजे सुरक्षा छापामार और प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए। सबके कतारबद्ध होने के बाद डिवीजन सचिव कॉ. विकास ने झण्डा फहराया। `झण्डा गीत' के बाद सचिव ने पिछले पांच सालों में डिवीजन आन्दोलन में आए उतार-चढ़ावों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। बाद में सारे कॉमरेड हाथों में झण्डे और बैनर लेकर क्रांति के नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में `कॉ. दीपक अधिवेशन हाल' के पास पहुंचे। हाल के सामने निर्मित शहीद स्मारक का अनावरण कॉ. अशोक ने किया। शहीदों की याद में समूची कॅम्यून ने दो मिनट की खामोशी पेश करके श्रद्धांजली दी। और वहां से सुरक्षा छापामार अपने-अपने काम पर चले गए तो प्रतिनिधिगण अधिवेशन हाल में दाखिल हो गए।

डीवीसी सदस्या कॉ. नर्मदा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बाद में अधिवेशन के सुचारू संचालन के लिए तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल को एकमत से चुन लिया गया। हाल की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए डिवीजनल कमेटी के चार कॉमरेडों को स्टीयरिंग कमेटी के तौर पर अधिवेशन ने स्वीकार किया।

अध्यक्षमण्डल ने अधिवेशन के सामने एजेन्डा पेश किया, तो प्रतिनिधियों ने उसका अनुमोदन किया। सभा-सत्र की शुरूआत केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सायन्ना के उद्घाटन-भाषण के साथ हुई। कॉ. सायन्ना ने अपने भाषण में मौजूदा देशीय-अंतर्राष्ट्रीय हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि क्रांति के लिए हालात दिन-ब-दिन अनुकूल बनते जा रहे हैं। उन्होंने साम्राज्यवाद के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि संकट के चलते ही पिछड़े देशों में भूमण्डलीकरण जैसी नीतियां लादी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि साम्राज्यवाद निर्देशित नीतियों के चलते जनता का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है और हर तरफ इन नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ विभिन्न तबकों की जनता लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए जनता का नेतृत्व करने के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की जरूरत है। उन्होंने हमारी पार्टी की उपलब्धियों और विफलताओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि अपनी खामियों को दूर करने से हमारा आन्दोलन और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकेगा। आखिर में उन्होंने यह आशा करते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि यह अधिवेशन आन्दोलन को और भी तेज करने के लिए जरूरी फैसले करेगा।

बाद में एक-एक बुनियादी दस्तावेज पर हुई बहस के बाद कुछ संशोधनों के साथ अधिवेशन ने उन्हें पारित किया। डिवीजन की समीक्षा में प्रतिनिधियों ने कई संशोधन करके उसे और भी समृद्ध बनाया।

आखिरी सत्र में पुरानी डिवीजनल कमेटी ने आत्मालोचना पेश की। और आत्मालोचना-आलोचना के बाद प्रतिनिधियों ने नई कमेटी का चयन किया। 5 सदस्यों की कमेटी के अलावा, एक वैकल्पिक सदस्य को भी चुन लिया गया। नव निर्वाचित कमेटी ने कॉ. विकास को दोबारा अपना सचिव चुन लिया। सभी प्रतिनिधियों के शपथ-ग्रहण करने के साथ ही सभा-सत्र का समापन हुआ।

आखिर में कॉ. दीपक अधिवेशन हाल से कॉ. विक्रम ग्राउण्ड तक सभी प्रतिनिधियों और सुरक्षा छापामारों ने जुलूस निकाला। झण्डे के सामने नव निर्वाचित कमेटी का परिचय करवाया गया। कॉ. गौतम ने समापन भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में अधिवेशन द्वारा निर्धारित फौरी कार्यभारों का ब्यौरा देते हुए सभी से इन पर दृढ़ता से अमल करने का आह्वान किया। उन्होंने दुश्मन की चुनौती को स्वीकारते हुए साहस के साथ लड़ते हुए डिवीजन आन्दोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उनके भाषण के बाद `अंतर्राष्ट्रीय गीत' गाकर झण्डा उतारा गया।

अधिवेशन द्वारा निर्धारित फौरी कार्यभार :

1) एरिया कमेटियों का सैद्धांतिक-राजनीतिक स्तर ऊंचा करके उन्हें एरिया स्तर के आन्दोलन का नेतृत्व कर सकने वाली मजबूत कमेटियों के तौर पर विकसित किया जाए।

2) कमेटियों में जनवादी केन्द्रीयता और सामूहिक काम तरीका लागू किए जाएं।

3) स्थानीय आदिवासी कॉमरेडों और महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाए।

4) नियमित प्रशिक्षण के जरिए दस्तों की फौजी कुशलता बढ़ा दी जाए।

5) दुश्मन की बदलती कार्यनीति का अध्ययन करते हुए, उसके बलों पर प्रहार किए जाएं। फौजी कार्यभारों को पूरा करने के लिए विशेष छापामार दस्ते का निर्माण किया जाए।

6) आन्दोलन के बढ़ते कार्यभारों के मद्देनजर भर्ती को बढ़ा

दी जाए। दुश्मन द्वारा अपनाई जा रही `कोवर्ट वार' (छिपी लड़ाई) के दावपेंचों को मात दी जाए।

7) स्थानीय तौर पर पार्टी के निर्माण पर केन्द्रित करना चाहिए। जन संगठनों की रेन्ज/जिला कमेटियों को सुचारू ढंग से संचालित करते हुए उनकी सदस्यता व्यापक स्तर पर बढ़ा दी जाए।

8) सभी गांवों पर संगठनों और पार्टी की पकड़ मजबूत करते हुए, मजबूत गांवों से शुरू करके सिलसिलेवार गांव-गांव में ग्राम राज्य कमेटियों का निर्माण किया जाए।

9) जीआरडी/एआरडी का निर्माण बड़े पैमाने पर बढ़ाकर उनके नेतृत्व में जन-प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए।

10) बड़े गांवों पर, छात्र-कर्मचारियों पर तथा महिलाओं पर काम को केन्द्रित किया जाए।

11) संघर्षों में जनता की भूमिका बढ़ाई जाए। आंशिक संघर्षों को राजनीतिक संघर्षों की तरफ, अंतिम रूप से राजसत्ता छीन लेने की तरफ मोड़ दिया जाए।

12) सरकार के झूठे सुधारों की ढोंगबाजी का जनता में पर्दाफाश करते हुए दुश्मन द्वारा जारी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। गांव-गांव में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य से विकास और कल्याण कार्यक्रम अपनाए जाएं।

13) सहकारिता आन्दोलन को तेज किया जाए।

14) पार्टी और हथियारबंद दस्तों का उन्मूलन करके क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के इरादे से केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा छेड़े गए आक्रमण-अभियान को हराने के लिए साहस के साथ लड़ाई की जाए। अतीत में हुए आक्रमण अभियानों के कड़वे अनुभवों से सबक सीखते हुए गलतियां सुधार ली जाएं।

15) डिवीजन स्तर पर सांस्कृतिक संगठनों का गठन करने का प्रयास किया जाए ताकि साम्राज्यवादी एवं सामंती-पितृशाही संस्कृति का मुकाबला करते हुए जनवादी संस्कृति कायम की जाए।

16) नई वन नीति का विरोध करते हुए, `जंगल पर अधिकार आदिवासियों को' के नारे तहत संघर्ष किए जाएं।

नारे

* स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाओ - एरिया कमेटियों को मजबूत करो !
* स्थानीय स्तर पर मजबूत पार्टी का निर्माण करो - आत्मगत ताकतों को बढ़ाओ !
* ग्राम राज्य कमेटियों का निर्माण करो - गांव-गांव में उत्पीड़ित जनता की राजसत्ता कायम करो !
* जन मिलिशिया का निर्माण करो - प्रतिरोध में जनता की भूमिका बढ़ाओ !
* आधार इलाकों का निर्माण करो - मुक्त इलाकों की स्थापना के लिए नींव रखो !
* साहस के साथ लड़ो - सरकारी हमले को हरा दो ! ❖

(.... पृष्ठ 17 का शेष)

किया। बाद में अधिवेशन ने जेल में बंदी बनाए गए कॉमरेडों की रिहाई की मांग करते हुए तथा अधिवेशन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

अधिवेशन ने पार्टी के बुनियादी दस्तावेजों पर गहरी चर्चा के बाद कुछ संशोधनों के साथ उन्हें पारित किया। और संशोधनों को दण्डकारण्य अधिवेशन में चर्चा के लिए पेश करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, दण्डकारण्य राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षा और डिवीजन की सांगठनिक समीक्षा पर भी प्रतिनिधियों ने चर्चा करके उनमें कई संशोधन करके और भी समृद्ध बनाया।

नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अधिवेशन ने एक प्रस्ताव किया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का स्वागत करते हुए ही उसमें विशाल बस्तर के विलय का विरोध किया गया। अधिवेशन ने माना कि बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा कभी नहीं रहा। साथ ही, बस्तर की जनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए `अलग जनवादी बस्तर' राज्य का गठन जरूरी मानते हुए अधिवेशन ने इस मांग पर मजदूर-किसानों, छात्र-बुद्धिजीवियों का समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी स्वीकार की।

अधिवेशन ने डिवीजन आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए तीन सदस्यों की नई डिवीजनल कमेटी चुन ली। नव निर्वाचित डिवीजनल कमेटी ने कॉ. दसरू को सचिव चुन लिया। दण्डकारण्य के तीसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए अधिवेशन ने तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भी चुन लिया। और इसके साथ ही अधिवेशन का सभा-सत्र संपन्न हुआ।

आखिर में, सभी प्रतिनिधियों और अन्य कॉमरेडों ने नारे लगाते हुए `कॉ. निर्मला अधिवेशन हाल' से `कॉ. फुलवती ग्राउण्ड' तक जुलूस निकाला। कतारबद्ध होकर खड़े कॅम्यून के सभी सदस्यों को नव निर्वाचित डिवीजनल कमेटी का परिचय करवाया गया। बाद में नए सचिव कॉ. दसरू ने सभी पार्टी सदस्यों से शपथ दिलवाई।

अधिवेशन में निर्धारित कार्यभार

1) उदारतावाद, व्यक्तिगत काम तरीका, स्वतःस्फूर्तता, अर्थवाद आदि गैर-सर्वहारा भटकावों के खिलाफ लड़ो!
2) एरिया कमेटियों को राजनीतिक तौर पर विकसित करते हुए वर्ग संघर्ष को तेज करेंगे!
3) पार्टी संगठनों को व्यापक बनाकर जनता की राजसत्ता के अंगों का निर्माण करेंगे!
4) भर्तियों को बढ़ा लेंगे! जन छापामार सेना को मजबूत करेंगे!
5) जन मिलिशिया को मजबूत करेंगे! जनयुद्ध को विकसित करेंगे! ✪

श्रद्धांजली

कॉमरेड विनय हमारे दिलों में सदा अमर रहेगा!

*[1994 में मांडवा (बालाघाट) मुठभेड़ में शहीद होने वाले चार कॉमरेडों में कॉ. विनय भी एक था जिसने पुलिस दरिंदों के खिलाफ अत्यंत वीरता के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। कुछ अपरिहार्य कारणों से उसकी जीवनी `**प्रभात**' में अब तक नहीं प्रकाशित की जा चुकी है। हमें काफी देर से मिली उनकी जीवनी पाठकों को लिए पेश हैं - संपादकमण्डल]*

1994 के मई माह में बालाघाट जिले के मांडवा गांव में पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर छापामार दस्ते पर घात लगाकर हमला किया था जिसमें चार कॉमरेड शहीद हुए थे, जबकि एक पुलिस वाले को छापामारों ने मार गिराया था। शहीद साथियों में एक था कॉ. विनय। कॉ. विनय ने उत्तरी तेलंगाना के करीमनगर जिले के ग्राम इंदुर्ती में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। उस इलाके में तेजी से चल रहे आन्दोलन ने इंटरमीडिएट पढ़ रहे युवा छात्र कॉ. विनय को आकर्षित किया। कुछ दिन वहां के आन्दोलन में काम करने के बाद 1990 में दण्डकारण्य आन्दोलन से जुड़ गया।

शुरू में गड़चिरोली जिले में चामोर्षी छापामार दस्ते का सदस्य बनकर काम किया और तत्कालीन फॉरेस्ट कमेटी के फैसले पर बालाघाट आया। बालाघाट में मलाजखण्ड दस्ते का सदस्य बना। कुछ ही समय बाद उसने वहीं पार्टी सदस्यता हासिल की। 1991 से 1994 में अपनी शहादत तक कॉ. विनय ने बिना किसी ढुलमुलपन के दृढ़ता से आन्दोलन में काम किया। दस्ते में पाइलट, डॉक्टर, शिक्षक जो भी जिम्मेदारी उसे दी गई उसने बड़ी कुशलता से पूरी की। साथी दस्ता सदस्यों का विश्वास हासिल करके सभी का चहेता बन गया। दस्ते के अनुशासन का उसने कड़ाई से पालन किया। वह दस्ते के सभी साथियों से घुलमिलकर रहते हुए उनकी गलतियों की बेहचक आलोचना किया करता था। जब कोई कॉमरेड उसकी गलतियों की आलोचना करता तो वह बड़ी ईमानदारी के साथ आत्मालोचना कर लेता था। वह अपने गुणों से दस्ते में हमेशा एक मिसाल बनकर पेश आता था। वह अपनी राजनीतिक चेतना बढ़ाने के विषय में हमेशा गंभीर रहता था और अध्ययन कार्य सतत जारी रखता था। जो विषय वह नहीं जानता उसके बारे में दूसरों से पूछने में वह कभी कोई संकोच नहीं करता था। जिले के आदिवासी जनता में जल्द ही लोकप्रिय बन गया और स्थानीय भाषा सीखकर जनता को राजनीति समझाया करता था। कॉ. विनय खासतौर पर गांवों में बच्चों को इकट्ठा किया करता था और उनके साथ खेल-कूद और नाच-गानों के साथ घुलमिल जाता था। इस तरह उसने कई गांवों में बाल संगठनों का निर्माण किया। दस्ते के डॉक्टर के नाते वह लोगों का इलाज करता था और उनका हर दुख-दर्द बांट लेता था। दस्ते में एक छापामार के नाते फौजी मामलों में कभी पीछे नहीं रहता था। मिलिटरी तकनीक सीखने और दैनिक व्यायाम, कवायद आदि में आगे रहा करता था। गांव के युवक-युवतियों को भी उसने कई बार फौजी प्रशिक्षण दिया। एक ईमानदार क्रांतिकारी के तौर पर वह हमेशा जनता की भलाई के बारे में सोचा करता था। जिले की जनता उसे कभी नहीं भूलती, हर साल 28 जुलाई के मौके पर उसे श्रद्धांजली देती है और उसके सपनों को साकार बनाने का संकल्प लेती है। ❖

पार्टी के वफादार समर्थक शहीद गावडे लिंगैया को लाल सलाम!

कॉमरेड गावडे लिंगैया एक ऐसा ईमानदार इन्सान थे जिन्होंने पार्टी द्वारा सौंपी हरेक जिम्मेदारी तो पूरी की ही, पार्टी द्वारा उनके पास रखे गए एक लाख रुपए को भी चार साल तक अपने पास बड़ी हिफाजत के साथ रख लिया और उसमें से एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं किया, इसके बावजूद कि इस दौरान पार्टी से उनका संपर्क टूट गया था और कई बार उन्हें आर्थक तंगी झेलनी पड़ी थी।

गड़चिरोली डिवीजन के सिरोंचा तहसील का एक गांव है सिरिकोंडा। इस गांव का निवासी थे गावडे लिंगैया। 1980 के दशक में जब सिरोंचा छापामार दस्ता मौजूद था तब वह सिरिकोंडा जाया करता था। अहेरी दस्ता भी कभी-कभार यह गांव जाया करता था। जब-जब छापामार दस्ता जाता था, तब कॉ. लिंगैया गांव और एरिया के बारे में जानकारी दिया करता था। पार्टी की राजनीति पर उसकी आस्था अटल थी। वह हमेशा चाहता था और क्रांतिकारियों से आपनी बात रखता था कि उसके इलाके में पार्टी छापामार दस्ते की बहाली करे। 1996 में जब अहेरी दस्ता उनका गांव गया था तब एक ठेकेदार से पार्टी के लिए चंदा वसूलने की जिम्मेदारी कॉ. लिंगैया को दी। कॉ. लिंगैया ने 1,04,000 रु. वसूलकर हिफाजत से अपने पास रख लिया। लेकिन उसके बाद 4 वर्षों तक दस्ते का वह गांव जाना ही नहीं हुआ। 1999 में जब दस्ता दोबारा सिरिकोंडा गया, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से पार्टी के जिम्मेवारों को पैसे सौंप दिए। कॉ. लिंगैया 50 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते हमसे भौतिक रूप से विदा हो गए। उनकी मृत्यु से पार्टी ने क्रांति का एक ईमानदार समर्थक और सच्चा हमदर्द खो दिया। कॉ. लिंगैया एक आदर्शवान इन्सान थे। आइए, हम सब उन्हें अपना आदर्श बनाकर उस शहीद की स्मृति को सिर झुकाकर श्रद्धांजली दें। ✪

बीमारी का शिकार बनकर शहीद हुए क्रांतिकारी जननेता कॉमरेड सिंगराय, कॉमरेड प्रसाद और कॉमरेड दामू तामूर को लाल सलाम!

कॉ. सिंगराय

उत्तर बस्तर डिवीजन, तहसील नारायणपुर, रेंज बेनूर, गांव इन्नर का एक आदिवासी किसान था कॉ. सिंगराय। इन्नर कोई 80 मकानों वाला गांव था। और इस गांव में कॉ. सिंगराय जनता का चहेता और नेता था। 1995 में वह डीएकेएमएस के ग्राम अध्यक्ष बने थे और 1998 तक रेन्ज कमेटी अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने रेन्ज भर में कई संघर्षों में जनता का नेतृत्व किया। युवक-युवतियों के लिए खेल-कूद का आयोजन करके नौजवानों का दिल जीतकर उन्हें क्रांति की राजनीति की ओर खींच लाया करता था। गांव के लोगों को सामूहिक कामों में गोलबंद करने के अलावा, गांजा आदि नशीले पदार्थों के धंधे के खिलाफ, तेन्दुपत्ता मजदूरी में बढ़ोत्तरी के लिए किए गए संघर्षों में उसने सबसे आगे रहकर लोगों का नेतृत्व किया। जब बेनूर की पुलिस ने पार्टी के एक समर्थक किसान को बेरहमी से पीटकर जान से मार दिया था, तब थाने के सामने लोगों के धरने का नेतृत्व किया। इन्नर गांव के निकट डंडावेंड के स्कूल भवन में पुलिस ने एक बार मुकाम किया था, तो उसने मिलिशिया के युवकों से मिलकर बम विस्फोट करके पुलिस को हैरान-परेशान कर दिया। गांव के एक दसरे संघ नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सिंगराय ने न सिर्फ उसके परिवार की मदद की, बल्कि उसकी रिहाई की मांग से संघर्ष चलाया। कोय्यूर शहीदों की याद में आयोजित स्मृति सभा के मौके पर आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा करने, इन्नर से डंडावेंड तक जुलूस निकालने में उसका योगदान रहा। 28 जुलाई को शहीद सप्ताह के बारे में प्रचार करने के लिए उसने डीएकेएमएस के कई युवा साथियों को गोलबंद करके प्रचार दलों का गठन किया और खुद भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इन संघर्षों से उभरते हुए वह ग्राम पार्टी सचिव बन गया। बीमारी से कॉ. सिंगराय की असमय मृत्यु हुई। आइए, इस क्रांतिकारी के अधूरे सपनों को साकार बनाने के लिए संकल्प लें।

कॉ. प्रसाद

कॉ. प्रसाद कोण्डागांव तहसील, ग्राम राजुवेडा का निवासी था। आदिवासी इलाकों में सरकार की लंबे अरसे से जारी घोर लापरवाही के चलते हर साल कई लोगों को असमय मृत्यु का शिकार होना पड़ता है जो एक आम बात है। ऐसे लोगों में मासूम बच्चों से लेकर सभी उम्र के स्त्री-पुरुष होते हैं। कॉ. प्रसाद ने 25 साल की उम्र में ही बीमारी का शिकार बन गया। आदिवासी राउत समाज में जन्मे कॉ. प्रसाद 1995 से डीएकेएमएस का सदस्य बनकर काम करते हुए ग्राम विकास कमेटी का सदस्य चुन लिया गया। उसने कृषि विकास के लिए कई प्रयास किए - दूसरी फसल बोना, मवेशियों से फसलों को बचाने का बंदोबस्त करना, सब्जियां उगाना, फलदार पौधे लगाना आदि। 1998 सितंबर में वह ग्राम रक्षक दस्ते का सदस्य चुना गया और अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण की भावना के कारण 1999 में पार्टी का उम्मीदवार सदस्य बन गया। जब गांव के मुखियाओं और जमींदारों ने पुलिस से सांठगांठ कर गांव पर हमला करना शुरू किया और पार्टी में पूर्ण समय के लिए काम करने वालों के घरों पर हमला करना और उनके परिवार सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तब कॉ. प्रसाद जनता के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हो गया। जमींदारों को दण्डित करने में उसने जनता का पक्ष लिया। फरवरी 2000 में केलंगा गांव में छापामार दस्ते पर पुलिस ने हमला करके गोलीबारी की तो, उस मुठभेड़ से सुरक्षित निकल आए कुछ दस्ता सदस्यों को कॉ. प्रसाद ने पुलिस की नजरों से बचाया।

23 दिसंबर 2000 को कॉ. प्रसाद बीमारी के कारण शहीद हो गए। आइए, कॉ. प्रसाद के दृढ़ संकल्प, आदर्श आचरण, कुरबानी की भावना आदि गुणों को आत्मसात करते हुए उसे सविनम्र श्रद्धांजली दें।

कॉ. दामू

कॉ. दामू मर्दापाल रेन्ज, वावकनार गांव का निवासी था। 35 वर्षीय दामू डीएकेएमएस का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। जनता के इस चहेता ने डीएकेएमएस के एक जिला कमेटी नेता की गलत नीतियों के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष किया। आदिवासियों का हिन्दूकरण करते हुए, जनता पर जारी साम्प्रदायिकतावादियों के हमलों के खिलाफ उसने दृढ़ता से संघर्ष किया। इस तरह वह संगठन का अध्यक्ष बन गया। गांव में बच्चों को गोलबंद करके बाल संगठन गठित करने में उनका बड़ा योगदान रहा। पुलिस को परेशान करने के लिए मर्दापाल पुलिस थाने पर किए गए हमले में कॉ. दामू की भूमिका रही थी। पुलिस की गोलीबारी में कॉ. निर्मला की शहादत के बाद पार्टी द्वारा आहूत उत्तर बस्तर बंद को सफल बनाने में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। मर्दापाल में एक सरकारी बंगला को जलाने में भी दामू ने लोगों का नेतृत्व किया।

जनता के पिछड़े हुए कृषि तरीको में बदलाव लाने के लिए, नई फसलों का परिचय करने के लिए कॉ. दामू ने बड़ा प्रयास किया। इलाज की सुविधाओं से वंचित अपने गांव में जन चिकित्सा केन्द्र खोलने में उसने पहलकदमी की। आइए, इस नौजवान साथी के सपनों को साकार बनाने के लिए शपथ लें। ✪

भुमकाल पर ब्रितानी सेनाओं का हमला - भुमकाल का पीछा कदम

विशाल बस्तर राज्य में भड़के जन-विद्रोहों में से `महान भुमकाल' का ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास के मुताबिक 1774 से 1910 तक के 136 सालों के दौरान बस्तर की आदिवासी जनता ने 10 विद्रोह किए थे - 1) हल्बा विद्रोह (1774-1790), 2) भूपालपट्टनम संघर्ष (1795), 3) परालकोट विद्रोह (1825), 4) तारापुर विद्रोह (1842-1854), 5) मेरिया विद्रोह (1842-63), 6) महान मुक्ति संग्राम (1856-57), 7) कोया विद्रोह (1859), 8) मुरिया विद्रोह (1876), 9) रानी चोरिस (1878-1882) और 10) महान भुमकाल (1910)।

उपनिवेशी शासन के पहले बस्तर पर पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने हमले किए, तो स्थानीय जनता उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। बाद में, 1853 से ब्रितानी सेनाओं के खिलाफ आमने सामने लड़ने का अनुभव भी बस्तर की जनता को है। इन संघर्षों से बस्तरियों की यही पहचान मिल जाती है कि उन्होंने अपनी धरती पर परायों के शासन को कभी बर्दाश्त नहीं किया चाहे वे विदेशी शासक हों या पड़ोसी राज्यों के पराए शासक हों। भले ही उनकी ताकत बहुत ज्यादा क्यों न हो, बस्तर की जनवाद प्रेमी जनता ने उनका डटकर मुकाबला किया और 'अपनी धरती पर अपना शासन' की तमन्ना रखी। ऐसी धरती पर आज दोबारा 'धरती मां की मुक्ति के लिए' संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का मकसद भी राजसत्ता छीन लेना ही है। लुटेरे शासक वर्गों की पाशविक सेनाओं के खिलाफ आज के जन छापामार सैनिक लड़ रहे हैं। इसके अलावा, हाल के दिनों में बस्तर राज्य में पिछले 6 महीनों से हजारों जनता सड़कों पर आ रही है। नए प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस्तर के जबरिया विलय का विरोध करते हुए भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] द्वारा किए गए *'एक और भुमकाल के लिए तैयार हो जाओ'* के आह्वान पर प्रतिक्रियास्वरूप आंदोलित हो रही जनता को इस मौके पर विशेष रूप से याद की जाए। 1825 में ही अंग्रेजी हत्यारों के फांसी के फंदे को चूमकर बस्तर के इतिहास के सर्वप्रथम शहीद का श्रेय प्राप्त करने वाले गेंदसिंह से लेकर आज तक इस रणभूमि पर हजारों हजार योद्धाओं ने मकसद को हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुती दी। उन सभी को हम अपना आदर्श बना लें। उनकी संघर्षमय गाथाओं को आज की पीढियों को बताने और मौजूदा सामंती-साम्राज्यवादी शासन का सफाया करने की जिम्मेदारी हम पर ही है। इस धरती पर गर्व से लाल झण्डा फहराने की जिम्मेदारी भी हम पर ही है।

अंग्रेजों के शासन का मुकाबला करते हुए चले `महान भुमकाल' नामक जन विद्रोह को कुचलने के लिए जो दमनचक्र चलाया गया था वह बेहद बर्बरतापूर्ण था। 39,114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से हमारे देश के केरल और अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों और साथ ही, बेल्जियम, फिलिप्पीन्स, इज्राएल आदि देशों से भी बड़ा बस्तर राज्य उन दिनों 84 परगनों में बंटा था। इनमें से 47 परगनों में महान भुमकाल जन विद्रोह जोरदार ढंग से चला था, जबकि पूरे बस्तर में इसका प्रभाव था। लगभग 1000 गांवों में उस विद्रोह का पैगाम पहुंचाया गया था जिन्होंने संघर्ष के शोलों को और हवा दी।

जन विद्रोह से उपनिवेशी शासकों और उनके सामने घुटने टेके स्थानीय राजाओं में कंपकंपी पैदा हुई थी। `माड़िया राज' की घोषणा करके जनता ने 40 दिनों का खुद का शासन चलाया, तो शासकों ने अपनी पाशविक सेनाओं को बस्तर भेजा। सेन्ट्रल प्रॉविन्स के 200 सशस्त्र सैनिकों को, डिप्यूटी सूपरिन्टिन्डेन्ट पिल्लाई के नेतृत्व में मद्रास के 150 विशेष सैनिकों को, मेजर ब्लोइप जॉन्सन के नेतृत्व में 22वीं बटालियन (पंजाब) के 70 हत्यारे बलों को तैनात किया गया। इसके अलावा जबलपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर (उड़ीसा) और नागपुर से भी विशेष बल बस्तर पहुंचे थे। रायपुर से आए 150 पुलिस वालों का दल भी शामिल था। ये सब आधुनिक हथियारों से लैस थे और उनके निशाने पर थी तीर-धनुषों से लैस आदिवासी जनता। 8 फरवरी 1910 से 25 फरवरी के बीच ये बल बस्तर पहुंचे थे और बस्तर को घेर लिया गया।

बड़े पैमाने पर ब्रितानी सैन्य बलों की तैनाती से बस्तर के सभी गांवों में खलबली मच गई। बस्तर की संघर्षरत आदिवासी जनता जंगल मां की गोद में छिप गई। गांव सुनसान हो गए। घर-आंगन जला दिए गए। खाकी बलों की नजर में पड़े लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ीं। जिसने बगावत की उसका सफाया कर दिया गया। अनगिनत महिलाओं की इज्जत लूटी गई और कइयों की जानें गईं। नन्हे बच्चे अनाथ हो गए। सारा जंगल ही विदेशी दरिंदों के हमले से सिहर उठा। बन्दूकों की गूंजों से, लोहे के जूतों के रौंदन से चले विदेशी भाड़े के सैनिकों की ज्यादतियों और नरसंहारों से जंगल मां रो पड़ी। ब्रिटिश वालों की 'सब का नाश' की नीति के खिलाफ बस्तर भूमि पर जनता का आक्रोश भड़का।

अपने अधिकारियों और पड़ोस के अहेरी राजा से `महान भुमकाल' की खबरें पाकर चन्द्रपुर, नागपुर और रायपुर में ब्रितानी अधिकारी हड़बड़ा गए और उपलब्ध बलों को इकट्ठा किया। स्टेनगनों से लैस 120 लोगों का पुलिस दल जिसका नेतृत्व एएसपी ड्यूक कर रहा था, रायपुर से धमतरी तक रेलगाड़ी में और बाद में दक्षिण-पूर्वी दिशा में 136 मील सड़क पर सफर करके जगदलपुर पहुंच गया। 21 साल बतौर एसपी काम करके 1899 से 1903 तक बस्तर का प्रशासनिक अधिकारी रहे जी.डब्ल्यू. गेयर ने इन बलों की कमान स्वीकार की। इन बलों को अपर्याप्त मानते हुए इन अधिकारियों ने मांग की तो रंडाल के नेतृत्व में 25 सशस्त्र पुलिस

वालों का एक और दस्ता पहुंच गया। ये 8-13 तारीखों के बीच पहुंच गए। 15 तारीख तक इन बलों के अलावा उपरोक्त बलों में कुछ इंद्रावती नदी पहुंच गए।

ब्रितानी सेनाएं उन हजारों जन बलों को देख हक्का-बक्का रह गईं जो 1 फरवरी से राजधानी जगदलपुर शहर को घेरकर रखे हुए थे। 5 दलों में बंटे हजारों लोगों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए उस शहर पर सैन्य बल कब्जा नहीं कर सके। शहर के राज परिवार ने जान हथेली पर रख ली। इंद्रावती नदी तक आए पुलिस बलों को विद्रोहियों ने नदी पार करने से रोकना चाहा। 16 तारीख तक सैन्य बल आस्ना तक बढ़ गए। उन दिनों जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर पुल नहीं था। दोनों तरफ दोनों बलों ने मोर्चा संभाला। लेकिन जन बलों की संख्या को देखकर डरे ब्रितानी अधिकारी दिब्रेट और गेयर ने साजिश रची। उन्होंने जनता से अपील की कि वे जंग लड़ने नहीं आए थे, बल्कि हमेशा की तरह जनता की समस्याएं सुनने आए थे और जनता उनका विश्वास करे। भोलेभाले आदिवासियों ने उन जाने-पहचाने अधिकारियों को भरोसा किया। इस पृष्ठभूमि में 16 तारीख को घटी घटना को बालचंद जैन के शब्दों में सुन लिया जाए -

अंग्रेजी अधिकारी कार में सवार होकर आए थे। चूंकि खड़कघाट के पास पुल नहीं था इसलिए गाड़ी वहीं रुक गई। वह बस्तर राज्य में आने वाली सबसे पहली कार थी। सड़क पर दौड़ रही उस कार को देखकर भोलेभाले आदिवासी लोग आश्चर्य होकर देखने लगे थे। जैन ने कहा कि षड़यंत्रकारी अधिकारियों ने धोखेबाजी से जनता पर गोलीबारी की। विनायक सिंह का कहना है कि उस दिन के युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा की गई भीषण गोलीबारी में तीर-धनुषों से लैस 25 हजार लोग मारे गए थे। बदकिस्मती से उस युद्ध में धराशायी हुए जनयोद्धाओं का इतिहास या ब्यौरा किसी भी सरकार ने या किसी भी इतिहासकार ने जनता को आज तक उपलब्ध नहीं करवाया।

16 तारीख को हुए खड़कघाट युद्ध में इंद्रावती नदी के तट पर जनता का खून बहा था। बहती नदी लाल हो गई थी। उस तट पर मिट्टी के हर कण को लगे खून आदिवासियों के दिलों में अंकित होकर बदला लेने हेतु उन्हें हर पल प्रेरित करने लगा। उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले अपने बहादुर नेता हुंगा को याद करते हुए जनता ने संघर्ष का संकल्प लिया। अयतू, एड़का, कापा, कोहला, मासा, रेका, विज्जा, भीमा, लकमा, हाडी आदि शहीदों को जनता ने याद की। गुण्डादुर के नेतृत्व में जल्द ही बदला लेने का संकल्प हर तरफ दोहराया गया। खड़कघाट हत्याकांड से क्रोधित जनता को देख और जनता के संकल्प के बारे में सुनकर राजा का पसीना छूट गया। राजमहल से ऐसी अफवाहें भी फैली थीं कि उसने आत्महत्या की कोशिश तक कर डाली। राजा का चाचा लाल कालेंद्र सिंह और महारानी सुबरन कुंवर ने जनता का पक्ष लेकर राजा को चेतावनी दी।

उसे यह चेतावनी दी गई कि खून के प्यासे अंग्रेजी दरिंदों को कोई भी मदद न दी जाए, उसके शासन को मजबूत करने वाली कोई भी कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद राजा ने अंग्रेजी अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए। इससे विदेशी शासकों ने राजा के परिवार को बचाने का कदम उठाया। राजमहल के सामने शीशे के टुकड़े बिछा दिए गए ताकि अंदर कोई दाखिल न हो सके। पुलिस बलों को तैनात किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद बस्तर की जनता का एक ही सवाल लुटेरे अधिकारियों और राजा के दिलों मे प्रतिध्वनित हो रहा था - "क्यों कर हम पर गोलियों की बौछार की गई?"

जनता की हालत देखते हुए ब्रितानी अधिकारियों को लग रहा था कि उनके पास मौजूद बल नाकाफी हैं। वे अतिरिक्त बलों का इंतजार कर रहे थे। तब तक किसी भी तरह जनता को शांत रखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। तोल-मोल और जनता में फूट डालने की कोशिश करने लगे थे। नेताओं को खरीदने की कोशिश करने लग गए। आदिवासियों के भोलेभालेपन और जमीन पर उनके विश्वास के चलते `माटी किरिया' पर उनकी आस्था का फायदा उठाते हुए षड़यंत्रकारी ब्रितानी अधिकारियों ने कई साजिशें कीं। उन्होंने सबसे पहले लाल कालेन्द्र सिंह को राजमहल बुलाया। लेकिन उसने दरबार में राजा की कड़ी भर्त्सना की। राजा को निकम्मा कहा। बस्तर राज्य को गिरवी रखने वाला गुलाम कहा। बस्तर की जनता की आकांक्षाओं के साथ गद्दारी की कहा। भुमकाल के नेताओं के नाम बताने और अन्य ब्यौरे देने तथा उन्हें पकड़ा देने की अंग्रेजी अधिकारियों की मांग पर लाल ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उसे काबू कर लिए बिना बस्तर के भुमकाल की ज्वालाओं को बुझाना असंभव हैं, यह बात वे अच्छी तरह जानते थे। इस तरह के तोल-मोल के समझौतों से एक सप्ताह बीत गया और इस बीच अतिरिक्त बल बहुंच गए। इससे विदेशी शासकों ने जनता का दमन करने बलों को तत्काल मोर्चे पर तैनात किया।

गुण्डादुर : *1910 के भुमकाल का नेता। वह जनता का नेता था, जनता की संघर्षशील आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। एक युद्ध गीत था, युद्ध का संकेत था। कुरबानी की प्रेरणा था। भावी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श, आज भी जीती-जागती याद - कचोट देने वाला अतीत है। विदेशी लुटेरों के दिलों में मची एक हड़कंप, दुश्मन के सामने कभी सिर न झुकाने वाला एक सेनानी था। जंगल मां की गोद उसका पता था। घनिष्ठ साथी सोनू मांझी की गद्दारी का शिकार बने आजादी का दीवाना था। आज भी बस्तर की जनता के गीतों में पाए जाने वाला अमर नेता। अंग्रेजों के लिए `जिन्दा या मुर्दा' 10 हजार रुपए का इनामी विद्रोही था। गुण्डादुर एक व्यक्ति का नाम नहीं, सर्वनाम है। अब तक किसी भी इतिहासकार की कलम के लिए एक अबूझ पहेली रहे गुण्डादुर के इतिहास को वर्तमान क्रांतिकारी आन्दोलन सादर प्रणाम करता है।*

वह 24 फरवरी थी। बस्तर पहुंचे सैन्य बलों ने गंगामुंडा पहाड़ी को घेर लिया। वहां पर सोए विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। उन्हें काबू कर लिया गया। कुछ विद्रोही नेता पकड़े गए।

इस घटना से जनता में व्याप्त दहशत को दूर करने के लिए जनता के नेता गुण्डादुर ने काफी कोशिश की। उसने जनता को गोलबंद किया। गुण्डादुर पर विश्वास के चलते जनता जल्द ही डर से उबर गई। फिर से तीर-धनुष उठाए गए। अंग्रेजों की गद्दारी अब भी जनता के क्रोध का कारण बनी हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को किसी मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि लड़ाकुओं ने अलनार में मुकाम किया है। जगदलपुर से 8 किलोमीटर दूर स्थित अलनार को रातों रात ही अंग्रेजी सेनाओं ने घेर लिया। नींद में रहे लड़ाकुओं को घेर लिया गया। लेकिन अचानक वे नींद से उठे और बगल में स्थित तीर-धनुष उठाए। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण की बात ही नहीं उठती। **"हम युद्ध करेंगे"** यही उनका नारा था। अपने साथ रही महिलाओं और बच्चों को पीछे रखकर तने हुए तीर-धनुषों से आगे बढ़े स्थानीय लोगों पर लुटेरे पुलिस वालों की बंदूकें बरस पड़ीं। फिर एक बार खून की नदियां बहीं। ऐसी स्थिति में जनता को पीछे हटना पड़ा। उनका प्यारा नेता गुण्डादुर जंगल मां की गोद में सुरक्षित खिसक गया। यहां जनता को एक और पराजय झेलनी पड़ी। जगदलपुर पर अधिकारियों का पूरा कब्जा होता रहा। हर नवागत सैन्य टुकड़ी दमनात्मक हमलों में शामिल होती रही और हमला तीखा हो गया।

26 फरवरी को लाल कालेन्द्र सिंह और 15 अन्य विद्रोह के समर्थकों को बंदी बनाया गया। लाल का घर जला दिया गया। बाकी घरों को लूटा गया। इनकी महिलाओं का घोर अपमान किया गया। जो भी बगावत करता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। रानी सुबरन कुंवर को भी बंदी बनाया गया। लाल को बस्तर से तड़ीपार करके नागपुर से 175 मील दूर स्थित एरियापुर भेज दिया गया। वहीं 1916 में उसकी मृत्यु हो गई। रानी सुबरन को रायपुर भेजा गया जहां अक्टूबर (1910) में उसकी मृत्यु हो गई। इन्हें इस तरह की सजाएं दी गईं, जबकि आम जनता को भी नहीं छोड़ते हुए ब्रितानी सेनाओं ने क्रूर यातनाएं दीं। पुलिस वाले लोगों को तब तक चाबुकों से पीटा करते थे जब तक कि वे बेहोश न हो जाते। 2000 वर्ग कि.मी. के दायरे में स्थित 65 गांवों के 500 लोगों को क्रूरतम यातनाएं दी गईं। इस तरह कई यातनाएं देकर छोड़ने के बाद कई लोगों ने दम तोड़ दिया। इस तरह की यातनाओं का विवरण कहीं भी दर्ज नहीं है। इस इतिहास का गवाह खुद जनता ही है।

जंगल में कदम रखने वाले अतिरिक्त बलों को 4 मुख्य भागों में बांटकर चारों तरफ भेजा गया। इन सेनाओं ने 6 मार्च 1910 से लेकर 15 दिन तक सैन्य अभियान चलाया। इन सेनाओं में, खासकर रैंडल के नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में सुन लें तो रेंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सेनाएं परजा इलाके पर टूट पड़ीं। मिडेल्टन स्टेवार्ड के नेतृत्व वाले बलों ने दंडामी-माडिया इलाके पर केन्द्रित किया। इनके निशाने का मुख्य केन्द्र कूकानार था जो संघर्ष का केन्द्र था और गुण्डादुर की जन्मस्थली था। इसलिए इस गांव का नाम सुनते ही सेनाएं जल-भुनती थीं। रोहिल्ला की सेना के इस गांव के लोगों द्वारा सफाया किए जाने के गुस्से से लुटेरी सेनाओं ने इस गांव पर हमला करके तमाम स्त्री-पुरुषों को मार डाला। दूसरी तरफ, डूरी की सेनाओं ने छोटाडोंगर को केन्द्र बनाया। लेकिन इन सेनाओं को बहादुर `अबूझमाड़' की जनता ने घेर लिया। असहाय बन चुकी डूरी की सेनाओं को पंजाब बटालियन ने बचाया जो समय पर वहां पहुंचीं।

माड़ की जनता को पुलिस की अभूतपूर्व दमनात्मक कार्रवाइयों का शिकार होना पड़ा था। इन सेनाओं ने कई गांवों पर धावा बोलकर महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया। गरीब आदिवासी जनता की घासफूस की झोंपड़ियों को पुलिस बलों ने जला दिया। जनता को मानसिक रूप से आहत किया गया था। जनता के दिलों में जो जख्म किए गए थे उनके निशान आज भी मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर जनता को हिलाने से कई पीड़ामय गाथाएं सुनाई जाती हैं। (याद रहें ***'प्रभात'*** के पिछले अंक में ***भुमकाल*** के बारे में सिलसिलेबार छप रहे लेख पढ़कर स्थनीय जनता द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित किया गया था।)

चौथे बल ने ड्यूक के नेतृत्व में सुकमा के दमन की कार्रवाई शुरू की। भुमकाल के चलते उसे मिले कड़वे अनुभवों से उसने जनता के खिलाफ तीखी नफरत से बर्बरतम हमले किए। स्थानीय जमींदार जनकैया ने भी इसका साथ दिया। इनके साझे हमलों में जनता बड़ी तादाद में मारी गई।

उपरोक्त सेनाओं के अलावा, सैन्य कार्रवाई में भाग लेकर लौट रहे मद्रास बलों ने बीजापुर में लूट और अत्याचार मचाए। इस तरह, हर तरफ बस्तर की जनता पर दमन का पहाड़ टूट पड़ा।

लूट, बलात्कार, घरों को जलाने के अलावा विदेशी शासकों ने जनता से युद्ध का खर्च चुकाने का दबाव डालकर बड़ी मात्रा में जुर्माने वसूले। गरीब आदिवासी जनता से जबरन बड़ी मात्रा में धन वसूला गया। 1910 के दस्तावेजों से पता चलता है कि 8 तहसीलों के 47 परगनों के 838 गांवों से जुर्मानों के रूप में वसूला गया कुल धन एक लाख रुपए था। दूसरे 21 के 120 गांवों से जबरन 3,041 रुपए वसूले गए थे।

अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का परचम फहराने के जुर्म पर चलाए गए अदालती मुकदमों की संख्या भी कम नहीं थी। इनके निपटारे के लिए जगदलपुर में विशेष अदालतें चलाई गईं। 13 मार्च 1910 से 28 अप्रैल 1910 तक इन मुकदमों की सुनवाई की गई थी। आनन-फानन दिए गए फैसले में 78 लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। हालांकि विद्रोह की राह पर चल रही जनता को पाठ पढ़ाने के इरादे से ये फैसले सुनाए गए थे, लेकिन सभी मुकदमों को और 10 साल तक चलाया गया।

विद्रोह करने वाली बस्तर की जनता को पाठ पढ़ाने के इरादे से विदेशी दरिंदों के द्वारा किए गए कत्लेआम, अत्याचार, मुकदमे, गिरफ्तारियां, यातनाएं, बलात्कार, घर जलाना, जुर्माने आदि ने जनता को बेहद झकझोर दिया। लेकिन इतिहास ने साबित किया है कि इसका असर अस्थाई ही है। बस्तर की बहादुर जनता पिछले 20 सालों से फिर से संघर्ष की *(शेष पृष्ठ 25 पर ....)*

गोंडी रिपोर्टकु

जनता पुलिस तुन प्रतिरोध कीसि पूंडतंग!

उत्तर बस्तर डिवीजन केशकाल एरिया, किसकोडो रेंज ग्राम कोटकोडो ते पुलिस तोर हमला कीतोर।

2000 सितंबर लेलेंज ते कोटकोडो नाटे ना पोरोन पुलिसकु वासि हमला कीतोर। इगटा संगठन तोर कुन पोयसि ओयला बच्चोको दिय्यानाह कोशिश कीसोरे मत्तोर, मत्ति वायालासि हिम्मत आलो। मत्ति संगठन तोर काम तुन रोमि कीयना, नक्सलवादीरकुन खतम कीयना इत्तेकि बहे बारा दाया लागिंता। पुलिस तोरु नरका हमला कीयला वात्तोर। सब्बेटोरु उंजिसि मत्तस्के चारी बित्तान पोयसि वात्तोर। चारी तोरु संगठन तोरा लोहकुन तोहचीतोर। नाटेने संगठन तोरु मुन्नेने वडकिसि मत्तोर - पुलिस तोरु वात्तेके सब्बे आस्कु, कोयतोर जमासि पूडाकाल इंजि। वरोर केयतेकि सब्बे लोहकुनोर पेसिसि वित्ति वायना इंजि वडकले मत्ता। अद्दामे उंदि दिया पुलिस तोरु नरका वासी संगठन तोरांग लोह्कुने नेंगना शुरू कीत्तोर, नाटेनोरु उसकाड ता मारे बोरे पुन्नोर आसि। मत्ति बेव-बेव लोह्कुने ओडियतोरो अवु लोह्कनांग मुय्यताह पुलिस तोरकुन लातींग-लातींग हारतंग। इदे मौका ते संगठन तोर पेसिसि वितितोर। आस्कु पुलिस्कुना संगे लड़ाई कीसि पूडतांग। सब्बे पुलिस तोरु गुडरा पोरो जोंगासि विचार कीत्तोर - नेंडु मम्माट परवाल, दूसरा बेरा ज्यादा बड्जा वायकाल इंजि, अद दिया वापस अत्तोर। मूंड-नालुंग दियांग पेरिके ओस्सो वेने आमाबेड़ा, धनोरा थानातोरु पुलिसकु मिलेमासि 50 मूल वात्तोर। अद दिय्या वेने नरकाये वात्तोर। अद दिया संगठन तोरकुन पोयतोर। अस्के अव्वे लोह्कुना आस्कु तेदसि मंजि वरोन-वरोन पुलिस कुन हारना-जाहना कीतांग। इदे मौका ते संगठन तोरु ईके-आके पोयता पुलिसकुन धक्का हीसि वितीतूर। पुलिस तोरु ओना धक्का ता मारे, चेरोटा लाटा ते (गुफा) बुर वित्सि मुटतोर, पुलिस ना तुपाकी उंदि वडका अरता, पुलिस उंदि वडका अरतोर।

थानेदार कुन बडगा पोयसि ताकना मुइताङ जीवाना एरे (मेस्सकाना) लातीता। थानेदार `आयगो' इंजि मुटतोर मति पेरिके धीरे से तेदिसि, सब्बे पुलिस तोर कुन सीटी उरसी मेट्टा पोरो केयसि जमासि, आया पर्रो इत्तोर। वरोन पोयसि मत्तोर, वेनकीने ओयकाल इंजि ओसोर मत्तोर, ओर वेन्ने नवडे अरदागडाह मौका ऊड्सि, मेट्टा तेके वित्तितोर, जैक पूंड्सूड्तोर मत्ति पूंडा परवानके विडसिसि हत्तोर।

इद कबुरु केंजिसि एरिया ते दीदीस्कु, दादालोरु उशारासि मावा नाटे वेन्ने वात्तेकि इदामे कीसी पूंडकाल इंजि नाटे-नाटे मीटिंग कीतोर। ओस्सो सब्बे नाटेनोर कुन, संगठनतोर हिम्मत हीत्तोर। पुलिस कुन पूंडसी खुशी आसि, मीटु वेन्ने एरे मत्तेके ओरकुन हौक्सि मन्नेराट इंजोरे दलम कुन वेन्ने आलोचना कीत्तोर। ✪

अलग बस्तर राज्य तुन मांग कीसोरे उत्तर बस्तर ते रैलींग पेस्तुङ !

उत्तर बस्तर डिवीजन, केशकाल एरिया ते अलग बस्तर राज्य बनेमायना इंजि दिसंबर, जनवरी ते रैली पसीहतोर। अंतागढ़ रेंज सरन्डी नाटे 5,000 जनता, अंतागढ़ तहसील किसकोडो नाटेने 2,000 जनता रेली पेसीहतोर।

इद रैली ता बारे नाटे-नाटे जनता कुन समझा कीले आत्ता। ताना पेरिके रैली आता, इद मौका ते नाटे-नाटेना डीएकेएमएस, केएएमएस संगे प्रचार दलकु बनेमासि एरिया ते हर नाटे जनता कुन आमसभा कीसोरे समझा कीत्तोर। मावा बस्तर ता संपत्ति पूरा मावाये कइदे मंदाना इत्तेकि मावा राज्य पन्डाना जरूरी आंदु। माटु छत्तीसगढ़ ते मन्नोम इंजि चेतना बेरसता। इचुक दियाने नेतालोरु जनता ना पोरोय ते वांदुर मत्ति, नेन्डु बस्तर तुन छत्तीसगढ़ ते मिला कीत्तानकु बोरे वडकावालोरु हिल्लेर। जनता हड़ताल कीत्तेकि कोंडांग-कोंडांग हूडिंतोर, मत्ति सत्ते आन्दु इंजि मुन्नेह वासि वडकवालोरु बोरे हिल्लेर इंजि जनता समझे मात्ता। अदिन काजे जनता वेल्ले संख्या ते रैली ते शामिल आसि बस्तर राज्य बनेमायाना इंजि पुकार कीत्ता। ✪

(.... पृष्ठ 24 का शेष)

राह पर चल रही है। अब उसने हथियारबंद संघर्ष के लिए कमर कस ली। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के अंत के लिए उसने क्रांति का रास्ता चुन लिया। अपने अतीत के संघर्षमय विरासत को जारी रखते हुए लाल झण्डे पर आस्था रखकर अपनी संतानों को दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आन्दोलन में भाग लेने के लिए भेज रही है। वे अपने कुरबानियों से भरे इतिहास को दोहराते हुए संघर्ष कर रहे हैं। वे न सिर्फ कल के गुण्डादुर का ही स्मरण कर रहे हैं, बल्कि आज के कोय्यूर शहीदों और अनगिनत अन्य शहीदों को आदर्श मान रहे हैं। वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि साहस के साथ लड़ने से जीत हमारी ही है।

*(नोट : अप्रैल 1999 से **'प्रभात'** में नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही बस्तर की जनता के विद्रोहों के इतिहास की श्रृंखला अगले अंक में समाप्त हो रही है। अगले अंक में जनता के विद्रोहों में शहीद हुए तमाम वीर योद्धाओं को श्रद्धांजली पेश करते हुए समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए हम पाठकों से अनमोल विचारों का आमंत्रण कर रहे हैं। पिछले अंकों में प्रकाशित लेखों को पढ़कर अपनी कीमती प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने वाले श्रोताओं और पाठकों को हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। - संपादकमण्डल)*

फिलिप्पीन्स के क्रांतिकारी आंदोलन का आगे कदम

विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ चल रहे हथियारबंद संघर्षों में से फिलिप्पीनी जनता का संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.पी.) के नेतृत्व में यह लड़ाई दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते पर कदम-ब-कदम आगे बढ़ रही है। फासीवादी तानाशाही का सामना करके, अमरीकी साम्राज्यवादियों के एल.आइ.सी. (गुरिल्ला युद्ध विरोधी रणनीति) को नाकाम करते हुए पिछले तीस वर्षों से यह लड़ाई चल रही है। कॉ. माओ द्वारा विकसित जनयुद्ध की रणनीतिगत दिशा के आधार पर वे अपने देश की जनता की साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। यह युद्ध विश्व की जनता के सामने एक मिसाल है।

1969 में सी.पी.पी. की पुनःस्थापना हुई। इसके पहले और उसके बाद उन्हें कई गलत दिशाओं के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा, गलत दिशाओं के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। फलस्वरूप, फिलिप्पीन्स में क्रांतिकारी आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक संघर्ष चलाकर ही, गलत रुझानों के कारण हुई गलत कार्यदिशा को सुधारकर वे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ा सके हैं।

पार्टी-निर्माण का इतिहास

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, फिलीप्पीन्स पर जापानी आक्रमण के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हुआ था। फासीवादी जापान के आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पीपुल्स आर्मी (जनसेना) की स्थापना की थी। पर तब का पार्टी नेता विनसेंट लावा अमरीकी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राउडर के संशोधनवादी दिशा के प्रभाव में था। उसने फिलिप्पीन्स में अमरीकी साम्राज्यवाद के पुनरागमन का स्वागत किया और पीपुल्स आर्मी को निष्क्रिय बना दिया।

इस दक्षिणपंथी दिशा के खिलाफ हुए संघर्ष में उसका छोटा भाई, जोस लावा ने 1950 के दशक की शुरूआत में "वामपंथी" दिशा सामने लाई। उसने सशस्त्र उठावों की योजना बनाई। सैनिकी बल को बिना जनाधार के विस्तारित किया। शहरों में उठाव के लिए कुछ प्रतिक्रियावादी राजनीतिक गुटों से संबंध बनाया। फलस्वरूप वह प्रतिक्रियावादी शासक गुट की चालों में फंस गया और सशस्त्र क्रांतिकारी उठाव की बुरी तरह से हार हुई।

इस पराजय के बाद नेतृत्व में आए जीसस लावा ने फिर से दक्षिणपंथी अवसरवादी दिशा का वर्चस्व लाया। पीपुल्स आर्मी को संसदीय चुनाव में प्रचार संगठन बनाने का सुझाव रखा और पार्टी ढांचा तोड़ दिया। 1950 के दशक के अंत तक पार्टी का अस्तित्व ही नहीं के बराबर था।

इसी दौरान विश्वविद्यालयों तथा अन्य इलाकों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद से प्रेरित युवकों ने देश में उठे साम्राज्यवाद विरोधी जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका पार्टी से संबंध आया और उनके प्रतिनिधि को पार्टी नेतृत्व में लाया गया। नौजवान सर्वहारा क्रांतिकारियों ने पार्टी की प्रस्थापित दिशा का विरोध करते हुए दीर्घकालीन जनयुद्ध द्वारा नव जनवादी क्रांति की जरूरत पर जोर दिया। पार्टी इतिहास की समीक्षा शुरू की। पार्टी के भीतर संघर्ष में लावा ने संशोधनवादी सोवियत पार्टी की दिशा का समर्थन किया। अप्रैल 1967 में लावा और उसके समर्थकों से अलग होकर सर्वहारा क्रांतिकारियों ने पार्टी की पुनःस्थापना करने का निर्णय लिया। उनकी घोषणा बीजिंग रिव्यू में प्रकाशित हुई।

पार्टी के पहले भूल-सुधार आंदोलन अभियान की तैयारी हुई। उन्होंने पार्टी दस्तावेज लिखे, पार्टी का संविधान तैयार किया और नव जनवादी क्रांति का कार्यक्रम बनाया। फिलिप्पीन्स में क्रांति की विशेषताएं स्पष्ट की। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को अपना सिद्धांत स्वीकार किया। 26 दिसंबर 1968 को सी.पी.पी. की पुनःस्थापना की गई। तीन महीने बाद नई जनसेना - न्यू पीपुल्स आर्मी - का गठन किया गया।

एनपीए का गठन करने के लिए उन्होंने पुराने पीपुल्स आर्मी पर नियंत्रण रख रहे गुन्हेगार नेतृत्व की आलोचना की, पुराने सैनिक और नए भर्ती सैनिकों को राजनीतिक शिक्षण दिया। पुरानी सेना के अधिकतर योद्धाओं को वे जीत पाए। 29 मार्च 1969 को न्यू पीपुल्स आर्मी की स्थापना की घोषणा की गई और जनयुद्ध शुरू करने का भी ऐलान किया गया। तब एनपीए 60 योद्धाओं और 36 बंदूकों से थी।

फिलिप्पीनी क्रांति की विशेषताएं और क्रांति की दिशा

पुनःस्थापना के बाद सी.पी.पी. ने अपने समाज का विश्लेषण मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा के आधार पर किया। उसका निष्कर्ष था कि 1896 में उपनिवेशवाद और सामंतवाद के खिलाफ पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में हुई क्रांति आधूरी थी। अब भी राष्ट्रीय जनवादी कार्य पूरा करना बाकी रह गया है। अब यह जनवादी क्रांति नया रूप लेगी जिसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग को करना है। यह क्रांति विश्व सर्वहारा क्रांति का हिस्सा होगी।

फिलिप्पीन्स एक अर्ध-सामंती और अर्ध-उपनिवेशी देश है। दीर्घकालीन जनयुद्ध के जरिए दलाल बड़े पूंजीपति और जमींदारों का तख़्ता पलटा जा सकता है। यह युद्ध ग्रामीण इलाकों में चलाना होगा। सर्वहारा की क्रांतिकारी पार्टी ही इस युद्ध का नेतृत्व कर सकती है। उनका मुख्य और विश्वसनीय दोस्त किसान है। देहाती इलाका न सिर्फ अनुकूल धरातल प्रदान करता है, बल्कि वह ऐसा

सामाजिक भूभाग है जिसमें सर्वहारा व्यापक किसान जनता को संगठित करके उसे जनयुद्ध के लिए गोलबंद किया जा सकता है। इस तरह नव जनवादी क्रांति की नीव - मजदूर एवं किसान वर्गों की एकता सचाई बन सकती है।

फिलिप्पीन्स में क्रांति सफल करने के लिए वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थिति पर भी ध्यान दिया गया। फिलिप्पीन्स प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है। दुश्मन की ताकत को बांटने के लिए इन द्वीपों, उनमें मौजूद पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा सी.पी.पी. ने विश्लेषण किया। शुरू में देश का यह द्वीप-चरित्र एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने में समस्या बनकर था। लेकिन वे राष्ट्रव्यापी जनयुद्ध विकसित करने में सफल हुए और इस प्रारंभिक भौगोलिक असुविधा को दूरगामी सुविधा में परिवर्तित कर सके। "बड़े द्वीप पहले, छोटे द्वीप बाद में," और "केंद्रीकृत नेतृत्व और विकेंद्रीकृत कार्रवाइयां" - इन मार्गदर्शकों के आधार पर सी.पी.पी. और एनपीए अपने आपको उन 11 बड़े द्वीपों में फैलाने में सफल हुईं, जिनमें देश की 94% आबादी रहती है।

पुनःस्थापित सी.पी.पी. ने राष्ट्रीय जनवादी लड़ाई को क्रांतिकारी वर्ग दिशा के अनुसार चलाना शुरू किया। मजदूर-किसान एकता नव जनवादी क्रांति की नींव है। शहर का निम्न पूंजीपति वर्ग भी एक आधारभूत शक्ति के रूप में जीता जा सकता है। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग भी एक सकारात्मक शक्ति है, पर उसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में सावधान रहना जरूरी है। मुख्य शासक वर्गों के भीतर अंतरविरोधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह सबसे प्रतिक्रियावादी गुट जो साम्राज्यवाद से अधिक अधीनता दर्शाता है, को अलग-थलग कर पराजित किया जा सकता है। इस तरह, एक के बाद एक को पराजित किया जा सकता है जब तक कि सारी शासक व्यवस्ता ही खत्म न हो। इस वर्ग दिशा के आधार पर सी.पी.पी. ने संयुक्त मोर्चे के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अनेक औपचारिक और कई गैर-औपचारिक रिश्ते-गठजोड़ बनाए गए हैं। सशस्त्र संघर्ष के समर्थन में एक औपचारिक मंच कार्यरत है - राष्ट्रीय जनवादी जनता का मंच (एनडीएफपी)। पार्टी की समझ यह है कि क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष ही संघर्ष का प्रधान रूप है क्योंकि उसी के द्वारा क्रांति का केंद्रीय प्रश्न - प्रतिक्रियावादियों से सत्ता हथियाना - संभव है। प्रतिक्रांतिकारी राज्य व्यवस्था की फौजी नौकरशाही को नेस्तनाबूद करने का यह प्रमुख तरीका है। पर उसके साथ कानूनी संघर्ष भी जरूरी है, भले ही वह द्वितीय क्यों न हो। इसलिए सी.पी.पी. ने शुरू से ही शहरों पर आधारित कानूनी जनवादी जन आंदोलन और देहात में सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का समन्वय करती आई है। दोनों आंदोलनों ने एक-दूसरे के विकास की सहायता की है।

फिलिप्पीन्स में सशस्त्र संघर्ष का विकास

1969 में सी.पी.पी. की पुनःस्थापना और एनपीए के गठन के बाद सशस्त्र संघर्ष के विकास को तीन चरणों में देखा जा सकता है। 1968 से 1979 तक पहला चरण जब सशस्त्र संघर्ष की नींव रखी गई थी, 1980 से 1991 तक दूसरा चरण जब क्रांतिकारी शक्तियों का महत्वपूर्ण विकास हुआ पर "दक्षिणपंथी" और "वाम-पंथी" अवसरवादी रुझानों ने संघर्ष को कमजोर किया और तीसरा चरण 1992 से वर्तमान काल तक जब दूसरा भूल-सुधार अभियान चलाया गया है।

पहले चरण में, पार्टी के पुनरनिर्माण के बाद, देश के उन प्रमुख केंद्रों में काडर भेजे गए जहां जनयुद्ध चलाना था। शहरों में जन आंदोलन तेज किया गया। 1972 में जब सैनिकी शासक मार्कोस द्वारा घोषित किए गए व्यापक और भयंकर दमन अभियान का दौर शुरू हुआ, तब उसका सामना करते हुए पार्टी को बचाने में, सशस्त्र संघर्ष तेज करने में और शहरों में भूमिगत जन शक्तियां विकसित करने में पार्टी सफल रही। लगातार दमन के बावजूद मार्कोस की फासीवादी तानाशाही सी.पी.पी. और एनपीए को कुचलने में पूरी तरह नाकामयाब रही।

दूसरे चरण में पार्टी और नई जन सेना के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ी। जनयुद्ध तेज हुआ, करीब 60 गुरिल्ला फ्रंटों में कार्य चल रहा था। फासीवादी तानाशाही के खिलाफ कानूनी जन आंदोलन तेज हुआ (1983-86)। इन सफलताओं के साथ पार्टी में मनोगतवाद और अवसरवाद के रुझानों ने केंद्रीय नेतृत्व के एक हिस्से में घर बसाया। कुछ कॉमरेड पार्टी की राजनीतिक-संगठनात्मक दिशा पर प्रश्न करने लगे। फिलिप्पीनी समाज का वर्ग चरित्र बदल गया है, वह अर्ध-सामंती नहीं रहा, ऐसा कहकर वे रणनीति बदलने की वकालत करने लगे। इसमें दोनों `वाम' और `दक्षिण' दिशाएं उभरीं। जहां वाम दिशा शहरों में उठाव करने के पक्ष में थी, एनपीए की यूनिटों को लोकयुद्ध के विकास के चरणों की उपेक्षा करते हुए, कंपनी और उसके भी ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रही थी, जन कार्य की जगह सिर्फ फौजी कार्य को महत्व देना शुरू किया, वहीं दक्षिणपंथी शहरी कानूनी आंदोलन को संघर्ष का प्रधान रूप समझने लगे, गैर-सर्वहारा सिद्धांतों का समर्थन करने लगे, संयुक्त मोर्चे पर पार्टी का नेतृत्व समाप्त करने की कोशिश करने लगे। आगे चलकर दोनों प्रवाह एकजुट हो गए, दोनों विदेशी मदद की अपेक्षा में आधुनिक संशोधनवाद का समर्थन करने लगे। इन दोनों गलत `दिशाओं' का पार्टी एवं एनपीए पर बुरा असर पड़ा। जनाधार सिकुड़ गया, शहरों की भूमिगत युनिटें दुश्मन को मालूम हो गईं, अवास्तविक स्तर पर बढ़ाई एनपीए की यूनिटें निष्क्रिय हो गईं। 1988 में ही पार्टी में आलोचना शुरू हुई। आखिर 1991 में केंद्रीय कमेटी ने ठोस परिस्थिति का जायज़ा लेकर दूसरी भूल-सुधार मुहिम शुरू की। इस भूल-सुधार मुहिम के दौरान अवसरवादी तत्व अलग-थलग पड़ गए और उनमें से कई को दुश्मन ने समाजवाद विरोधी प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया।

तीसरा चरण दूसरे भूल-सुधार अभियान के साथ शुरू हुआ। उसमें विचारधारात्मक एवं राजनीतिक शिक्षण का दौर चलाया गया। अपने-अपने क्षेत्रों में गलत दिशा का असर की समीक्षा की

गई, और ठोस कार्यों के अमल की प्रक्रिया शुरू की गई। इस चरण के पहले कुछ वर्षों में जनता के बीच कार्य को प्रधान महत्व दिया गया। एनपीए की क्रांति में भूमिका फिर एक बार स्पष्ट की गई और इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन धीरे-धीरे फैलने लगा। पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का शिक्षण पर ध्यान दे रही है। पांच फिलिप्पीनी भाषाओं में पार्टी साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य और पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं।

एनपीए की भूमिका

सी.पी.पी. अध्यक्ष अरमान्डो लिवानाग के शब्दों में, "न्यू पीपुल्स आर्मी का केंद्रीय कार्य है दलाल बड़े पूंजीपति एवं जमींदारों की राज्यसत्ता का नाश करना ताकि मजदूर वर्ग और किसान जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना कर सके। पर लड़ाई के ये कार्य पूरे करने हैं तो उसे व्यापक जनता को अपने राष्ट्रीय एवं जनवादी अधिकारों और हितों को बढ़ाने के लिए जागृत करना, संगठित करना और गोलबंद करना जरूरी है। एनपीए को लगातार जन कार्य करना होगा ताकि अपने केंद्रीय कार्य को एक मजबूत नींव मिले, ताकि उसका ताकत का स्रोत कभी खत्म न हो, ताकि जनता के सबसे अच्छे बेटे और बेटियां भर्ती होते रहें। व्यापक जनता भी एनपीए को चाहती है, उसे पोसती है सिर्फ इसलिए कि वह उसकी सेवा करती है और उसके अधिकारों और हितों के लिए लड़ती है। एनपीए को चाहिए कि वह क्रांतिकारी राजनीति को ही हमेशा सर्वोपरि रखे। इस सेना को पूरी तरह से फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्वीकारना है और पार्टी द्वारा तय किया हुआ जनवादी क्रांति के कार्यक्रम पर अमल करने का मुख्य संगठन के रूप में काम करना है। उसे जनदिशा - यानी जनता से सीखो, उस पर विश्वास करो, उस पर निर्भर रहो के आधार पर चलना है।"

वर्तमान परिस्थिति

सी.पी.पी. की समझ यह है कि, "विश्व पूंजीवाद के बढ़ते संकट के कारण शासक वर्गों की सत्ता भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संकट में फंसी हुई है। साम्राज्यवादी अमरीका का समर्थन प्राप्त एस्ट्राडा सरकार भी घोर संकट में फंसी है। जन आंदोलन और एनपीए के बढ़ते हमलों से यह पूरी राज्यव्यवस्था निश्चित ही और कमजोर हो जाएगी। वर्तमान स्थिति क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए अनुकूल है।

पार्टी के भूल-सुधार अभियान के बाद संपूर्ण पार्टी और एनपीए के भीतर पार्टी को नई ऊर्जा मिल चुकी है - लाल योद्धाओं की राजनीतिक चेतना विकसित हुई है। भूल-सुधार मुहिम के साथ फुले हुए एनपीए की यूनिटों को पुनरगठित करके उन्हें जन कार्य में भिजवाया गया ताकि खोया हुआ जनाधार फिर एक बार मजबूत किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से एनपीए की आक्रमणकारी कार्रवाइयां धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं। ये कार्यनीतिगत आक्रामक कार्रवाइयां बढ़ती हैं जैसे जनाधार बढ़ता है, किसी गुरिल्ला जोन में, किसी गुरिल्ला फ्रंट में, किसी रीजन में।

1999 में एनपीए की कुल ताकत कई रेजिमेन्टों के बराबर ही थी। एनपीए अब 13 सामरिक इलाकों में 81 गुरिल्ला फ्रन्टों में कार्यरत है। साधारण रूप से एक गुरिल्ला फ्रन्ट में एक कंपनी के बराबर की कुल ताकत रहती है। इसमें, केंद्र में है एक प्लाटून और बाकी बल केंद्र से हर दिशा में छोटे दस्तों में फैला हुआ है। वे जनता को संगठित करने में लगे हैं। कई रीजन में मुख्य गुरिल्ला यूनिट अनेक गुरिल्ला फ्रन्टों को एक-दूसरे से बांध लेता है तब एनपीए उन इलाकों में रीजन स्तर पर कार्रवाइयां कर सकती है। आज हजारों स्त्री-पुरुष एनपीए में पूर्णकाल सेवा कर रहे हैं। और दसियों हजार जन मिलिशिया, आत्म रक्षा दस्ते में अपनी ताकत में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। अब एनपीए के समर्थन से स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक सत्ता की संस्थाएं खड़ी हैं, हालांकि शहरों में प्रतिक्रियावादी सरकार मजबूत है। यानी अब फिलिप्पीन्स में दो प्रकार की सरकारें चल रही हैं। दीर्घकालीन लोकयुद्ध द्वारा इस प्रतिक्रियावादी सरकार को खत्म करके क्रांतिकारी जनवादी सरकार उसकी जगह लेगी।

हालांकि एस्ट्राडा सरकार ने सैनिक शासन घोषित नहीं किया है, पर उसी तरह का दमन ला रही है। एस्ट्राडा सरकार ने क्रांतिकारी संयुक्त मंच - एनडीएफपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत शुरू की गई शांति वार्ताओं से गद्दारी की है। पर सी.पी.पी. जनयुद्ध को और तेज करते हुए और संयुक्त मोर्चे को व्यापक करते हुए एस्ट्राडा सरकार को अलग-थलग कर देने में कामयाब रही है। फिलहाल एनडीएफपी ने मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रन्ट के साथ साझा गठबंधन बनाया है। वैसे एनपीए के कई आक्रामक कार्रवाइयों को व्यापक प्रचार मिला है। दो बार उसने पुलिस एवं फौज के कई बड़े अधिकारियों को पकड़ा और वार्ता के द्वारा अपनी मांगें हासिल करने के बाद ही उनको रिहा किया।

इस तरह फिलिप्पीनी जनता की मुक्ति के साथ-साथ विश्व समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से फिलिप्पीन्स में सी.पी.पी. के नेतृत्व में लोकयुद्ध आगे बढ़ रहा है। ✪

(.... पृष्ठ 35 का शेष)

लिए छुपाए रखना संभव नहीं है। इतिहास में यह सचाई साबित हो चुकी है कि कोई भी कुछ ही लोगों को कुछ ही समय तक ही धोखा दे सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इसी तरह बालाघाट पुलिस भी सभी को हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकती, भ्रम में नहीं रख सकती। दूसरी ओर बालाघाट की जनता पुलिसिया दमन के कई तरीकों को देख चुकी है। लेकिन वह लड़ने और आन्दोलन करने से कभी पीछे नहीं हटी है। अब भी पुलिस अगर यह समझती है कि गांवों को खाली करवाने जैसे दमनात्मक तरीकों से बालाघाट की जनता संघर्ष की राह छोड़ देगी, उससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष की राह पर चल रही बालाघाट की जनता यह बात साबित भी कर रही है। ✪

बजट **2001-02**

लुटेरों का बजट लुटेरे वर्गों की ही भलाई करेगा !

हर साल 28 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाना एक रिवाज सा ही चलता आ रहा है। कहा जाता है कि यह अंग्रेजों की परंपरा ही है। यह हर साल एक ड्रामा जैसा होता है। संक्षेप में कहा जाए, तो बजट का मतलब है सरकार की अनुमानित आय और खर्च का वार्षिक परचा और उसमें तालमेल बिठाने का विवरण। हर साल यह बात देख ही रहे हैं कि संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद, जहां एक ओर विपक्षी पार्टियां आलोचनाओं का अंबार लगा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तारीफ के पुल बांधता है। इसके अलावा, बड़े उद्योगपतियों और संपन्न वर्गों का एक वर्ग हमेशा बजट की प्रशंसा करता है, तो अपनी कुछ छिटपुट मांगें पूरी न होने से नाराजगी जताने वाला एक वर्ग भी हमेशा रहता है। इस बार 32 प्रमुख इजारेदार पूंजीपतियों ने "अच्छा है" कहकर बजट को आसमान पर चढ़ाकर प्रशंसा की। उधर, बहुराष्ट्रीय निगमों और विश्व के आर्थिक संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी यह कहकर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं कि यह बजट उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। इस तरह के वार्षिक बजटों से गरीबों की उन्नति की उम्मीद करना नादानी ही होगा और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बजट को तैयार करने की बात करना जनता के साथ छलावा ही होगा। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इन बजटों से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। प्रस्तुत लेख में इस बजट का विश्लेषण करके यह जान लेंगे कि भारत सरकार साम्राज्यवादी संस्थाओं और संपन्न लोगों के सामने किस तरह घुटने टेक रही है।

पिछले साल (2000-01) का बजट पेश करते हुए भारत के वित्त मंत्री यश्वन्त सिन्हा ने कई वरदान दिए और वादे किए थे। भारत द्वारा 8% विकास हासिल करने का दावा किया था। राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत 13 तक बढ़ाने की बात कही। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, यानी उन्हें बेचकर 10 हजार करोड़ रुपए जुगाड़कर बजट घाटे को पाटने की बात भी कही। घाटे का हल काला धन बाहर लाने और प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत बढ़ाने में ढूंढ़ने के बजाए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, 9वीं पंचवर्षी योजना में बताए गए मदों पर 88,100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की थी। गैर-योजना व्यय को कम करने की घोषणा भी की। सकल घरेलू उत्पाद 7% बढ़ाने की बात कही और 9% बढ़ाना सरकार का मकसद बताया। बैंकों के पास मौजूद 53 हजार करोड़ बुरे कर्जों को किसी तरह वसूलने की बात कही। इस तरह के कई वादे सिन्हा ने किए थे। लेकिन जहां तक इन पर अमल का सवाल है, परिणाम उलटे रहे हैं। इस बार भी सिन्हा ने अपने बजट भाषण में हमेशा की तरह मीठे वादे किए। आगामी 10 सालों को विकास के दशक का नाम दिया। इस दौरान देश में से गरीबी को खत्म करने की गंभीर बात भी कही। देश के इतिहास को जानने वालों को यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब झूठे वादे ही हैं। आम आदमी यह जान गया है कि यह सब गरीबों के वोट लूटने के लिए, सत्ता का सुख हमेशा भोगते रहने के लिए लुटेरे नेताओं द्वारा की जाने वाली तिकड़मबाजी ही है। आइए, अब यह देखें कि इस बार किस मद पर कितना आवंटन किया गया है। यह भी देखें कि उनका तथाकथित विकास-पथ क्या है।

सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत एक दिवास्वप्न ही बनकर रह गया तथा वह 6 प्रतिशत और उससे कम पर ही कई सालों से अटक गया है। कृषि क्षेत्र `नकारात्मक विकास दर' का शिकार हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था का एक-तिहाई हिस्सा कृषि-क्षेत्र के लिए आवंटित राशि कुल बजट व्यय का 0.86% (यानी 3,38,487 करोड़) ही है। सकल घरेलू उत्पाद में तो 0.13% ही (21,81,862 करोड़) ही खर्च करेंगे। पहले से काफी बड़े संकट से गुजर रहे देश के कृषि-क्षेत्र के लिए यह राशि एक दम अपर्याप्त है। पूरे देश में 37 प्रतिशत जमीन को ही पानी मिल रहा है। करीबन 8 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपयोग में नहीं लाया गया जिसमें आधी जमीन खेती लायक है। उसे उपयोग में लाना है तो पैसा चाहिए जो यह लुटेरी सरकार नहीं देती। देश में मौजूद 15 प्रतिशत दलितों और 8 प्रतिशत आदिवासियों की बहुसंख्या भूमिहीन और गरीब किसानों की ही है। बड़े-बड़े जमींदारों के पास जमीन के भारी-भरकम रकबे मौजूद हैं। वास्तव में जोतने वालों के पास जमीन ही नहीं रह गई। इसलिए देश में जोतने वाले की ही जमीन के आधार पर खेतिहर क्रांति को सफल बनाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया है।

अब उद्योग पर नजर डाली जाए। औद्यौगिक विकास दर पिछले साल के मुकाबले एक प्रतिशत घटकर 4.3 प्रतिशत के पास अटक गई है। हालांकि पिछले तीन सालों से सेवा-क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन वह भी अब उतार पर है। पिछले साल के 9.6% के मुकाबले इस वर्ष 8.3% रह गया। सेवा-क्षेत्र की प्रगति पानी का बुलबुला सिद्ध हुई। विकास दर के 7 से 6 प्रतिशत तक लुढ़कने के पीछे सेवा-क्षेत्र का पतन ही कारण है।

बेरोजगारी साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। राजग सरकार ने सालाना एक करोड़ नौकरियां देने, 10 सालों में 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इसके लिए सरकार को सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित किया गया। जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाते हुए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करते हुए, वहीं दूसरी तरफ सालाना एक करोड़ नौकरियां देने की बात करना छलावा ही है। यहीं पर खुद प्रधानमंत्री

की बातों को याद करेंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार की नौकरियों में सालाना 10% कटौती करने की बात कही जिस पर अब वास्तव में अमल किया जा रहा है। साम्राज्यवादियों और विश्व के मुद्रा संस्थानों की शर्तों के तहत ही यह हो रहा है। मिसाल के तौर पर 1990 तक रेल विभाग को छोड़कर केन्द्र सरकार के उपक्रमों में 194 लाख कर्मचारी रहा करते थे, जबकि 1997-98 तक 32.5 लाख घटकर 158.5 लाख हो गए। इसमें और भी तेजी से गिरावट होने के आसार बाल्को आदि सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से साफ नजर आ रहे हैं। बाल्को की बिक्री का विरोध करते हुए 3 मार्च से 7,000 से अधिक मजदूर हड़ताल पर गए थे। और कई सार्वजनिक कंपनियां निजीकरण की सूची में हैं। नेहरू के बताए इन `मंदिरों' का क्या हश्र होने वाला है और नेहरू के बताए कल्याणकारी राज्य में औद्योगिक विकास का कैसे नाश हुआ है, साफ देखा जा सकता है।

कंपनियों से और विभिन्न संस्थाओं से मजदूरों को नौकरियों से हटाकर सड़कों पर फेंक देने के अलावा इस बार के बजट में श्रम कानूनों में फेरबदल करके सिन्हा ने मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया। मौजूदा श्रम कानूनों के मुताबिक जिस कंपनी में 100 मजदूर होंगे उसे भारत सरकार के कानूनों का पालन करना होगा। ऐसा होने से कानूनी रूप से पूंजीपतियों को हो रही दिक्कत के चलते 100 मजदूरों के बजाए 1000 मजदूर होने से उसमें श्रम कानून लागू करने की बात कही गई। इससे परोक्ष रूप से मजदूरों को सड़कों पर फेंका जाएगा। 2001 तक देश में 16 करोड़ बेरोजगार मौजूद हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री पर नजर डाली जाए। सभी सरकारें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह हामी भरती आ रही हैं कि सरकारी कंपनियों को बेचकर बजट घाटा पाटा जाएगा। ऐसा करने से होने वाले परिणामों पर नजर डाली जाए। सालाना 10 हजार करोड़ शेयर बेचने की तमन्ना रखने के बावजूद विदेशी कंपनियां आसानी से आगे नहीं आ रही हैं। वर्ष 1991 में 5.3 अरब रुपए की स्वीकृति के बावजूद 3.5 अरब रुपए ही पहुंचे हैं। इसमें साल-दर-साल कमी होती रही और आखिर, सितंबर 2000 तक 286.6 अरब रुपए की स्वीकृति हुई तो 111.1 अरब ही पहुंचे हैं। मतलब, विदेशी कंपनियों की मंशा है कि सरकारों को और भी समर्पित होने पर मजबूर कर दिया जाए। अभी तक एमआरपीटी, फेरा जैसे कानून कूड़ेदान में फेंक दिए जा चुके हैं। देशीय बैंकों से उन्हें बड़ी मात्रा में कर्ज दिए जा रहे हैं। 1980 के दशक में कंपनियों के विलय और टेकओव्हर की कुल 30-35 घटनाएं हुई थीं। अब राजग सरकार ने विनिवेशीकरण के लिए बाकायदा एक मंत्री को ही नियुक्त कर डाला और बिक्रियों में तेजी लाने के लिए कमर कस ली। घोरतम विषय यह है कि खुद सरकार इन्हें ऋण दे रही है। उदाहरण के लिए 1999 में लाफार्ज ने 550 करोड़ रुपए में टिस्को स्टील कंपनी को टेकओव्हर किया तो आइसीआइसीआइ और दूसरी सरकारी वित्त संस्थाओं ने 215 करोड़ का ऋण दिया। 1998 में एक्केक्ट्रोलक्स ने एबी को 100 करोड़ का ऋण देकर वोल्टास के 160 करोड़ के शेयर दे दिए। भारत की जनता विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अपने बचे-खुचे पैसे जमा करने लगी है तो सरकार इस तरह वह धन दलाल पूंजीपतियों और विदेशी संस्थाओं को दे रही है जोकि जनता के साथ साफ तौर पर गद्दारी ही है।

अब विदेशी आयातों पर नजर डाली जाए। अमरीका के दबाव के सामने झुकते हुए, बिल क्लिन्टन की भारत यात्रा के पहले ही सरकार ने 714 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा दिए थे। अप्रैल 2001 तक बाकी 715 वस्तुओं पर भी प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। ये सब परदे के पीछे गुप्त तरीके से चलते हुए आखिर में जनता के सामने आ रहे हैं। 1990-91 में नई आर्थिक नीतियों को शुरू करने के बाद से आयातों में अंधाधुंध इजाफा होता गया और स्वदेशी उद्योग - घरेलू और छोटे उद्योग - बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के सामने समर्पण करके विदेशों से किए जा रहे आयातों से भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र समस्याएं झेल रहा है। 1995 में कृषि आयात 5 हजार करोड़ रुपए के हुआ करते थे जो 1999-2000 तक 20,000 करोड़ तक बढ़ गए। लेकिन निर्यातों में इस दर से वृद्धि नहीं हुई। जिन वस्तुओं पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए उनमें गेहूं के आटे से लेकर नमक, चप्पलें, झाड़ू, बीडी, प्याज, ककड़ी, ब्रश तक शामिल हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि देशीय बाजार में किस पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की बाढ़ सी आएगी। अखबारों में ये खबरें छप ही रही हैं कि चीनी वस्तुओं से बाजार भरे जा रहे हैं। आयात शुल्क पर स्लैब को 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक घटा दिया गया जिससे 1428 करोड़ रुपए की आय कम हो रही है। ये सब हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले और विदेशी कंपनियों को भारी मुनाफे बटोरने वाले फैसले ही थे।

जहां तक कर वसूली की बात है, सरकार संपन्न वर्गों को तो छूट दे देती है, लेकिन गरीबों से जबरन वसूलती है। कर दो प्रकार के होते हैं - प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर। करों से होने वाली कुल आय में परोक्ष करों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है जिससे गरीबों की तकलीफें बढ़ रही हैं। विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले कर और शुल्क इस श्रेणी में आते हैं। पोस्टकार्ड, माचिस जैसी वस्तुओं, जिनकी जरूरत गरीबों को होती है, पर सरकार ने इस वर्ष 4,700 करोड़ से ज्यादा उत्पादन शुल्क बढ़ाया। सकल घरेलू उत्पाद में करों से होने वाली आय 1980-81 में 13 प्रतिशत रही, जो फिलहाल 9 प्रतिशत तक घट गई। इस कमी में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा ही ज्यादा है। प्रत्यक्ष करों में सरकार ने सिर्फ इस एक वर्ष में ही 5,500 करोड़ रुपए की रियायत दी है। अमीर लोगों द्वारा अपनी आय पर चुकाए जाने वाले कर और कार्पोरेट क्षेत्र पर उसकी संपत्तियों पर लगने वाले कर इस श्रेणी में आते हैं। रिलाएन्स इंडस्ट्रीज़ के पैदा होने के बाद बीते 28 सालों में उसने कभी भी कार्पोरेट कर नहीं चुकाया। `फोर्ब्स' पत्रिका द्वारा प्रकाशित विश्व के 50 धनाढ्यों की सूची में

6.6 अरब डालर की आय वाली रिलाएन्स कंपनी भी शामिल है जिससे उसके विकास के रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ही बैंकों के पास मौजूद संपन्न वर्गों के बुरे कर्ज 53 हजार करोड़ हैं। इन कर्जों को वसूलने की राजनीतिक ईमानदारी सरकारों को नहीं है। यह धन पूरा गरीबों द्वारा विभिन्न रूपों में इकट्ठा की गई बचतें ही है। दूसरी तरफ, इस बार सिन्हा ने बैंकों से अमीरों को ऋण लेने में ब्याज दरें बड़ी बाधा बनी हुई हैं कहकर ब्याज दरों में कटौती की जोकि गरीबों की बचतों पर सीधी मार है। अमीर लोगों से बुरे कर्ज वसूलने में अक्षम सरकारी अधिकारी गरीबों से तो पाई-पाई वसूलते हैं। आदिवासी बहुल बस्तर जिले में पिछले साल बैंकों ने आदिवासियों से पुलिस जुल्म का सहारा लेकर वसूला। मध्ययुगीन बर्बरता को भुला देते हुए पुलिस थानों में किसानों की पीठों पर पत्थर लादकर कर्ज वसूले गए। इस बर्बरता को छुपाकर मध्यप्रदेश सरकार ने शर्म-हया छोड़कर घोषित किया कि कर्जा वसूली में बस्तर जिला सबसे ऊपर है। इससे साफ नजर आता है कि देश के शासक और उनका पुलिस अमला किसके पक्षधर हैं।

इस बजट में पेश किया गया एक और खतरनाक प्रस्ताव यह है कि जन वितरण प्रणाली को सीमित करके राज्यों के जिम्मे छोड़ देना। देश में लंबे अरसे से जन वितरण प्रणाली अमल में होने से ही गरीबी पर अंकुश लगा हुआ है कहकर तारीफ करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता आमर्त्य सेन अब क्या कहेंगे, देखने की बात है! जन वितरण प्रणाली को सीमित करने का अर्थ है उसका नाश करना ही।

अब यह देखें कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की गतिविधियां कैसी रही हैं। देश के आधा दर्जन राज्यों में जनता बाढ़ या सूखे से दो-चार है तो सरकारी गोदामों में 185 करोड़ रुपए का खाद्य अनाज सड़ गया है। 1999-2000 में संसदीय कमेटी ने इसकी समीक्षा करके सुझाव दिया कि 2,05,520 टन सड़े हुए खाद्य अनाज को गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। इसे इसी तरह भण्डारित करने से सालाना 400 करोड़ रुपए का खर्च झेलने पड़ने की बात भी कही गई। वाकई, यह भारत के इतिहास में ही अभूतपूर्व है। इतिहास में अब तक यही देखा गया है कि बड़े संकटों के समय में साम्राज्यवादी देशों में ही ऐसा हुआ है। हमारे देश जैसे एक पिछड़तम देश में गरीबों के पेट पर लात मारकर अनाज को सड़ाकर फेंकना लुटेरे शासक वर्गों की बदतर नीतियों का ही परिणाम है।

यहां एक नजर कीमतों पर भी डाली जाए। केन्द्र सरकार ने नवंबर 2000 में इराक, फिलिप्पीन्स और बंग्लादेश को गेंहू निर्यात करने का समझौता किया। कीमत 90 डालर (4,200 रुपए) प्रति टन निर्धारित की गई। यानी रु. 4.20 प्रति किलो! दूसरी तरफ यहां के बाजारों में लोगों को रु. 7.25 प्रति किलो के भाव से गेंहू बेचा जाता है। यह भाव आटा मशीनों का है, फुटकर दुकानों में भाव 9 रुपए से भी ज्यादा है।

इस बजट में पेयजल पर 2,100 करोड़, शिशु कल्याण पर 1,051 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पर 5,000 करोड़, इंदिरा आवास योजना पर 1,500 करोड़ और ग्रामीण गृह-निर्माण पर 1,710 करोड़ - कुल मिलाकर 11,362 करोड़ आवंटित किए गए। रक्षा विभाग पर 13,000 करोड़ बढ़ाया गया जिससे कुल रक्षा आवंटन 58,587 करोड़ हो गया। रक्षा से जन कल्याण पर 47,225 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए। जाहिर है सरकार जन कल्याण के मुकाबले सुरक्षा की चिंता ही ज्यादा है। गौरतलब है कि बोफोर्स काण्ड, तहलका काण्ड जैसे घोटालों की जननी यही रक्षा विभाग है।

इस तरह किसी भी क्षेत्र पर नजर डाली जाए, तो यही पता चल जाता है कि इस बजट में गरीबों को फायदा पहुंचाने वाला एक भी कदम नहीं है। गरीबों को और भी गरीब बनाने वाले कदम ही इस बजट में अधिक हैं। देश का विदेशी ऋण 1998-99 में 4,18,460 करोड़ रहा और अंदरूनी ऋण 4,58,800 करोड़ रहा है - कुल मिलाकर 8,77,260 करोड़ ऋण है। पोकरण आणविक परीक्षणों के बाद विश्व बैंक के ऋणों पर अब तक रोक लगी हुई थी जो इस वर्ष के अप्रैल माह से हटा दी गई। तो अब साफ है कि कर्जों का बोझ बढ़ता ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आए दिन भुखमरी, कर्जों का बोझ, अपमान और अत्याचार सहते हुए जीने की विवशता से प्रत्येक देशवासी बाहर आना पसंद करेगा। भारत की जनता की सच्ची आजादी और सम्मानपूर्वक अस्तित्व के लिए नव जनवादी क्रांति ही एक मात्र रास्ता है। ✪

बहीगांव में जनता पर पुलिस की लाठीचार्ज और दमन का विरोध करो !

बस्तर जिला केशकाल तहसील के बहीगांव में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का हम विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 पर स्थित बहीगांव में आदिवासियों ने इमली का घोषित वजिब दाम (5 रुपए प्रति किलो) और खरीदी की मांग की, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके किसानों को घायल किया। इससे क्रोधित हो उठे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, तो पुलिस ने 35 लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। 16 लोगों को गिरफ्तार करके बिना जमानत के जेल में बंदी बनाकर रख दिया। और बाकी 19 लोगों के लिए तलाशी जारी है। हम पुलिस की गैर-जनवादी कार्रवाइयों की निंदा करते हुए मांग कर रहे हैं कि बेकसूर किसानों को रिहा किया जाए और उन पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाए।

स्पेशल जोनल कमेटी,

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]

दण्डकारण्य

दमन-प्रतिरोध

पुलिस अफसरों का भाड़े का टट्टू और होमगार्डों का मुखिया बुरका बसवैया एक्शन टीम के हाथों कुत्ते की मौत मरा !

बुरका बसवैया पश्चिम बस्तर डिवीजन के मद्देड एरिया स्थित आवापल्ली रेन्ज के ग्राम संड्रेड का निवासी था। हालांकि 1990 के पहले यह डीएकेएमएस में शामिल था, लेकिन 1990 के बाद चले जन जागरण अभियान के दौरान इसने गांव के दुष्ट मुखियाओं से सांठगांठ कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। बाद में मुखियाओं और पुलिस की मदद से इसने अपनी जन विरोधी कार्रवाइयां तेज कर दीं। सेन्ड्रेड के अलावा, आसपास के गांवों के मुखियाओं के नियमित संपर्क में रहते हुए संगठन के खिलाफ एक गुण्डा नेता के तौर पर उभरा था।

उस समय की दक्षिण बस्तर डिवीजन पार्टी ने 1991 के बाद `जवाबी जन जागरण अभियान' छेड़कर पुलिस को सहयोग देने वाले और संगठन के खिलाफ काम करने वाले मुखियाओं को सबक सिखा दिया था। इस अभियान के तहत जनता ने आवापल्ली रेन्ज के कई गांवों के मुखियाओं के खिलाफ पिटाई, जन अदालतें, जुर्माना वसूलना आदि रूपों में मुखियाओं को दण्डित किया था। इस सिलसिले में कई गांवों में जन संगठनों का पुनर्निर्माण किया गया और गांवों में फिर से संगठनों का बोलबाला हो गया।

सेंड्रेड का पड़ोसी गांव बंडारुपल्ली में शुरू से ही हमारा संगठन काफी मजबूत रहा। 1990 के जन जागरण अभियान के दौरान भी यह गांव आन्दोलन के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा रहा था। इस गांव के संगठन नेता कामरेड चापा लच्चुमैया जो डीएकेएमएस के दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी सदस्य भी थे, आसपास के गांवों के बदमाश मुखियाओं को दण्डित करने में जनता का नेतृत्व करने लगे, तो बुरका बसवैया पुलिस को उनकी गतिविधियों का पूरा इत्तला दिया करता ता। 1994 में पुलिस ने कामरेड चापा लच्चुमैया को गिरफ्तार करके उनकी हत्या करके लाश को लापता कर दिया। उस इलाके के संगठन पर चोट करने में पुलिस ने बसवैया का इस्तेमाल किया।

1994 के आखिर में छापामार दस्ते ने जनता के सहयोग से इसके घर पर हमला करके इसे गिरफ्तार कर पिटाई करके चेतावनी दी। दस्ते को देर से यह पता चला था कि वह पहले ही होमगार्ड बन चुका था। इसके बाद वह संड्रेड से भागा और तहसील मुख्यालय बीजापुर में रहने लगा जो पुलिस बलों का मुख्य अड्डा भी है। वह वहां रहते हुए गांवों पर पुलिस की हरेक छापेमारी में पुलिस के साथ रहा। आत्मसमर्पण की नौटंकी को सफलता दिलाने के लिए उसने एड़ी-चोटी का जोर लगाया था - गांवों में मुखियाओं से सांठगांठ करके संगठनों में शामिल लोगों का पता लगाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना, यातनाएं देना, दस्ता सदस्यों के परिवारों पर दबाव डालना, दस्ते से घर वापिस जाने वालों का ब्यौरा जुटाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना आदि हरकतें करता रहा। इस तरह वह पुलिस का एक सक्रिय मुखबिर बन गया। मद्देड, नेशनल पार्क, भैरमगढ़, बासागूडा इलाकों में छापामार दस्तों का सफाया करने के इरादे से इसने पुलिस को काफी सहयोग दिया। पुलिस महानिदेशक मदन गोपाल पाण्डे, एसपी लांगकुमेर, हिमांशु गुप्ता जैसे क्रूर पुलिस अधिकारियों का वह दांया हाथ बना था।

हालांकि पूरे डिवीजन के लिए खतरा बने हुए बसवैया का सफाया करने का प्रस्ताव पार्टी की डिवीजनल कमेटी ने काफी पहले ही किया था, लेकिन वह जन छापामारों के हाथों में पड़ने से बचता रहा। इसका सफाया करने के लिए 4-5 बार की गई कोशिशें विफल हुईं। और इन कोशिशों का पता चल जाने से वह ज्यादा सावधानी से घूमने लगा।

आखिरकार 11 दिसंबर 2000 को बीजापुर के निकट, जगदलपुर सड़क पर स्थित नैमेड गांव के मुरगा बाजार में डिवीजनल कमेटी द्वारा गठित 4 सदस्यीय एक्शन टीम ने इसका सफाया किया और नारे लगाते हुए लोगों के बीच में से सकुशल वापिस आ गई। जनता का कट्टर दुश्मन बन चुके बसवैया की मौत से जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि एक्शन टीम की जोरदार ढंग से प्रशंसा की। बसवैया की मौत कई मुखबिरों और होमगार्डों के लिए एक चेतावनी है जो यह गलतफहमी पाले हुए हैं कि बीजापुर जैसे प्रतिक्रियावादियों के मुख्यालय में रहकर जान बचाई जा सकती है। ✪

पृथक नाग विदर्भ राज्य की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को गड़चिरोली जिला बंद सफल!

दण्डकारण्य के तीसरे अधिवेशन ने फैसला किया कि पृथक नाग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जनांदोलन खड़ा किया जाए। इसके पहले भी, 1998 के मई माह में पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने संयुक्त बयान जारी करके विदर्भ के मुद्दे पर पार्टी का रवैया स्पष्ट किया था। हाल में गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने 26 जनवरी को बंद का आह्वान किया। इस मौके पर वितरित पर्चों, पोस्टरों और प्रेस वक्तव्य के माध्यम से पार्टी ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर जन संघर्ष का आह्वान किया। जिले के सभी तबकों की जनता ने बंद का पूरा समर्थन किया। स्कूलें, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, दुकानें आदि बंद रखी गईं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गई। गांवों में लोगों ने सब काम बंद रखकर बंद का पालन किया। बाद में डिवीजनल कमेटी ने एक बयान में बंद को सफल बनाने वाली जनता का क्रांतिकारी अभिवादन किया। ✪

नई सदी में पीजीए के छापामारों का पहला मौकाई घात हमला सफल !

बहादुर छापामारों को क्रांतिकारी बधाई !

माड़ डिवीजन में दिनोंदिन आगे बढ़ रहे क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए दुश्मन ने दमन और सुधार वाली दोहरी नीति अपनाई है। करोड़ों रुपए खर्च करके लागों को गुमराह करने के प्रायस लगातार जारी हैं। खासतौर पर यहां के नौजवानों को भ्रष्ट बनाकर उन्हें आन्दोलन से विमुख बनाने के लिए सरकार कई घिनौने हथकण्डे अपना रही है। और समय-समय पर यहां बड़े खोजबीन अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि छापामार दस्तों का सफाया किया जा सके। इसी तरह पुलिस वालों ने पिछले जनवरी महीने में माड़ अंचल में एक बड़ा दमन अभियान छेड़ दिया था। उस अभियान में कई बड़े पुलिस अफसर शामिल थे और कुल मिलाकर उनकी संख्या 60 के करीब थी। नारायणपुर से निकले पुलिस के इस दल ने कुतुल, कच्चापाल, इरकभट्टी आदि गांवों में छापेमारी की। इन सभी गांवों में पुलिस ने जनता द्वारा निर्मित शहीद स्मारक को तोड़ डाला। उनका आतंक का यह सिलसिला तब जाकर थम गया जब पीजीए के छापामारों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया।

जैसे ही पीजीए के योद्धाओं को यह मालूम हुआ था कि पुलिस ने दमन अभियान छेड़ दिया है और कई गांवों में जनता द्वारा निर्मित शहीद स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है, तो छापामारों की एक टुकड़ी हमले की तैयारी की। आसपास के गांवों की जनता की सक्रिय मदद से उन्होंने पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी लेकर इरुकभट्टी गांव के पास घात लगाकर हमला करने का फैसला किया। उसके तहत जब वे तय जगह पर फौजी तैयारियां कर ही रहे थे कि पुलिस दल आ पहुंचा। तब छापामारों ने तुरंत ही पहलकदमी करते हुए पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया। हालांकि बाकी पुलिस वालों ने जवाबी गोलीबारी की लेकिन छापामार सकुशल पीछे हट गए। लगातार पांच गांवों में शहीद स्मारकों को गिराने से जनता का आक्रोश जो भड़का था, पीजीए के इस हमले से हर तरफ खुशियां मनाई गईं। ✪

होमगार्ड का सफाया !

दक्षिण बस्तर डिवीजन, जगुरगोंडा इलाके के ग्राम चिंतगुप्पा के निवासी सोडी जिम्माल को एक्शन टीम ने 12 फरवरी 2001 को बुरकापाडु गांव के निकट मार डाला। जिम्माल होमगार्ड था और वह आसपास के गांवों के संघ नेताओं के बारे में, छापामार दस्ते के आने-जाने के बारे में और दस्ते के मुकाम-स्थलों के बारे में चिंतागुप्पा में तैनात पुलिस वालों को बताया करता था। एक बार इसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह खुलकर जन विरोधी कार्रवाइयों में भाग लेता रहा, तो जनता के फैसले पर एक्शन टीम ने उसका सफाया कर डाला। ✪

मुखबिर बारसू पोट्टावी को सजा-ए-मौत !

उत्तर बस्तर डिवीजन के कोयलीबेडा दस्ता इलाके में चारगांव रेंज के सोडे गांव का निवासी बारसू पोट्टावी 8वीं कक्षा तक पढ़ा था। इसके दादा और पिता मांझी थे। बारसू 1999 में पढ़ाई छोड़कर गांव में डीएकेएमएस का सदस्य बना था। इस गांव में पहले एक मुखबिर रहता था और उसकी सूचना के आधार पर बारसू को पुलिस ने दो बार गिरफ्तार किया था। हिरासत में वह पुलिस द्वारा दिए गए प्रलोभनों से मुखबिर बन गया। एक तो यह मांझी का बेटा था और दूसरा यह इलाके के जाने-माने कबड्डी खिलाड़ी था। इसलिए आसपास के कई गांवों के नौजवानों में इसकी पहचान थी। इसके आधार पर वह गांवों में घूमते हुए जन संगठनों के नेताओं और छापामार दस्ते की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र करके पुलिस को पहुंचाने लगा। इसकी दी सूचना के आधार पर पुलिस ने जन संगठनों के कई नेताओं और पार्टी के समर्थकों को गिरफ्तार किया। कई बार रातों में पुलिस द्वारा मारी गई छापेमारियों में बारसू भी शामिल था। लेकिन वह पुलिस के साथ रहते समय नकाब पहना करता था ताकि लोग उसे पहचान न सकें। पुलिस ने इसे यह प्रलोभन दिया कि दस्ते के साथ मुठभेड़ करवाने से पुलिस की नौकरी दी जाएगी। इससे यह एक सायकिल लेकर हर दिन 4-5 गांवों में घूमने लगा। कोयलीबेड़ा और अंतागढ़ पुलिस थानों से इसके अच्छे संबंध थे। पुलिस बारसू को हजारों रुपए दे रही थी। बारसू ने कई और लोगों को मुखबिर बनाया। धीरे-धीरे वह चोर बनकर सायकिलों की चोरी करने लगा और दूर के गांवों में ले जाकर बेचता था। पुलिस को इसकी गतिविधियों के बारे में मालूम होने के बावजूद उसे पूरी छूट दी गई।

जनता ने इसकी गतिविधियों के बारे में पार्टी को सूचित किया। जनता इसकी हर हलचल पर नजर रखी हुई थी। और जनता की सूचना पर छापामार दस्ते ने इसे गिरफ्तार किया। इसे छापामार दस्ते ने जन अदालत में पेश किया जहां पर उन 16 गांवों की जनता उपस्थित थी जहां के लोगों को पुलिस ने इसकी सूचना पर गिरफ्तार किया था। जन अदालत में इसके अपराधों पर खुली चर्चा हुई और स्त्री-पुरुषों और बच्चों ने भी इसकी पिटाई कर डाली। बारसू ने उन सभी के नाम बताए जो उसके साथ सहयोग करते थे। बाद में तमाम जनता की राय के मुताबिक उसे मार डाला गया। ✪

"यह अकाल प्राकृतिक नहीं - शोषणकारी सरकार की देन है!"

दक्षिण और पश्चिम बस्तर में सूखे के प्रति सरकारी लापरवाही के खिलाफ जनता का आन्दोलन

इस वर्ष वर्षा के अभाव के चलते छत्तीसगढ़ राज्य भीषण अकाल की स्थिति से गुजर रही है। राज्य सरकार ने 11 जिलों को अकाल पीड़ित घोषणा की, लेकिन उनमें बस्तर संभाग के तीनों जिले शामिल नहीं है। दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) जिले के 4 तहसीलों में भयंकर सूखा व्याप्त है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिले में सिर्फ 1.77% जमीन को ही सिंचाई सुविधा हासिल है। बाकी जमीन पूरी तरह वर्षा पर आधारित है। पिछले साल सितंबर माह में ही बारिश रुक गई थी जिससे फसलों चौपट हो गईं। अधिकतर किसान सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत फसल प्राप्त कर सके। इस हालत में लोगों ने रोजी-रोटी की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन करना शुरू किया।

कथित आजादी के 53 साल बाद भी सरकार ने अकाल से बचने के लिए अभी तक कोई कारगर योजना नहीं बनाई है। सरकार सालों से यहां से अरबों रुपए के मूल्य की खनिज व वन संपदा लूट रही है। किंतू विकास के नाम से सड़क निर्माण को छोड़कर जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने का उसने एक भी प्रयास नहीं किया है। यहां पर शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नगण्य हैं। जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए पिछले 20 सालों से हमारी पार्टी के नेतृत्व में आन्दोलन करती आ रही है। इस क्रांतिकारी किसान आन्दोलन को कुचलने के लिए जोगी सरकार ने 42 करोड़ रुपए से 2 नए एसएएफ बटालियन खोलने की स्वीकृति दी जिनमें से एक दन्तेवाडा जिले में प्रस्तावित है। यानी 21 करोड़ रु. दन्तेवाडा जिले को मिल रहे हैं। एक ओर जिले की 6 लाख जनता भीषण अकाल से जूझ रही है और पेयजल की समस्या विकट है। इसके लिए मात्र 1 करोड़ रु. आवंटित करके जोगी ने साबित किया कि उसे जनता की तकलीफें दूर करने से ज्यादा दिलचस्पी जनता के दमन में ही है। यह राशि भी तालाबों, स्टाप डैमों और कुंओं के निर्माण पर नहीं, बल्कि 90 प्रतिशत राशि पंचायत भवनों और सड़कों के निर्माण पर ही खर्च की जा रही है। हालांकि इससे अकाल पीड़ित जनता को अस्थाई तौर पर मजदूरी मिल सकती है, लेकिन किसानों को अकाल से मुक्ति पाने में यह काम उपयोगी कतई नहीं है। और तो और इससे भ्रष्ट नौकरशाहों और ठेकेदारों को फायदा जरूर होता है। सरकार के दमन-यंत्र को सुविधा होती है।

दूसरी तरफ, सरकार और सरकार की शह पर नेता-ठेकेदारों द्वारा की जा रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई से भी यहां के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे अवर्षा या असामयिक वर्षा हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, तो सरकार की जन-विरोधी नीतियों के परिणामस्वरूप ही अकाल की समस्या साल-दर-साल बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को अकाल से बचाने में सरकार की अक्षमता और लापरवाही का विरोध करते हुए कई संगठनों से बने संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में 5 फरवरी 2001 को कोंटा, बासागुडा, जगरगुडा, आवापल्ली, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़ आदि जगहों पर जनता ने जंगी प्रदर्शनों और विशाल रैलियों का आयोजन किया। बीजापुर में 15,000, कोंटा में 12,000, जगरगुडा में 10,000, भैरमगढ़ में 20,000, आवापल्ली में 5,000, भोपालपट्टनम मं 10,000, बासागूडेम में 6,000 - इस तरह दोनों डिवीजनों में कुल मिलाकर करीब 80,000 लोगों ने इन रैलियों में भागीदारी ली। लोगों ने कई जगहों पर चक्काजाम भी किया और आधा घण्टे से लेकर एक घण्टे तक यातायात को रोक दिया।

इससे पहले, जनता को रैलियों में भाग लेने का आह्वान करते हुए व्यापक प्रचार कार्यक्रम चलाया गया। दक्षिण और पश्चिम बस्तर डिवीजनों में डीएकेएमएस के 80 प्रचार दलों और केएएमएस के 50 प्रचार दलों ने दो हफ्ते पहले से ही प्रचार अभियान शुरू किया। 3,500 पर्चे, 1,000 पोस्टर, 250 बैनर, 50 प्लैकार्ड वितरित किए गए।

इन रैलियों में जनता ने जो मांगें उठाईं वे इस प्रकार हैं -

1) अकाल से नष्ट हुई फसलों के मुआवजा के रूप में प्रत्येक एकड़ जमीन के लिए दो क्विन्टल धान दो।
2) गांव-गांव में सूखा राहत कार्य (तालाब, भूमि समतल, स्टापडैम, कुंआ निर्माण आदि) शुरू करो।
3) उचित मूल्य दुकान के माध्यम से अकाल पीड़ितों के लिए विशेष कोटा जारी करके 4 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल बेचा जाए।
4) खरीफ फसलों के लिए बीज दो।
5) पुराने कर्जों को माफ करो और नए कर्ज दो।

अकाल की समस्या दक्षिण बस्तर से लेकर बालाघाट तक दण्डकारण्य के हर इलाके में सालों से बनी हुई है। सरकार की घोरतम लापरवाही का नतीजा ही है कि कृषि का विकास न हो पाया है और सिंचाई सुविधाएं नहीं बनी हैं। इससे थोड़ा वर्षा कम होने से भी फसलें मार खा रही हैं और किसानों की जिन्दगी गड़बड़ा रही है। वर्षा के न आने के पर्यावरणीय कारण के पीछे सरकार ही दोषी है। जनता अब स्पष्ट रूप से समझने लगी है कि अकाल की वजह प्राकृतिक प्रकोप नहीं, बल्कि सरकार की घोर लापरवाही है। इसलिए ही जनता इस तरह बड़े पैमाने पर इस मसले पर आन्दोलन में उतरी है। इसके बावजूद सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए जनता को इस लुटेरी सरकार का असली चेहरा पहचान कर अपने विकास के प्रयास खुद ही करना होगा। गांव-गांव में बनाई जा रही ग्राम राज्य कमेटियों, जो जनता की नई राजसत्ता के प्राथमिक अंग है, के नेतृत्व में जनता को पहलकदमी करनी चाहिए और सूखा के स्थाई समाधान के प्रयास शुरू करने होंगे। और साथ ही, इस लुटेरे राज्य को खत्म करके मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर नव जनवादी व्यवस्था कायम करने के लिए संघर्ष में दृढ़ता से भाग लेना चाहिए। दण्डकारण्य आधार इलाके के लक्ष्य से जारी क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी लेनी चाहिए। ✪

"गांव खाली करवा दो - बदनामी नक्सलियों पर डाल दो!"

क्रांतिकारी आन्दोलन के दमन के लिए बालाघाट पुलिस का नया हथकण्डा !!

पोलवत्तूर, छींदीटोला और कोकमा ऐसे गांव हैं जो बालाघाट जिले के घने जंगलों में बसे हुए हैं। इन तीन गांवों में कुल 60 मकान हैं और यहां के निवासी कुछ हद तक काश्तकारी पर और ज्यादातर जंगल में खुलने वाले मजदूरी कामों पर निर्भर करते हुए जीवन गुजारते हैं।

पिछले 10 सालों से इन गांवों की जनता डीएकेएमएस और केएएमएस के नेतृत्व में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रही है। अपने गांवों में संगठनों के नेतृत्व में जंगल विभाग वालों के जुल्म एवं अत्याचारों के खिलाफ जनता ने संघर्ष किया। जंगल विभाग वालों द्वारा दी जाने वाली कम मजदूरी दरों के खिलाफ लड़कर जनता ने मजदूरी बढ़ा ली। तेन्दुपत्ता ठेकेदारों और अन्य ठेकेदारों के खिलाफ भी लड़कर जनता ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। इस सिलसिले में इन गांवों में ग्राम राज्य कमेटियों का निर्माण भी किया गया जो कि जनता की राजसत्ता के अंग हैं। लेकिन यह सफर काफी कठिन रहा। संघर्षों के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे गए। पुलिस ने क्रूरतम दमन पर अमल किया। गिरफ्तारियां, जेल की सजाएं, कोर्ट-कचहरियों का चक्कर - जनता सब झेल चुकी है। इसके बावूजद जनता संघर्ष में डटकर खड़ी हो गई, तो सितंबर 1999 में पोलवत्तूर गांव का प्यारा नेता और ग्राम राज्य कमेटी अध्यक्ष कॉ. दिलीप को पुलिस ने अपने दलालों के जरिए खाने में जहर मिलवाकर हत्या करवाई।

पुलिस को इन सारी हरकतों और दमन के प्रयोग के बावजूद इन गांवों की जनता को पार्टी से अलग करने में और आन्दोलन को कुचलने में सफलता नहीं मिली। इससे पुलिस ने नई चालें चलीं। अक्टूबर 1999 में पुलिस ने एक शिव-भक्त को पोलवत्तूर भेजकर वहां एक हिन्दू भगवान की स्थापना करवाई। यह प्रचार करवाया गया कि इस भगवान के पास जाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इससे इस गांव में आसपास के गांवों से लोगों का आना-जाना बढ़ा। इसके अलावा, उस ढोंगी शिव-भक्त ने गांव के दो लोगों को मुखबिर बनाया। पुलिस वाले भी सादे कपड़ों में भगवान के पास आते-जाते हुए मुखबिरों से सूचना लेकर जाने लगे।

ये मुखबिर दस्ते का सफाया करने के मौके की ताक में बैठे थे। इसी समय, यानी मई 2000 में दस्ता कोकमा गांव गया था और वहीं से पोलवत्तूर के दो व्यक्तियों को बुलाया। उनमें से एक पुलिस मुखबिर था लेकिन यह बात दस्ते को मालूम नहीं थी। उनके साथ बात करके रात में वापस भेजा तो मुखबिर रातों रात ही डोरा पुलिसथाना गया और सुबह तक पुलिस को ले आया। लेकिन दस्ता वहां से चला गया तो उनकी योजना पिट गई। जनता को यह मालूम हो गया कि किसने पुलिस को लाया। इससे मुखबिर घबरा गए कि दस्ता उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा। इसलिए उन्होंने एक और साजिश रची। उन्होंने गांव के लोगों को यह कहकर डराया, "नक्सलवादियों ने हमारे गांव के सभी युवक-युवतियों को दस्ते में भर्ती होने को कहा। वरना गोलियों से उड़ा देंगे कहा। इसलिए हमें गांव खाली करके भागना होगा।" 10 सालों से दस्ते को जानने वाली ग्रामवासियों ने इस पर भरोसा नहीं किया। वे बोले कि दस्ते को आने दो उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन मुखबिरों ने पुलिस और मुखियाओं की मदद से दबाव डालकर इन तीनों गावों के लोगों को जबर्दस्ती गांव खाली करवाया। लोग मजबूर होकर रोते-रोते गांव छोड़ दिए।

सच्चाई यह थी, तो उलटा यह प्रचार किया गया कि नक्सलवादियों ने ही इन गांवों की जनता को खाली करवाया, जैसे `उलटा चोर कोटवार को डाटा'। `दस्ते में भर्ती न होंगे तो गांव में न रहने को कहा', कहकर कहानियां गढ़ी गईं। इन्हीं कहानियों को गढ़ी गईं। इन्हीं कहानियों को अखबारों और रेडियो ने बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया। किसी भी अखबार ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि मामला क्या है। पार्टी की ओर से ब्यौरेवार वक्तव्यों को भी प्रकाशित नहीं किया। खुद पुलिस अधीक्षक ने अखबार वालों को यह धमकी दे दी कि पीपुल्स वार पार्टी के वक्तव्यों को प्रकाशित नहीं किया जाए।

पुलिस वालों ने इन तीन गांवों की जनता के जबरिया विस्थापन के खिलाफ जनता को जनवादी तरीकों में भी विरोध जताने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस द्वारा इन गांवों को उजाड़ दिए जाने के खिलाफ इस इलाके की जनता, कुछ सरपंचों और जनपद पंचायत सदस्यों ने "विस्थापन विरोधी मंच" के नाम से एक साझा मोर्चा बनाया। इसके नेतृत्व में 30 जून 2000 को बालाघाट शहर में इस विस्थापन के खिलाफ एक प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। लेकिन पुलिस ने इसे विफल करने के लिए तीव्र दमन लाद दिया। पुलिस ट्रकों और बसों को आदेश दिया कि इस इलाके के लोगों को नहीं लाया जाए। ट्रकों और बसों के मालिकों ने पुलिस के आदेशों का पालन करते हुए इस इलाके के लोगों को अपनी गाड़ियों में नहीं बिठाया। जनता, सरपंचों और जनपद सदस्यों को पुलिस ने गंभीर चेतावनी दी। `विस्थापन विरोधी मंच' में शामिल सरपंचों और जनपद सदस्यों को गिरफ्तार करके प्रदर्शन की प्रस्तावित तारीख के बाद छोड़ दिया। रिहाई के बाद भी इन लोगों ने पत्रकारों को गांव खाली करने के मामले की पूरी जानकारी दी। फिर भी पुलिस के सख्त आदेशों के चलते अखबारों ने नहीं छापी। बालाघाट एस.पी. ने खुद ही अखबारों को वक्तव्य दिया कि उन्होंने विस्थापन विरोधी मंच के नाम से नक्सलियों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन को विफल कर दिया।

लेकिन ऐसी दमनात्मक कार्रवाइयों से बालाघाट की पुलिस अपने घिनौने हथकण्डों को बाहरी दुनिया से अस्थाई तौर पर ही छुपा सकती है। लेकिन हमेशा के *(शेष पृष्ठ 28 पर ....)*

बाल्को को निजी कंपनी स्टरलाइट को कौड़ियों में बेचने का विरोध करो!

बाल्को के मजदूरों ! आपकी जायज हड़ताल को तोड़कर गद्दारी करने वाले ट्रेड यूनियनों को मार भगाकर क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन का निर्माण करें !

2 मार्च 2000 को केन्द्र सरकार ने भारत अल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) में अपनी 51 फीसदी हिस्सेदारी 551.5 करोड़ रु. में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बेच दिया। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए अलग से एक मंत्रालय ही खोलकर कुल 246 सार्वजनिक उपक्रमों में 50 के निजीकरण की ठान ली हुई राजग सरकार की यह पहली बड़ी बिक्री थी। इस फैसले पर जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध खड़ा किया गया, तो विपक्षी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों ने भी अपने स्वार्थ हितों की खातिर इसमें अपना सुर मिलाया। संसद के दोनों सदनों में इस पर हुई तीखी नोकझोंक के बाद सरकार 120 मतों के बहुमत से जीत गई। दूसरे ही दिन उसने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज से 551.5 करोड़ रु. का चेक लेकर उसे बाल्को का कब्जा सौंप दिया। 3 मार्च से बाल्को के मजदूर इस बिक्री के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी।

नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर से 275 कि.मी. दूर पर स्थित जिला शहर कोरबा में 1965 में स्थापित इस कंपनी में कोई 7,500 मजदूर कार्यरत हैं। इसके अलावा कई कैजुअल मजदूर भी हैं। हंगरी और पुराने सोवियत संघ के तकनीक से निर्मित यह कंपनी *'छत्तीसगढ़ की शान'* और *'छोटी रत्न'* कहलाती है। इसमें बॉक्साइट से अल्यूमिना बनता है। इसके स्मेल्टर संयंत्र में शुद्ध अल्यूमिना से अल्यूमिनियम और कई किस्म की परिष्कृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें बहुत ही कुशल और काबिल मजदूर कार्यरत हैं। इस कंपनी में ऐसे मौके विरले ही आए हैं कि हड़तालें हुई हों या काम बंद हुआ हो। पिछले 12 साल बाल्को लगातार मुनाफा कमा रही थी। उदाहरण के लिए इसने 1997-98 में 79.84 करोड़ रु. और 1999-2000 में 55.89 करोड़ रु. का शुद्ध मुनाफा कमाया। इसके पहले घाटे में चल रहे या बंद पड़े उपक्रमों का ही निजीकरण किया जाता था, या किसी उपक्रम का निजीकरण करने के लिए या तो उसे घाटे में चलने को मजबूर किया जाता था या फिर घाटे में चलने का झूठा प्रचार किया जाता था। लेकिन अब मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को भी बेहिचक औने-पौने दामों में बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साम्राज्यवादियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उंगलियों पर नाचने वाली राजग सरकार ने बाल्को, जो अल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली भारत की तीसरी बड़ी कंपनी है, का निजीकरण करने का निश्चय करके 15 जून 2000 को 51 प्रतिशत शेयरों को बेचने के लिए निविदाएं बुलाईं।

अब निरस्त हो चुके विनिवेश आयोग द्वारा 1997 में की गई इस सिफारिश को कि बाल्को का 40% विनिवेशीकरण किया जाए, ताक पर रखते हुए सरकार ने 51 प्रतिशत शेयरों को कौड़ियों में बेचने का फैसला लिया। महज 551.5 करोड़ रु. में स्टरलाइट द्वारा बाजी मार लेने और दूसरी किसी भी कंपनी द्वारा निविदा पेश करने में नाटकीय ढंग से दिलचस्पी न दिखाने से यहां तक कि शासक वर्गों द्वारा भी शक की उंगली उठाई गई। बाल्को की तमाम संपत्तियों पर नजर डाली जाए, तो यह समझ में आता है कि इसे किस तरह औने-पौने दामों में बेचा गया है। बाल्को के परिसर में 90 करोड़ रु. के मूल्य की बेची जा सकने वाली सामग्रियां पड़ी हुई हैं। स्टरलाइट कंपनी को लगभग 50 करोड़ रु. की रद्दी सामग्री, 70 करोड़ रु. की अन्य सामग्री, 100 करोड़ रु. के मूल्य के कच्चेमाल (कॉस्टिक सोडा, ईंधन तेल, बॉक्साइट आदि) पर नियंत्रण प्राप्त हो चुका है। इस खरीदी से स्टरलाइट को 3,000 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मिल गया है। 2 लाख रु. प्रति एकड़ के वर्तमान मूल्य के हिसाब से सिर्फ यह जमीन की कीमत ही कोई 70 करोड़ रु. होगी। (एक समय 20 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा देकर यह भूमि आदिवासियों से अधिग्रहित की गई थी!) मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 100 करोड़ रु. के मूल्य की बाल्को की रियल एस्टेट संपतितयों पर अब स्टरलाइट का अधिकार होगा। बाल्को संयंत्र, मशीनों और अन्य उपकरणों को छोड़कर सिर्फ अन्य मदों में मौजूद संपत्तियों का मूल्य ही 900 करोड़ रु. से ज्यादा होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बाल्को के अंदर स्थित पावर प्लान्ट की कीमत कम-से-कम 1,000 करोड़ रु. होगी। ऐसे में महज 551.5 करोड़ रु. में बाल्को की 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच डालना न सिर्फ बाल्को के मजदूरों, बल्कि तमाम देशवासियों के साथ की गई गद्दारी है।

जब ऐसे आरोप आने लगे थे कि बाल्को के मूल्यांकन में और स्टरलाइट की निविदा बिना किसी खास स्पर्धा के ही पास होने में हेराफेरियां हुई हैं, तो विनिवेश मंत्री अरुण शौरी बेसिर-पैर के तर्क देने लग गया और उलटा-सीधा गणित बोलने लग गया। बाल्को के मूल्यांकन के लिए उसने जिस जार्डाइन फ्लेमिंग कंपनी को चुना, वह भी अतीत में भारतीय गैस प्राधिकरण के विनिवेश के विवादास्पद मामले में बदनाम थी। उसकी आंकड़ों की कवायद जनता के सामने पिटने लगी, तो उसने यह सवाल उठाकर बेशर्मी से जवाबी हमला छेड़ दिया, *"है कोई कंपनी जो इससे ऊंची बोली लगाए?!"*

बाल्को के निजीकरण पर सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया

की। नई आर्थिक नीतियों का शिल्पि मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अजीत जोगी, यहां तक कि राजग की घटक पार्टियां तेलुगुदेशम और शिवसेना ने भी इस सौदे का विरोध किया। वाम दलों ने हमेशा की तरह अपनी कमजोर आवाज में 'विरोध' का रोना शुरू किया। लेकिन यहां गौरतलब बात यह है कि बाल्को के मूल्यांकन पर समूचे विपक्ष ने अपना विरोध केन्द्रित किया। अपने को आदिवासियों का हितैषी बताने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी सरकार को विश्वास में लिए बिना ही यह सौदा किए जाने पर ही ज्यादा नाराज़गी जाहिर की। उसने इस सौदे में 100 करोड़ रु. की दलाली ली जाने की बात कहकर अंधेरे में तीर छोड़ दी। हड़तालरत मजदूरों के पास जाकर झूठा वादा किया कि इस बिक्री को निरस्त करवाने के लिए उससे जो कुछ हो पाएगा वह करेगा। इस बिक्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। आगे चलकर जोगी ने बेहद कमजोर कानूनों का हवाला देकर हास्यास्पद सवाल उठाया कि स्टरलाइट कंपनी आदिवासियों की जमीन की मालिक कैसे बन सकती है। जनता की करोड़ों रुपयों की संपत्तियों को बेहिचक बेचने वालों को इन कमजोर कानूनी उलझनों से निपटना कोई बड़ी बात ही नहीं है, यह बात खुद आजीत जोगी भी अच्छी तरह जानता है। यह सारा ड्रामा वह इसलिए कर रहा है ताकि जनता को भ्रम में रखा जा सके और जनता उसे "हमारी भलाई के लिए लड़ने वाला नायक" समझ सके। आखिर लगातार मुनाफा कमा रही इस कंपनी को बेचने की जरूरत ही क्या थी, यह सवाल सभी पार्टियों ने और सभी नेताओं ने जानबूझकर छोड़ दिया।

बिक्री का सौदा होते ही बाल्को के 7,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। मजदूरों में फूट पड़ी विरोध की भावना का फायदा उठाने के लिए तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने मजबूर होकर इस हड़ताल का नेतृत्व संभाला। 7 यूनियनों ने मिलकर *'बाल्को बचाओ संघर्ष समिति'* का गठन किया। भाजपा को छोड़ सबी राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने *'निजीकरण विरोधी संयुक्त समिति'* का गठन किया। हड़ताल के दूसरे दिन बाल्कोनगर की श्रमिक महिलाओं ने एक व्यापक मशाल-जुलूस निकाला। बाल्को की बिक्री को निरस्त करने की मांग सहित कई अन्य मांगों से मजदूरों ने अपनी हड़ताल दृढ़ता से जारी रखी। हमारी `स्पेशल जोनल कमेटी' ने इस हड़ताल का समर्थन किया। साथ ही, एक और वक्तव्य में हमारी पार्टी ने मजदूरों को चेताया कि हड़ताल का नेतृत्व कर रही शक्तियों पर नजर रखें। दरअसल इस हड़ताल का नेतृत्व करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने शासन काल में नई आर्थिक नीतियों पर अमल किया था। सिर्फ सरकार द्वारा `पारदर्शिता' न बरते जाने या और कोई बहाने से नाम के वास्ते इस सौदे का विरोध करके बीच में ही संघर्ष के साथ गद्दारी करना ही इन पार्टियों की मंशा थी। मजदूरों को इस भ्रम में रखकर कि मजदूरों की भलाई के लिए वे कटिबद्ध हैं, जनता को धोखा देकर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश ही की इन सभी बूर्जुवाई और संशोधनवादी पार्टियों ने। 67 दिन तक चली हड़ताल के साथ इन पार्टियों के ट्रेड यूनियनों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत गद्दारी की। निजीकरण को रोकने की बात तो दूर, कम-से-कम हड़ताल की अवधि के लिए वेतन देने की मांग हासिल करने में भी ये समझौतापरस्ती ट्रेड यूनियन नाकाम हो गए।

पहले भी देश के विभिन्न इलाकों में निजीकरण के खिलाफ मजदूरों और कर्मचारियों ने कई बार हड़तालें कीं। अधिकतर मौकों पर हड़ताल का नेतृत्व कर रहे ट्रेड यूनियन नेताओं ने ही गद्दारी की। दरअसल यह एक बहुत बड़ी साजिश है। बूर्जुवाई और संशोधनवादी ट्रेड यूनियन आमतौर पर पहले हड़ताल शुरू कर देते हैं और बाद में, जब सरकार दमन का सहारा लेती है, हड़ताल वापस लेते हैं ताकि मजदूर वर्ग को हताशा में डाल दिया जाए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि वे कभी नहीं जीत सकते।

यहां भी वही हुआ। क्रांतिकारी ताकतों को जैसी आशंका थी, बाल्को मजदूरों की हड़ताल के साथ भी नेतृत्व द्वारा गद्दारी की गई। इसकी वजह मजदूरों को सही नेतृत्व का न होना है। हड़ताल वापस लेने के बाद आक्रोश में आकर मजदूरों ने बूर्जुवाई और संशोधनवादी नेताओं को गद्दार कहकर जमकर लताड़ लगाई। लेकिन क्रांतिकारी नेतृत्व के अभाव में मजदूरों की संघर्षशीलता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाल्को के मजदूरों को कम से कम अब बूर्जूवाई और संशोधनवादी ट्रेड यूनियनों के असली चेहरे को पहचानना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि छत्तीसगढ़ का मजदूर वर्ग अपने समझौतापरस्ती नेतृत्व को मार भगाकर क्रांतिकारी नेतृत्व कायम कर ले। नव जनवादी क्रांति के तहत पास के दण्डकारण्य और अन्य इलाकों में चल रहे संघर्षों से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। सामंतवादी-साम्राज्यवादी-दलाल पूंजीवादी बंधनों से मुक्ति के लिए लड़ रहे अपने वर्ग बंधु आदिवासियों को उन्हें अपना आदर्श बना लेना चाहिए। नव जनवादी क्रांति के लक्ष्य से सही क्रांतिकारी नेतृत्व के तहत ही मजदूर संघर्ष को आगे बढ़ा सकेंगे - कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। ✪

शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक !

आधे आसमान के चमकते सितारे

(दण्डकाण्य की महिला शहीदों की जीवनियां)

ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए !

संघर्षरत महिला

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का मुखपत्र

पृथक जनवादी बस्तर राज्य की मांग को लेकर उत्तर बस्तर की जनता का आन्दोलन तेज!

(1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से लेकर अब तक जनता का यह जनवादी आन्दोलन किसी न किसी रूप में लगातार बिना रुके जारी है। विभिन्न जनवादी संगठनों के नेतृत्व में जनता की रैलियों का सिलसिला अभी भी जारी है। पेश है उत्तर बस्तर डिवीजन में निकाली रैलियों की यह रिपोर्ट। - संपादकमण्डल)

उत्तर बस्तर डिवीजन की जनता ने "पृथक जनवादी बस्तर" की मांग को लेकर मर्दापाल, वेडमाकोट, जमिरी, डौला, वयनार, सरंडी आदि हाट बाजारों में हजारों की तादाद में रैलियां निकालीं। इन तमाम रैलियों में `पृथक जनवादी बस्तर राज्य' का नारा हर तरफ गूंज उठा।

इन सभी रैलियों को विफल करने के लिए सैकड़ों पुलिस वालों ने जनता को डराने-धमकाने का प्रयास किया। लेकिन जनता ने इसकी परवाह न करते हुए हजारों की संख्या में भाग लेकर रैलियों को शानदार सफलता दिलाई। उसने फिर एक बार साबित किया कि बंदूक की नोक पर जनवादी आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता।

'बस्तर संघर्ष समिति' की अगुवाई में 14 दिसंबर 2000 को नारायणपुर तहसील के ग्राम वेडमाकोट के हाट बाजार में 6,000 लोगों ने रैली में भाग लिया। करीबन 80 गांवों से आने वाले इन लोगों में 3,000 महिलाओं की उपस्थिति एक विशेष बात थी। यहां से दूर के गांवों से लोग एक दिन पहले ही पहुंचे थे। हालांकि पुलिस वालों ने कैंप बिठाकर गश्त बढ़ाकर जनता में आतंक मचाने का प्रयास किया, फिर भी जनता ने इस पर कोई ध्यान नहीं देकर रैली को सफल बनाया।

इसी तरह 5 दिसंबर को कोंडागांव तहसील के वयनार हाटबाजार में भी रैली आयोजित की गई जिसमें 30 गांवों के 1,500 लोगों ने भाग लिया। 16 दिसंबर को मर्दापाल हाटबाजार में आयोजित रैली में लगभग 3,000 जनता ने भाग लिया जो 19 गांवों से आई थी। यहां भी पुलिस के आला अफसरों ने जनता को डराने का विफल प्रयास किया।

12 जनवरी 2001 को नारायणपुर तहसील के दौडाई हाटबाजार में एक सफल रैली आयोजित की गई जिसमें 60 गांवों से आए 4,000 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। केसकाल इलाके के ग्राम सरंडी में आयोजित रैली में 30 गांवों की 5,000 जनता ने भाग लिया। गांव किसकोड्डो में आयोजित रैली में 2,000 लोगों ने भाग लिया। नारायणपुर के निकट जमिरी हाटबाजार में 2,500 लोगों ने रैली निकाली। ग्राम एडका में 50 पुलिस वालों ने हमला करके रैली को विफल करने के लिए लोगों को बंदूक की नोक पर भगा दिया। `बस्तर संघर्ष समिति' ने एक बयान में इस घटना की निंदा की।

इन सभी रैलियों में `पृथक जनवादी बस्तर राज्य' की मांग के अलावा जनता की कई समस्याओं पर भी विभिन्न मांगें की गईं।

26 मार्च 2001 को नारायणपुर रैली और विशाल आमसभा की भारी सफलता

ऊपर बताई रैलियों के सिलसिले में आखिरी कड़ी के रूप में 26 मार्च को नारायणपुर में एक विशाल रैली और आमसभा आयोजित की गईं जो पूरी तरह सफल रहीं। रैली का आयोजन `बस्तर संघर्ष समिति' के नेतृत्व में किया गया। इस समिति ने पहले ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति ली थी। 25 मार्च की शाम से ही दूर-दराज के गांवों से लोगों का आना शुरू हो गया। कई लोगों ने नारायणपुर पहुंचने के लिए वाहनों का बंदोबस्त भी कर लिया। नारायणपुर के एएसपी आर.पी. साय के नेतृत्व में दो प्लाटूनों के एसएएफ बलों ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और भद्दी गालियां दीं। कम से कम तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा नारायणपुर रैली के लिए जा रहे कुछ लोगों को रावघाट, बेनूर आदि कस्बों में पुलिस ने रोककर, डरा-धमकाकर वापस भेजा। इसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग ग्राम गड़बेंगाल में इकट्ठा हो गए। सुबह के 10 बजे शुरू हुआ जुलूस करीब 5 कि.मी. चलकर बकुरपारा के पास विशाल आमसभा में परिवर्तित हुआ। जुलूस के दौरान जनता ने गगनभेदी नारे लगाए जिनमें प्रमुख इस प्रकार थे - **"पृथक जनवादी बस्तर राज्य का गठन करो", "बस्तर में साम्राज्यवादी-सामंतवादी लूट का विरोध करो", "बस्तर के संसाधनों को बस्तर के लिए ही खर्च करो", "आन्दोलनकारियों पर पुलिसिया दमन का विरोध करो"** आदि।

जुलूस और आमसभा में कम-से-कम 18,000 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया जो 200 से ज्यादा गांवों से आए थे। सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने बस्तर के अलग अस्तित्व के बारे में इतिहास का हवाला देते हुए विस्तार से बताया। और उन्होंने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया कि अभी तक बस्तर के संसाधनों की मनमानी लूट ही हो रही थी और सरकारों ने बस्तरवासियों की घोर लापरवाही की। जनता की मुख्य मांगें इस प्रकार थीं -

1) पृथक बस्तर राज्य का गठन किया जाए।
2) बस्तर में साम्राज्यवादी और सामंतवादी शोषण को समाप्त किया जाए।
3) कांकेर, जगदलपुर और दन्तेवाड़ा जिलों के नाम बदलकर क्रमशः उत्तर बस्तर, मध्य बस्तर और दक्षिण बस्तर के नाम रखा जाएं।
4) बस्तर में साम्राज्यवादी संस्कृति के फैलाव को रोक दिया जाए।
5) बस्तर के संसाधनों से हो रही आय का खर्च बस्तर के विकास के लिए ही हो। ✪

(.... अंतिम पृष्ठ का शेष)

भोलेभाले आदिवासियों और क्रांतिकारियों की हत्या की है। खासतौर पर बस्तर, राजनांदगांव और बालाघाट जिलों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।

उपरोक्त सभी घटनाएं पुलिस के जुल्मों और अत्याचारों को प्रमाणित करती हैं। देशवासियों को पुलिस द्वारा किए जा रहे इन कत्लेआमों की भर्त्सना करनी चाहिए। देश के सभी आदिवासियों को वहीं राह चुन लेने की जरूरत है जिस पर आज दण्डकारण्य के उत्पीड़ित आदिवासी किसान चल रहे हैं। देश के शासक वर्ग अपने भाड़े के बलों आधुनिक हथियारों से लैस करके जनता के खिलाफ उकसा रहे हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में एक फैसला लिया कि आदिवासी युवकों को पुलिस में भर्ती करके उन्हीं के जरिए आदिवासियों की हत्या करवाई जाए। 26 जनवरी 2001 को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुलिस के दो आदिवासी बटालियन बनाने का फैसला लिया। एक-एक बटालियन में 1200 पुलिस वाले होंगे। और इनमें से एक सरगुजा में रहेगा और दूसरा विशाल बस्तर में। ये दोनों बटालियन खासतौर पर आदिवासियों के दमन के लिए बनाए जाएंगे। इनके जवान आदिवासियों पर बन्दूकें तानेंगे और चाहे जब और चाहे जिसे गोलियों से भून डालेंगे। इस तरह के निरंकुश अधिकारों की गारंटी देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने 27 नवंबर 2000 को ही विधानसभा में "मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्रों की सुरक्षा अधिनियम को पारित किया। जाहिर है इससे पुलिस के जुल्मों और अत्याचारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

इसलिए, लोगों !

इस लुटेरी व्यवस्था में अब जनता की जानों को और न्यूनतम अधिकारों को कोई गारंटी नहीं रह गई है। बदहाली का आलम यह है कि जनता का अस्तित्व ही संकट में फंसा है। यह व्यवस्था जब तक जारी रहेगी तब तक यह यह खतरा बना रहेगा। हम अभी मौत के साये में जीने को मजबूर हैं। इसका जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ता के साथ कमर कस लेनी होगी। दण्डकारण्य के क्रांतिकारी किसानों के संघर्ष-पथ पर चलकर ही इस कातिल व्यवस्था का खात्मा किया जा सकता है। दण्डकारण्य के क्रांतिकारी किसान मुक्त इलाके के लक्ष्य से लड़ रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए।

अंत में, फिर एक बार कॉ. चिन्ना पद्दा को श्रद्धांजली पेश करेंगे जिसने संघर्ष के गढ़ पर अपना खून बनाकर अपनी जिन्दगी को सार्थक बनाया।

क्रांतिकारी बधाई के साथ,

स्पेशल जोनल कमेटी,

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]

दण्डकारण्य

हीरानार के लोगों और तमाम जनवाद के प्रेमियों को क्रांतिकारी बधाई !

तदण्डकारण्य के पश्चिम बस्तर एवं माड़ डिवीजनों के नजदीक स्थित हीरानार ग्राम में प्रस्तावित रोमेल्ट स्टील प्लान्ट का विरोध करते हुए दृढ़तापूर्वक खड़े हीरानार के लोगों और तमाम जनवाद के प्रेमियों को हम क्रांतिकारी बधाई दे रहे हैं। बस्तर की जनता के हितों को बहुराष्ट्रीय निगमों और दलाल पूंजीपतियों के पास गिरवी रखते हुए बनाई सभी नीतियों का हम खड़ा विरोध कर रहे हैं। हम जनता और जनवाद के प्रेमियों के पक्ष में खड़े रहेंगे और उनका पूरा-पूरा सहयोग करेंगे। शुरू से ही हम हीरानार स्थित स्टील प्लान्ट का विरोध करते आ रहे थे। हम सब के विरोध के चलते हीरानार में इस्पात संयंत्र का विचार त्यागने की स्थिति निर्मित हो गई है। इसे और भी तेज करेंगे।

लुटेरे वर्गों के राजनेता यह दिवास्वप्न देख रहे हैं कि हीरानार नहीं तो बस्तर के किसी दूसरे स्थान पर यह संयंत्र खोला जाएगा। लेकिन हम साबित करके दिखाएंगे कि बस्तर में कहीं भी हीरानार का अनुभव ही दोहराया जाएगा। हम यह ऐलान करेंगे कि बस्तर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दलाल पूंजीपतियों को जगह नहीं मिलेगी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण जैसी नई आर्थिक नीतियों का विरोध करेंगे। उन्हें वापिस लेने की मांग से संघर्ष करेंगे। जनता की जनवादी सत्ता कायम करने के लिए मजदूर-किसानों से एकताबद्ध होकर साहस के साथ लड़ेंगे। हम हमेशा आपके साथ होंगे।

स्पेशल जोनल कमेटी,

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]

दण्डकारण्य

वक्तव्य

दिन-ब-दिन आदिवासियों पर बढ़ रही पुलिसिया अत्याचारों का विरोध करो!

केन्द्र की नई आर्थिक नीतियों की अंधी दौड़ में रौंदे जा रहे आदिवासियों के सामने संघर्ष के बिना कोई चारा नहीं !

गड़चिरोली जिले के मर्कानार ग्रामवासी चिन्ना पद्दा अमर रहे !

प्यारे लोगों !

अभी केशोरी में आदिवासियों का खून सूखा ही नहीं कि देवास जिले के मेहंदीखेड़ा में आदिवासियों का खून फिर एक बार बहाया गया। महाराष्ट्र के गोंदिया जिला, केशोरी गांव में 18-12-2000 को पुलिस वालों ने बेवजह अंधाधुंध गोलीबारी करके 9 आदिवासियों की जानें लीं। उनका नक्सलवादी के रूप में गलत चित्रण करने की विफल कोशिशें भी कीं। अब, 2 अप्रैल 2001 को मध्यप्रदेश के देवास जिले में पुलिस वालों ने दो और आदिवासियों को अपनी बंदूकों का शिकार बनाया, जहां नक्सवादियों का नामोनिशान तक नहीं है। पुलिस जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले केशोरी वासियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं और वन विभाग के अधिकारियों के जुल्मों का विरोध करने पर मेहंदीखेड़ा के आदिवासियों को पुलिस ने अपने आंतक का शिकार बनाया। इनके अलावा 27 मार्च 2001 को महाराष्ट्र की पुलिस ने गड़चिरोली जिला, भामरागढ़ तहसील, ग्राम कोहकापरसी के निकट चिन्ना पद्दा पर गोलियां बरसाकर पहले घायल करके, बाद में उसे पकड़कर हत्या कर दी। चिन्ना पद्दा मर्कानार गांव का निवासी था। उसका गुनाह यही था कि वह जंगल के खरगोश का शिकार करने जा रहा था। जंगल में अचानक सामना होने के साथ ही गोलियां चलाकर घायल करके, बाद में क्रूरता से यातनाएं देकर हत्या करने वाले महाराष्ट्र के कमाण्डो जवानों की कायरता अपने आपमें अनोखी है। ठीक इसी तरह, बस्तर पुलिस ने 18 दिसंबर 1999 को माड़ अंचल में राजू नरोटी की हत्या की थी। इस तरह देखा जाए, तो आदिवासियों की हत्या संबंधी घटनाओं की फेहरिश्त बड़ी लंबी है। जहां कहीं भी आदिवासी किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष शुरू करते हैं, तो पुलिस वाले अंधाधुंध गोलीबारी करके उनकी जानें ले रहे हैं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वह इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है या नहीं। यदि वह नक्सल प्रभावित इलाका हो तो लाश पर `नक्सली' का ठप्पा लगाकर हाथ झाड़ ले सकते हैं। और दुनिया के सामने खुद को `हीरो' के रूप में पेश कर सकते हैं। यदि वह अलग इलाका है, तो `हिंसा पर उतारू लोगों पर काबू पाने के लिए' गोलीबारी करनी पड़ी कहकर सफाई दे सकते हैं। दूसरी ओर लुटेरे शासक वर्गों की मीडिया सभी आदिवासी इलाकों में `नक्सलवादियों का विस्तार' की बात को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करके पुलिस को सतर्क कर रही है। और पुलिस की सभी कार्रवाइयों का समर्थन कर रही है। यह अत्यंत गैर-जनवादी और अमानवीय नीति है। हम पुलिसिया अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं। तमाम जनता से हम आग्रह करते हैं कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण गतिविधियों का खुलकर विरोध करें।

देश की आबादी का 8 प्रतिशत आदिवासी हैं। आज भी मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए इलाकों में ही आदिवासी रहते हैं। ये सभी इलाके वन और खनिज संपदाओं के लिए जाने जाते हैं। इन पर देश के शासक वर्गों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और साम्राज्यवादियों की नजर पड़ी है। और इनके इशारों पर ही आदिवासियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं। साम्राज्यवादियों के आदेश पर देश में लागू की गई आर्थिक नीतियों के इस एक दशक में, अकेले मध्यप्रदेश में आदिवासियों पर गोलीबारी की कितनी घटनाएं हुई हैं, इस पर नजर डाली जाए।

जिला	गांव	तारीख
शिवपुरी	हंसली	3-2-1995
मुलतई	मुलतई	112-1-1998
शहडोल	जैतपुर	25-5-1995
खंडवा	मांडवा	27-8-1997
होशंगाबाद	नंदरवाड़ा	3-8-1997
खंडवा	टेटगांव	27-2-1999
देवास	कटुकिया	27-2-2000
सिहोर	निमटोन जंगल	27-8-2000
देवास	मेहंदीखेड़ा	2-4-2001

ये सभी घटनाएं मध्यप्रदेश के कथित नक्सल प्रभावित इलाकों के बाहर ही घटी हैं। नक्सलवादी आन्दोलन के इलाकों में पुलिस ने इस एक दशक में अनगिनत *(शेष पृष्ठ 39 पर....)*

वन-धन समितियों के एकाधिकार को समाप्त करवाने के लिए लड़कर कामयाबी हासिल कर चुकी शोषित आदिवासी जनता का क्रांतिकारी अभिनन्दन !

पिछले तीन सालों से बस्तर में वन-धन समितियों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जाता रहा। 'वन ही धन' के नारे से इन समितियों का गठन किया गया। प्रवीर कृष्ण बस्तर का कलेक्टर बनने के तुरन्त बाद इस योजना को अमली जामा पहनाया गया। पूर्व में गुजरात में जब वह डेरी उद्योग में अधिकारी रहे थे, तब उन्होंने दूध के उत्पादन बढ़ाने के नाम पर नई योजनाएं शुरू की थीं। लेकिन जब ये योजनाएं विवाद के घेरे में आकर संकट में फंस गईं, तब उन्होंने बस्तर में `वन कृष्ण' का अवतार लिया। वन-धन के नाम पर यहां शुरू की गई इस योजना का भी वही हश्र हुआ। स्थानीय आदिवासी जनता ने शुरू से ही वन-धन समितियों का विरोध किया है। किसानों की पीड़ा का कारण बन चुकी इन वन-धन समितियों के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन चलाया गया। 22 मार्च 2001 को बहीगांव में घटी घटना को इस आन्दोलन की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। आखिरकार 15 अप्रैल को वन-धन समितियों का एकाधिकार समाप्त किया गया। निश्चित रूप से यह जन संघर्षों द्वारा हासिल कामयाबी है। इस अवसर पर, हम उन तमाम आदिवासी किसान-मजदूरों, स्थानीय छोटे और मध्यम व्यापारियों का क्रांतिकारी अभिनन्दन करते हैं जिन्होंने सरकार के ढोंगी सुधारों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक लड़कर जीत हासिल की।

"जब तक सूरज चांद रहेगा, वन-धन तेरा नाम रहेगा", "इमली की छाव में गांव का पैसा गांव में" आदि नारों का प्रवीर कृष्ण के काल में सरकारी अमले ने बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया। वन-धन समितियों पर जगदलपुर से दिल्ली तक सेमिनारें की गईं। जून 2000 में जेनीवा में आयोजित `गरीबी के उन्मूलन' पर सेमिनार में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वहां अपनी सुधार योजनाओं की सफलता पर ढिंढ़ोरा पीट-पीटकर प्रचार किया। "राष्ट्रीय वन नीति" पर जुलाई 2000 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में प्रवीर कृष्ण को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उस सेमिनार के नतीजों का जायजा लेने वाले संसदीय दल ने फैसला किया कि इस योजना को देश भर के सभी आदिवासी इलाकों में लागू किया जाए। मध्यप्रदेश के 12 जिलों में इसे तत्काल ही लागू करने का फैसला किया। इस पृष्ठभूमि में दिग्गी सरकार ने इमली को बस्तर की जनता का प्रतीक कहकर, 18 जुलाई को विशेष इमली दिवस मनाकर, उस दिन इमली के पौधे लगाने जैसे कई कार्यक्रम चलाए। जगदलपुर में आयोजित सेमिनार में आए भलेमानुसों ने यहां तक कहा कि वन-धन समितियां पूरे देश के लिए आदर्श हैं। गांधी के सपनों का ग्राम स्वराज आदिवासियों में 'इमली' के रूप में जन्म लेने की बात की गई। सही वक्त पर, सही दिशा में बस्तर में इमली आन्दोलन शुरू किया गया कहकर प्रशंसा के पुल बांधे गए। बस्तर की जनता की बुनियादी समस्याओं को इस तेज हवा में उड़ा दिया गया। बस्तर की इमली के बारे में सरकार ने प्रचार और प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके पीछे दिग्विजय सिंह का पूरा समर्थन है। बस्तर में नक्सलवादियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए वन-धन को ही एक मात्र मंत्र माना गया। लेकिन क्रांतिकारी राजनीति से लैस बस्तर की बहादुर जनता तो शुरू से ही इस सरकारी नौटंकी का विरोध करते आ रही है। बस्तर की जनता ने ऐसे कई सरकारी नाटक देखे हैं। इसलिए उसने आखिर तक लड़ाई जारी रखी। बहीगांव में तो आमने-सामने की लड़ाई भी लड़ी। इस तरह जनता ने सरकार को घुटने ठेकने पर मजबूर करके अपनी मांगें हासिल कीं।

1999 में प्रवीर कृष्ण ने बस्तर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त होने के बाद बस्तर की वनोपजों पर ही अपना पूरा समय खर्च किया। और इसी विषय पर काफी शोध-कार्य करके पत्र-पत्रिकाओं को कई आंकड़े उपलब्ध करवाए। बस्तर के आदिवासियों से 4 रु. प्रति किलो के भाव से इमली खरीदकर अरब देशों में 400 रु. प्रति किलो के भाव से बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, यह बात उन्होंने कही। उन्होंने आगे कहा कि साहूकारों द्वारा जारी लूट-खसोट को खत्म करके आदिवासियों को सुधारने के लिए सरकार को बाजार पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए। उन्होंने ऐसे कई धूल चढ़े कानूनों को सामने लाकर, जिन पर अब तक अमल ही नहीं किया गया, छोटे और मध्यम व्यापारियों को हाटबाजारों में कदम रखने से रोक दिया। ये व्यापारी कई पीढ़ियों से बस्तर के हाटबाजारों पर निर्भर रहकर ही जीते आ रहे हैं। सरकारी कानूनों का शिकार बनकर ऐसे कोई 4,000 से ज्यादा व्यापारी परिवार सहित बेघरबार हो गए जो बस्तर में लगने वाले 100 से ज्यादा हाटबाजारों में जाकर या घर-घर, गांव-गांव घूमकर वनोपजों को खरीदकर अपना पेट पालते थे। 1999 में सरकार ने इमली खरीदी मूल्य 12 रु. घोषित किया।

अखबारों का मानना है कि बस्तर में वनोपजों के व्यापार का टर्नोवर 1,000 रु. है। 60 किस्म की वनोपजों को सरकार ने लघु वनोपज घोषित किया और इन्हें नान-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा गया है। इनमें औषधीय पौधों, फूलझाड़ू, चार के बीजों सहित 60 चीजें शामिल हैं। इनकी खरीदी वन-धन समितियों के माध्यम से ही करने की घोषणा हुई थी। प्रवीर कृष्ण के आंकड़ों के अनुसार इन चीजों की खरीदी में आदिवासियों को मात्र 20 प्रतिशत दाम ही मिल रहा है और बाकी 80 प्रतिशत को व्यापारी लूट रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कारोबार करने के लिए सरकार के पास पूंजी नहीं होने की बात कही। इसलिए ट्राइफेड (ट्राइबल को-ऑपरेटिव डेवलपमेन्ट फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया) से धन की मांग की। लेकिन वह भी हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। आर्थिक संकट ने सब को अपनी चपेट में ले रखा है। कथित रूप से आदिवासियों के

विकास के लिए गठित एक केन्द्र सरकार की संस्था के पास भी पैसा न होने की बात से यह पता चल जाता है कि सरकार आदिवासियों के विकास पर कितनी गंभीर है। शुरू से ही एक ओर राज्य सरकार और दूसरी ओर केन्द्र सरकार की संस्था ट्राइफ़ेड के बीच आदिवासी पिसते आ रहे हैं। वन-धन समितियों को अगर ट्राइफ़ेड पैसा देता है, तभी वे आदिवासियों से वनोपजों की खरीदी कर सकती हैं, वरना हाथ झाड़कर खड़े हो जाती हैं। आखिर हुआ भी यही है। लेकिन इस दरमियान किसानों को जो तकलीफें हुईं उनका वर्णन करना मुश्किल है।

ट्राइफ़ेड ने पिछले साल एक लाख क्विन्टल इमली की खरीदी की थी। इस साल अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक करीबन 2 लाख क्विन्टल इमली की खरीदी की जोकि पिछले साल के मुकाबले में दुनी है। हर साल जगदलपुर का बाजार जनवरी से जून तक इमली से भर जाता है। दिन-रात कांटे लगाए ही जाते हैं। विशाल बस्तर के कोने-कोने से भी इकट्ठी की गई इमली का 90 प्रतिशत जगदलपुर बाजार पहुंचता है। गांव के दाम और जगदलपुर के दाम के बीच का अंतर कम से कम 100 रु. प्रति क्विन्टल रहता है। ढुलाई और नुकसान के नाम पर यह अन्तर बरता जा रहा है। पिछले साल जगदलपुर पहुंची इमली का ही अब तक ट्राइफ़ेड भुगतान नहीं कर सका। 10 करोड़ रु. फंसे रहने से आदिवासी किसान परेशान हैं। इस साल और ज्यादा बढ़ गई। ऐसी स्थिति में, यह खबर चलने के बाद कि ट्राइफ़ेड इमली खरीदी बन्द करने जा रहा है, बाजार में और ज्यादा इमली आ गई। सीमा पर स्थित उड़ीसा के गांवों से भी इमली जगदलपुर बाजार पहुंची। वन-धन समितियां तो पैसे के अभाव के बावजूद किसानों के हाथ में रसीदें थमाते हुए ढेरों में पहुंच रही इमली खरीदती ही गईं। सिर्फ 5 दिनों में 10 हजार क्विन्टल इमली की खरीदी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों में यह डर कितना घर कर गया होगा कि कहीं ट्राइफ़ेड ने इमली खरीदना बंद किया तो घर कैसे चले। ऐसी हालत में इमली आदिवासियों से ट्राइफ़ेड के पास पहुंच तो गई, लेकिन पैसा किसानों के हाथ में नहीं आया। गहरे वित्तीय संकट में फंसे ट्राइफ़ेड ने तुरन्त ही 15 अप्रैल से इमली खरीदी बन्द कर दी। अब से इमली कौन खरीदेगा? किसानों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया।

बस्तर में वन-धन समितियों का गठन करके जनता के क्रोध और विपक्षी पार्टियों की विरोधिता का शिकार बनने वाले 'वन कृष्ण' छत्तीसगढ़ के गठन के चंद दिनों बाद स्थानान्तरित होकर चले गए। इनका स्थान लेने वाली ऋचा शर्मा ने "वन-धन, भाग-2" को जारी रखने की गंभीर घोषणा की। बस्तर की इस पहली महिला कलेक्टर ने जनता को और भी चमत्कार दिखाने का दावा किया। लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। वन-धन समितियों के सामने लंबी कतारों में दिन भर खड़े रहकर भी इमली की खरीदी न होने से भूखे पेट से बोझा उठाकर घर वापस जाने के अपने कड़वे अनुभवों को जनता नहीं भूली थी। इसलिए कलेक्टर ऋचा शर्मा की बातों पर जनता ने यकीन नहीं किया। वन-धन समितियों की दिवालिया हालत से जनता पहले से परेशन रही है। सदियों से सेठ-साहूकारों ने आदिवासियों का शोषण किया तो अब वन-धन समितियों ने भी उनके साथ धोखाधड़ी ही की। 'वन-धन' के दिनों में भी इन समितियों की कंगाल हालत के चलते जनता चोरी-छिपे उन्हीं पुराने सेठ-साहूकारों को अपनी इमली कौड़ियों के दाम बेचती रही। लेकिन कुछ चालाक और तगड़े व्यापारियों ने वन-धन समितियों को पैसों का लालच बताकर, उनके जरिए ही सस्ते में इमली खरीदवाई, ऐसी कई घटनाएं रोशनी में आईं। इस तरह, वन-धन समितियों के रहते हुए भी आदिवासियों को सेठ-साहूकारों की लूट का शिकार होना पड़ा। आज फिर ट्राइफ़ेड ने हाथ झाड़ लिए तो लोगों को दोबारा सेठ-साहूकारों के रहमोकरम पर निर्भर रहने को मजबूर होना ही पड़ेगा। ऋचा शर्मा के दावे खोखले निकले। वे अब मौन धारण कर लीं। आदिवासी किसानों को लगातार सेठ-साहूकारों या सरकार के हाथों लुटते ही रहना पड़ रहा है। या फिर उनके साझे शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। औने-पौने दामों के चलते उन्हें घाटे में रहना पड़ रहा है। इस व्यवस्था में व्यापारियों के पास जाने की विवशता से किसानों को आज तक मुक्ति नहीं मिली है।

आदिवासियों द्वारा इकट्ठी की जाने वाली वनोपजों की कीमतें बाजार में आए दिन घटती जा रही हैं। गरीब आदिवासी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दिन भर जंगल में घूमकर इन जंगली फसलों को इकट्ठा करते हैं। इनके मालिक वे ही हैं। अपनी घरेलू जरूरतों को निकालकर बाकी को वे बाजार में बेचते हैं। अरसे से यह प्रथा प्रचलित है कि वे आमतौर पर व्यापारियों से वस्तुओ की अदला-बदली करते हैं। पिछले 2-3 दशकों से ही आदिवासी किसान बाजार के साथ ज्यादा जुड़ता जा रहा है। बाजार के आम उतार-चढ़ाव और कानूनी बदलाव किसानों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं।

वन-धन समितियों का गठन करने के बाद प्रवीर कृष्ण ने पहले इमली का भाव 12 रु. प्रति किलो घोषित किया था। लेकिन ट्राइफ़ेड की कंगाल हालत के चलते यह भाव एक सीजन तक भी न चल पाया। जून 1999 तक आते-आते किसानों को 6 या 7 रु. प्रति किलो के भाव से इमली बेचने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में वर्ष 2001 तक इमली का दाम बुरी तरह गिर गया। ट्राइफ़ेड द्वारा निर्धारित मूल्य 4.50 रु. प्रति किलो तक घटा। इसके बावजूद किसानों के सामने बेचने की विवशता जो थी। इस वर्ष विशाल बस्तर में इमली की अच्छी-खासी फसल निकली। लेकिन यह कोई धान जैसा अनाज तो नहीं है कि जमा कर रखकर खाते रहें। इस तरह भण्डारण करने के लिए सरकार ने शीत संग्रहागार की सुविधा भी कहीं नहीं बनाई। किसी परम्परागत तरीके से अगर भण्डारण कर भी दे तो तब तक घर में चूल्हा कैसे जले? ऐसे हालात आदिवासी किसानों को अपनी वनोपजों को बेचने पर मजबूर कर देते हैं। किसानों की इस हालत को देख ट्राइफ़ेड ने इमली का दाम 4.50 रु. तक घटाने के बाद भी खरीदी में अपनी असमर्थता जाहिर की। इससे बाजार पर नजर गढ़े हुए तगड़े व्यापारियों ने ट्राइफ़ेड के अधिकारियों से सांठगांठ करके इमली का भाव 2 रु. प्रति किलो कर दिया। हर साल उत्तर भारत से बड़ी संख्या में आने वाले व्यापारी भी इस वर्ष कम ही आए। दिल्ली और सहारनपुर के

व्यापारियों ने जगदलपुर के व्यापारियों के हां में हां मिला दिया। इस वजह से इमली का दाम पिछले 20 सालों में भी हीनतम स्तर तक घट गया। और डेढ़, दो रुपए पर टिक गया।

किसानों से खरीदी गई इमली का भण्डारण करने के लिए ट्राइफ़ेड के पास भी पर्याप्त सुविधा नहीं रही है। जगदलपुर गोदाम में 15 हजार बोरे सड़ रहे हैं। रायपुर में मौजूद शीत संग्रहागार भी कम पड़ जाने से हजारों बोरे गोदामों के मुहाने में सड़ रहे हैं। दन्तेवाड़ा में शीत संग्रहागार बनाने का वादा धन के संकट के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक ओर खरीदा गया माल सड़ता रहा, और दूसरी ओर किसानों का बकाया भुगतान करने में ट्राइफ़ेड की असमर्थता जारी रही। कानून की आड़ में हाटबाजारों में बिचौलिए व्यापारियों पर लगे प्रतिबन्ध से और पैसे की किल्लत से वन-धन समितियों की दिवालिया हालत से आदिवासियों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गईं। वनोपजों के दाम बुरी तरह गिए गए।

इसके अलावा, जब वन-धन समितियों के बारे में प्रचार जोरों पर चल रहा था, प्रवीर कृष्ण ने ट्राइफ़ेड के साथ-साथ ऑइलफ़ेड को भी बस्तर लाया। किसानों को तिलहनें बेच सकने का स्वप्न दिखाया। इससे 1999 में बस्तर के किसानों ने 900 हेक्टेयर जमीन में सोयाबीन की फसल बो डाली।

ऑइलफ़ेड ने तिलहनों के अलावा ट्राइफ़ेड के साथ इमली भी खरीदी। चिरौंजी, आमचूर, महुआ, टोरा, मकई, रामतिल, कुर्थी, सूरजमुखी आदि भी खरीदे। सब बाजार में खप गए लेकिन इमली, आमचूर और चिरौंजी के न बिकने से ऑइलफ़ेड को भी ट्राइफ़ेड की तरह एक करोड़ का घाटा सहना पड़ा। ये दोनों संस्थाएं खुद तो डूब गईं, साथ-साथ किसानों को भी ले डूब गईं। पिछले कुछ सालों से विश्व बाजार को झकझोर रही आर्थिक मंदी दण्डकारण्य के शोषित आदिवासियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। दिनोंदिन गिरती जनता की क्रयशक्ति के चलते बाजार में वस्तुओं के ढेर लगते जा रहे हैं। इससे उपज रही मंदी खेतिहर मजदूरों, गरीब और मध्यम किसानों का जीना दूभर बना रही है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त तेज संकट के चलते देश के कई हिस्सों में किसान अपनी फसलों को वाजिब दाम न मिलने के कारण आत्महत्या की शरण ले रहे हैं। पिछले वर्ष बस्तर के पखांजूर इलाके में भी इस तरह की घटनाओं की खबर मिली थी। वनोपजों के दामों में हो रही गिरावट से बाजार से जुड़ चुका आदिवासियों का जीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। जहां एक ओर सरकार खुद यह कहती है कि हमारा देश कृषि-प्रधान देश है और यहां की आबादी का 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर खुलकर जन विरोधी नीतियां अपना रही है। इससे उसका जन विरोधी चेहरा साफ पहचाना जा सकता है। बस्तर के क्रांतिकारी किसान शुरू से ही सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं। किसान लगातार अपनी कृषि-उपजों और वनोपजों के वाजिब दाम की मांग कर रहे हैं। और यह भी मांग कर रहे हैं कि यदि बाजार में सही दाम न हो तो सरकार खुद खरीदे। इस मांग को लेकर कई बार किसानों ने आन्दोलन किया।

बाजार में वनोपजों के गिरते भाव

(रुपयों में)

वनोपज नाम	2000 *(प्रति 100 किलो)*	2001 *(प्रति 100 किलो)*
साल	431 *(1998 में 568)*	371
लाख	5,000	4000
चिरौंजी	30,000	60,000
गोंद	4,000	2,000
महुआ	300	200
टोरा	600	200
आमचूर	3,500	1,300
इमली *(बीज सहित)*	700 *(1999 में 1,200)*	250
इमली *(बीज रहित)*	1,800	500
फूलझाड़ू	1,400 *(1998)*	500

वन-धन समितियों के खिलाफ जनता द्वारा किए संघर्षों की पराकाष्ठा थी बहीगांव का किसान-प्रदर्शन। बस्तर के किसानों ने शुरू से ही वन-धन समितियों का गठन करके वनोपजों की खरीदी को नियंत्रित करने की सरकार की नीतियों का विरोध किया। विपक्षी पार्टियों ने भी वन-धन समिति की नीति का विरोध किया। आखिर सत्ता पक्ष के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी इसका विरोध करते हुए अखबारों में बयान दिए। अखबारों ने साफ तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनावों में विशाल बस्तर में कांग्रेस की करारी शिकस्त के लिए वन-धन समितियां ही जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] और डीएकेएमएस, केएएमएस जैसे क्रांतिकारी जन संगठनों ने विशाल बस्तर में किसानों को गोलबंद करके कई आमसभाओं का आयोजन किया। हजारों आदिवासी किसानों ने इन सभाओं में भाग लिया और वन-धन समितियों के प्रति अपना कड़ा विरोध जाहिर किया। उत्तर बस्तर के डौला में आयोजित सभा में 5,000 किसानों और छोटे व्यापारियों ने भाग लिया। वेडमाकोट में आयोजित आमसभा में 1800 लोगों ने भाग लिया। दक्षिण बस्तर डिवीजन के बीजापुर, गंगलूर, दोरनापाल, चिंतलनार, जेगुरगोंडा आदि हाटबाजारों में किसानों ने लगातार प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया। 29 नवंबर 2000 को उत्तर बस्तर के विश्रामपुरी गांव के किसानों ने कलेक्टर प्रवीर कृष्ण का घेराव करके विरोध प्रकट किया, तो वे आग-बबूला हो गए। मौके पर ही 2 किसानों को गिरफ्तार करके, 50,000 रु. की जमानत देने से ही उन्हें रिहा कर देने की घोषणा लाउडस्पीकर में करके गरीब और कमजोर आदिवासियों पर अपनी जोर-जबर्दस्ती की मिसाल पेश की। वहीं मंच पर बैठी केशकाल की विधायिका फूलो नेताम ने चुप्पी साधकर

कृष्ण की ज्यादतियों का मौन समर्थन किया। इस तरह कई और जगहों पर वन-धन समितियों के खिलाफ लोगों ने स्थानीय तौर पर कई विरोध प्रदर्शन किए। इसी सिलसिले में बहीगांव की घटना घटी।

बहीगांव के किसानों ने क्या चाहा? पुलिस वालों के सिर क्यों फूटे?

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर बहीगांव स्थित है। यहां के आदिवासियों ने स्थानीय वन-धन समिति में इमली बेची। पैसे के अभाव में समिति दो हफ्ते उन्हें सिर्फ रसीदें देकर खाली हाथ वापस भेजा। किसान तीसरे हफ्ते में भी पैसे मिलने की उम्मीद से 300 बैलगाड़ियों में इमली लादकर समिति के पास चले आए। लेकिन समिति ने उन्हें फिर एक बार निराश किया। ऊपर से भाव घटाकर 5 रु. प्रति किलो से 4.50 रु. प्रति किलो कर दिया। किसानों को मंडई (मेला) जाना था जो उसी हफ्ते में लगने वाला था। समिति ने पैसा नहीं दिया तो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने तत्काल ही बकाया भुगतान करने की मांग की। कोंडागांव एसडीएम आनन-फानन 1,30,000 रु. ले आया, पर वह राशि एकदम अपर्याप्त थी। इससे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 घण्टों तक चक्काजाम किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों की मजबूर हालत का पुलिस ने फायदा उठाना चाहा। लाठियों से प्रहार करके कई किसानों की अंधाधुंध पिटाई कर दी। फरसगांव के थानेदार ने हवा में गोलियां दागीं। इससे जनता का आक्रोष भड़क उठा जो सुबह से भूखे-प्यासे इमली की गठरियां लेकर खड़ी थी। लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इससे पुलिस वाले घायल हो दुम दबाकर पीछे हट गए। किसानों ने वन-धन समितियों के खिलाफ पनपा गुस्सा जुल्मी पुलिस वालों पर उतारा जो समिति के समर्थन में हथियारबंद होकर आए थे। इसके बाद लोग घर लौट गए।

11 वर्षों की अथक लड़ाई से सरकार का सिर झुकाकर तेन्दुपत्ता संघर्ष में कामयाबी हासिल करने वाली बस्तर की बहादुर जनता का क्रांतिकारी अभिनन्दन!

किसानों की इस विरोध कार्रवाई से सख्ते में आई पुलिस बड़ी संख्या में आकर गांवों पर टूट पड़ी। 36 लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया। हत्या के मामले सहित कई आपराधिक मामले उन पर दर्ज करने के परिणामस्वरूप अदालत ने उनकी जमानत की अपील को नामंजूर कर दिया। भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 147, 148, 149, 307, 332, 353, 427, 452 और 506 के तहत उन पर मामले दर्ज किए गए। इन धाराओं के तहत इन किसानों को मौत की सजा भी दी जा सकती है। जो किसान गिरफ्तारी से बच गए उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है। बहीगांव के किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज का समूची जनता ने विरोध किया। नव गठित छत्तीसगढ़ के `आदिवासी' मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने प्रदेश के किसी भी कोने में विरोध का स्वर सुनाई देने से पुलिस को भेजकर लाठियों और गोलियों की भाषा ही बोल रहे हैं। हम इस गैर-जनवादी दमनात्मक कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। बेकसूर आदिवासी किसानों पर की गई अमानवीय लाठी चार्ज का बदला जरूर लिया जाएगा। हम मांग करते हैं कि बहीगांव के किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए और उन पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस लिए जाएं; लाठीचार्ज और गोलीबारी के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को सजा दी जाए; किसानों का बकाया भुगतान किया जाए।

इस तरह, हर तरफ जनता के विरोध बावजूद किसी तरह पिछले तीन सालों से लंगड़ाती आ रही वन-धन समितियों के एकाधिकार को आखिर सरकार ने मजबूर होकर समाप्त किया। धन के अभाव के चलते ट्राइफ़ेड ने खरीदी बंद कर दी। आदिवासियों के विकास के नाम पर बनाई इस संस्था के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया क्या है, इससे साफ जाहिर हो जाता है। हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि ये वन-धन समितियां लंबे समय तक वनोपजों की खरीदी नहीं कर सकती और सरकार बस्तर के वनोपज व्यापार को इसलिए नियंत्रण में ले रही है ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस पर कब्जा सौंप दिया जा सके। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। सालाना 1,000 करोड़ रुपए के टर्नोवर वाले वनोपज व्यापार से ट्राइफ़ेड ने अपना हाथ खींच लिया। अब निजी व्यापार के प्रवेश के लिए हरी झण्डी दिखाई गई है।

ऐसी स्थिति में क्या बस्तर की भूमि पर 1,000 करोड़ रुपए के कारोबार के लिए आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इजाजत दी जाए? या एकजुटता से उन्हें मार भगा दिया जाए? आज यह प्रश्न सिर्फ बस्तर की जनता का नहीं, तमाम दण्डकारण्यवासियों, देश की तमाम जनता और जनतंत्र के प्रेमियों का प्रश्न भी है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह निजी व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाते हुए, वन-धन समितियों का एकाधिकार कायम करने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए, पिछले तीन सालों से लड़ाई जारी रखकर बस्तर के उत्पीड़ित आदिवासियों, छोटे व मध्यम व्यापारियों और जनतंत्र के प्रेमियों ने जीत हासिल की, उसी तरह आगे भी लड़ाई जारी रखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बस्तर की भूमि पर कदम रखने नहीं देंगे। तेन्दुपत्ता राष्ट्रीयकरण नीति के खिलाफ पिछले एक दशक से ज्यादा अरसे से जनता ने जो बहादुराना लड़ाई लड़ी, उसे भी इस वर्ष (2001) कामयाबी मिली। वन-धन समितियों के एकाधिकार की समाप्ति से यह बात फिर एक बार साबित हो चुकी है कि हालांकि क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकारें इस तरह के ढोंगी सुधार लाने पर मजबूर हो जाती हैं, फिर भी वे ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। सरकार के ढोंगी सुधारों को आमतौर पर जागरूक क्रांतिकारी जनता के संघर्षों से ही विफल किया जा सकता है। सरकारों के आर्थिक संकटों के परिणामस्वरूप भी ऐसे सुधार खुद ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। वन-धन समितियों का एकाधिकार विरोधी संघर्षों और तेन्दुपत्ता राष्ट्रीयकरण विरोधी संघर्षों ने यही साबित किया कि जनता की ताकत अपराजेय है। हम संघर्षरत जनता के पक्ष ही रहेंगे - जनता ही इतिहास का निर्माता है। ✪